राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 108

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, बुधवार, 25 सितंबर, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ट्रेनों में तोड़फोड़ और पलटाने की साजिश होगी नाकाम

>> 7

विश्वास.News

हुड्डा व कुमारी सैलजा की पुरानी तस्वीर प्रसारित ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज-4

आनलाइन गेमिंग की नई सुबह पर सट्टेबाजी का साया

विशेष सीरीज (किस्त-2)

पढ़ें पेज नं. 6

जागरण विशेष

भागलपुर में जूट से नवाचार, खोजा विदेश में बाजार

भागलपुर : भागलपुर के जूट का नवाचार देश-दुनिया में दम दिखा रहा है। भारत के साथ ही विदेश में भी बेबी कैरियर के लिए जूट की खासी मांग है। अमेरिका, इंग्लैंड, फिलिपींस, जर्मनी और पोलैंड आदि देशों को निर्यात के माध्यम से वर्तमान में यह भागलपुर के अर्थतंत्र का सारथी बन गया है। ● पेज-7

संपादकीय

सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों मंदिर : तिरुपति प्रसाद प्रकरण दर्शाता है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए। **विकास सारस्वत** का दृष्टिकोण।

नई विभाजक रेखाएं खींचने की कोशिश : बेलगाम हो रही जाति, पंथ और भाषा के सहारे की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति। **राजीव सचान** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

उपकरणों के हथियार में बदल जाने का संकट : हाल में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वाकीटाकी और रेडियो सेट विस्फोट के साथ अचानक फटे, तो दुनिया इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गई। अभिषेक कुमार सिंह का विश्लेषण।

चिंतित करता विपैला होता भूजल : दिल्ली में भूजल और गहराई में जाने के साथ इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। पंकज चतुर्वेदी का आलेख। ● पेज-9

भूमि घोटाले में जांच के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक के सीएम की याचिका खारिज

बेंगलुरु, प्रेट्र : भूमि घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने जोर का झटका दिया। कोर्ट ने सिद्दरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) द्वारा उनकी पत्नी को 14 भूखंडों के आवंटन में गड़बड़ी के संबंध में उनके खिलाफ राज्यपाल गहलोत द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को चुनौती दी थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा,'याचिका में बताए गए तथ्यों की निस्संदेह जांच की आवश्यकता है। इन सभी चीजों का लाभार्थी याचिकाकर्ता का परिवार है। अतः याचिका खारिज की जाती है।' कोर्ट ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है लेकिन राज्यपाल असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं और वर्तमान मामला ऐसा ही अपवाद है।

- कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुडा प्लाट आवंटन घोटाले में राज्यपाल की ओर से दिए गए जांच के आदेश को बरकरार रखा
- कोर्ट ने कहा- राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है पर वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं

बेंगलुरु में मंगलवार को हाई कोर्ट के लिए प्रस्थान करते मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे सीएम सिद्दरमैया। प्रेट्र

केंद्र सरकार बदले की भावना से राजनीति कर रही है। मैं कानून और संविधान में विश्वास रखता हूं। अंत में सच की जीत होगी। मैं कानूनी विशेषज्ञों और पार्टी नेताओं से विचार विमर्श के बाद अगली कानूनी कार्रवाई करूंगा।

- सिद्दरमैया

ये था मामला : आरोप है कि सिद्दरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसुरु के पाश इलाके में मुआवजे के रूप में जो भूखंड आवंटित किए गए थे, उनकी कीमत मुडा द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन की तुलना में काफी अधिक थी। मुडा ने पार्वती की 3 .16 एकड़ जमीन के बदले उन्हें 50 :50 के अनुपात से भूखंड दिए थे। आरोप है कि कसाबा होबली के कसारे गांव में स्थित उस 3 .16 एकड़ जमीन पर भी पार्वती का कोई कानूनी हक नहीं था, जिसके एवज में प्लाट आवंटित हुए।

राज्यपाल ने 16 अगस्त 2024 को सीएम के खिलाफ जांच को मंजूरी दी थी पेज>>5

इस्तीफा दें सिद्दरमैया, जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच होने दें : भाजपा पेज>>5

मेडिकल दाखिले में एनआरआइ कोटे की धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पंजाब में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के एनआरआइ कोटे का दायरा बढ़ाने के तय मानकों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाते हुए इसे धोखाधड़ी करार दिया। कोर्ट ने एनआरआइ कोटे का लाभ लेने के लिए तय शर्तों को देखकर कहा, यह पूरी तरह फ्राड (धोखाधड़ी) है, अब यह बंद होना चाहिए। इससे बैक डोर एंट्री को रास्ता मिलता है। इसने देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता कमजोर की है। यह और कुछ नहीं, पैसा बनाने का जरिया है। इन तीखी टिप्पणियों के साथ शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश सही ठहराते हुए पंजाब सरकार व अन्य की चुनौती याचिकाएं खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को एनआरआइ कोटे का दायरा बढ़ाने की पंजाब सरकार की अधिसूचना रद कर दी थी।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया है। पंजाब सरकार ने 20 अगस्त को अधिसूचना जारी कर मेडिकल में प्रवेश के लिए 15 प्रतिशत एनआरआइ कोटे की परिभाषा का विस्तार कर दिया था। उसमें एनआरआइ के रिश्तेदार, जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी, चचेरे भाई आदि को भी शामिल कर दिया था।

- पंजाब में मेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश में एनआरआइ कोटे का दायरा बढ़ाने पर की तीखी टिप्पणी
- अधिसूचना रद करने का हाई कोर्ट का आदेश ठहराया सही, पंजाब सरकार की याचिका खारिज

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एनआरआइ की विस्तारित परिभाषा देखकर कहा, यह क्या है। इसमें नजदीकी रिश्तेदारों पर भी विचार करने की बात है, यह तो बहुत अस्पष्ट चीज है। यह तो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है। हमें अब इस एनआरआइ कोटा बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। यह पूरी तरह धोखाड़ी है।

हाई कोर्ट में सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, यह और कुछ नहीं, पैसे के बल पर मेडिकल में प्रवेश पाने का जरिया है। पंजाब में तो सभी के एनआरआइ रिश्तेदार हैं। उनके मुवक्किल के 636 अंक आए हैं पर उसे एडमिशन नहीं मिला, जबकि इस कोटे में 250 अंक पाने वाले को एडमिशन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके नुकसानदेह परिणाम देखिए जिस छात्र के तीन गुना ज्यादा अंक आए हैं, वह प्रवेश नहीं पाएगा और विदेश में बसे मामा, ताई, ताया के दूर के रिश्तेदारों को मेधावी छात्रों से पहले प्रवेश मिल जाएगा। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।

तीन माह में तीसरी बार मिले मोदी व जेलेंस्की

पीएम ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत का समर्थन दोहराया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को अप्रभावित किए बिना भारत यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस क्रम में सोमवार को अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन-रूस विवाद के हालात पर चर्चा की। यह गत तीन माह में जेलेंस्की और मोदी की तीसरी भेंट थी जो बताती है कि भारत विवाद के समाधान की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि, यूक्रेन की तरफ से भारत में अगला शांति सम्मेलन कराने के प्रस्ताव पर नई दिल्ली का रुख बहुत उत्साहजनक नहीं है। वजह यह है कि भारत तभी कोई शांति समझौता अपने यहां कराने को लेकर उत्सुक होगा जब दोनों पक्षों के प्रतिनिधि हिस्सा लें। यूक्रेन विवाद पर पिछले दिनों स्विटजरलैंड में जो शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें रूस ने हिस्सा नहीं लिया था।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने दोनों नेताओं की मुलाकात के बारे में बताया, 'पीएम मोदी यूक्रेन की स्थिति को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। बैठक का आग्रह यूक्रेन की तरफ से ही आया था। यूक्रेन विवाद पर हमारा पुराना रुख है कि इसका समाधान वार्ता और कूटनीति से ही होना चाहिए। पीएम न सिर्फ यूक्रेन-रूस के बीच युद्ध में लोगों के मारे जाने से चिंतित हैं, बल्कि इस विवाद का दूसरे देशों, खास तौर पर विकासशील व गरीब देशों पर जो असर हो रहा है, उससे भी चिंतित है।' विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया, 'पीएम मोदी ने कहा, मौजूदा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो भी संभव कदम होगा भारत वह उठाने को तैयार हैं। इस बारे में जिस भी तरह की मदद चाहिए, वह उपलब्ध कराने को तैयार है।' राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मोदी के दौरे को याद करते हुए, उसके लिए उनका धन्यवाद किया।

मोदी ने जेलेंस्की से गत माह मुलाकात की थी। इससे कुछ हफ्तों पहले जुलाई में मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। मोदी एकमात्र वैश्विक नेता हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के शीर्ष नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात जून, 2024 में जी-7 शिखर बैठक के दौरान भी हुई थी।

- शांति सम्मेलन भारत में कराने के यूक्रेन सरकार के प्रस्ताव पर रुख सकारात्मक नहीं
- भारत का मत, जब विवाद से जुड़े दोनों ही पक्ष मौजूद हों, तभी इसका कोई मतलब
- स्विटजरलैंड में हुए शांति सम्मेलन में रूस ने हिस्सा नहीं लिया था

न्यूयार्क में एक द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

पश्चिम एशिया में युद्धविराम का आह्वान

विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और वार्ता व कूटनीति के मार्ग पर लौटने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि द्वि-राष्ट्र समाधान ही क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता ला सकता है।

अमेरिका यात्रा का वीडियो किया साझा

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक्स पर अपनी अमेरिका यात्रा के प्रमुख अंशों का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा फलदायी रही है, इसमें विविध कार्यक्रमों को शामिल किया गया और धरती को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

'ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी' के सदस्यों से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयार्क में ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी के अमेरिका चैप्टर के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वे भारत में हो रहे व्यापक बदलावों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रसारित करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से पराली जलने पर जवाब तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पंजाब में जलाई जा रही पराली का धुंआ आबोहवा खराब करने भले ही अभी दिल्ली न पहुंचा हो, पर पराली जलने का मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से पराली जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर जवाब मांगा। पूछा कि लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा।

वायु प्रदूषण के मामले में कोर्ट की मददगार न्यायमित्र वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने मंगलवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ के समक्ष पराली जलने का मामला उठाया। अपराजिता ने कहा,पराली जलना शुरू हो गया है। सीएक्यूएमवायु से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कार्रवाई की गई है। उनकी दलीलों पर पीठ ने केंद्र सरकार व सीएक्यूएम की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, कोर्ट इस पर शुक्रवार तक जवाब चाहता है। भाटी ने कहा, जानकारी दी जाएगी।

- पराली जलने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर मांगा जवाब
- पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर

प्रतीकात्मक

ज्ञात हो, हर वर्ष दिल्ली में सर्दियां आते ही वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। इसमें पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, व उत्तर प्रदेश में पराली (फसल के अवशेष) जलने से भी वृद्धि होती है। पिछले वर्ष ही कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक के आदेश दिए थे और दिल्ली व इससे सटे राज्यों से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कदम उठाने और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इस संबंध में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह के उपाय करने को कहा था।

सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

काम का दबाव न बन जाए जोखिम

हृदयरोग से क्या एगी अच्छी जीवनशैली

● पेज-13

85 हजार अंक के पार जाकर लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई : स्पष्ट संकेतों के अभाव में घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को दिनभर उतार-चढ़ाव का माहौल रहा। गिरावट के साथ दिन की शुरुआत करने वाला बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के दौरान 234 .62 बढ़कर पहली बार 85 हजार के पार पहुंचा। अंत में 84,914 .04 अंक पर बंद हुआ। (पेज-10)

बांग्लादेश के विदेश मंत्री से हुई जयशंकर की भेंट

नई दिल्ली : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे तौहीद हौसेन से विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पहली मुलाकात हुई है। न्यूयार्क में हुई भेंट के बारे में आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि दोनों ने द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की। (पेज-3)

अगैती फसलों पर आफत बरसाकर वापस जा रहा मानसून

नई दिल्ली : देश के पश्चिमी हिस्से से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। सामान्य से छह प्रतिशत ज्यादा बारिश के साथ देर से लौटते मानसून के चलते बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उप्र में पछैती फसलों को फायदा होगा, किंतु उत्तर भारत के बड़े हिस्से में तैयार अगैती फसलों को क्षति होने लगी है। (पेज-6)

उप्र में बदलेगा कानून, होटल-रेस्तरां वालों को बतानी होगी पहचान

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

खान-पान की वस्तुओं में लगातार मिलावट की घटनाओं पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खान-पान की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन किया जाए। दाल-रोटी व जूस जैसे खाद्य-पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाने को वीभत्स बताते हुए योगी ने कहा, होटलों, ढाबों व रेस्तरां आदि की गहन जांच की जाए। ढाबों-रेस्त्रां पर उनके संचालक, मालिक, मैनेजर आदि के नाम-पते प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाए। अपशिष्ट आदि मिलाने पर संचालक पर कार्रवाई हो। होटलों/ढाबों, रेस्तरां में ग्राहकों के बैठने से लेकर किचन और अन्य सभी क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से कवर किए जाएं। सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराया जाए। शेफ-वेटर के लिए मास्क व ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया जाए।

मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कहा, जूस, दाल-रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट/अखाद्य/गंदी चीजों की मिलावट की वीभत्स घटनाएं देखने-सुनने को मिल रही हैं। ऐसी घटनाएं आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने व अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किया जाना जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस, स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें कार्रवाई करें। सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी कैमरे के रिकार्ड को सुरक्षित रखेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा।

इसलिए योगी ने दिखाया कड़ा रुख पेज>>7

- सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन के दिए निर्देश
- कहा-खाद्य-पेय पदार्थों में मानव अपशिष्ट मिलाना नहीं करेंगे स्वीकार
- खान-पान के प्रतिष्ठानों की हो जांच, सभी कर्मचारियों का हो पुलिस सत्यापन

मुख्यमंत्री ने यह भी दिए निर्देश

- खान-पान वस्तुओं की शुद्धता-पवित्रता सुनिश्चित हो
- शेफ और वेटर के लिए मास्क-ग्लव्स पहनना हो अनिवार्य
- होटल-रेस्त्रां में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, यह सुनिश्चित किया जाए

इजरायल के हमले में मारा गया हिजबुल्ला का एक और कमांडर

बेरूत : इजरायल का लगातार दूसरे दिन भी लेबनान में हमला जारी रहा। राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला का वरिष्ठ कमांडर और मिसाइल व राकेट इकाई का प्रमुख मारा गया। इजरायल ने अब तक हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें 558 लोग मारे गए है। (पेज-11)

दिल्ली में पढ़ी हरिनी बनीं श्रीलंका की प्रधानमंत्री

कोलंबो : दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली हरिनी अमरसूर्या ने मंगलवार को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एस. भंडारनायके के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली पहली और इस पद तक पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता हैं। (पेज-11)

अभूतपूर्व

अमेरिका ने भारत के बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को अपना प्रमुख रक्षा साझेदार बनाया, तीनों देशों के बीच अभूतपूर्व सैन्य सहयोग की होगी शुरुआत

भारत, अमेरिका और यूएई की बनेगी सैन्य तिकड़ी

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

नई दिल्ली : आने वाले दिनों में भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच अभूतपूर्व सैन्य सहयोग की शुरुआत होने वाली है। इसके तहत तीनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, युद्धाभ्यास और सैन्य क्षेत्र से जुड़े सहयोग स्थापित किये जाएंगे। इसकी घोषणा अमेरिका व यूएई के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद जारी संयुक्त रणनीतिक बयान में की गई है।

इस बयान में भारत एकमात्र देश है, जिसका जिक्र पांच बार किया गया है। संयुक्त बयान में अमेरिका व यूएई ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत के साथ सैन्य सहयोग को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे ज्यादा प्रगाढ़ करने की बात कही है। उक्त दोनों देशों ने भारत से मध्य पूर्व क्षेत्र से होते हुए यूरोप तक की कनेक्टिविटी परियोजना को भी पूरा समर्थन देने की बात कही गई है। अमेरिका ने अभी तक सिर्फ भारत को प्रमुख रक्षा साझेदार का दर्जा दिया था। अब यूएई को भी यह दर्जा दे दिया गया है। अमेरिका और यूएई के बीच खाड़ी के क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य व रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में बताया गया है कि इनके बीच की साझेदारी अब भारत के साथ भी अभूतपूर्व सैन्य सहयोग की राह खोलेगा।

कई अंतरराष्ट्रीय जानकारों ने अमेरिका और यूएई की तरफ से की गई इस घोषणा को वैश्विक फलक पर दूरगामी असर वाला करार दिया है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पर अमेरिका के घटते असर को बैलेंस करने के लिए अब अमेरिका यूएई के साथ सैन्य सहयोग को प्रगाढ कर रहा है।

पिछले वर्ष ईरान और सऊदी अरब के बीच एक समझौता हुआ था। इसके पीछे चीन का हाथ होने की बात कही गई थी। इसे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के घटते प्रभाव के तौर पर भी देखा गया था।

आइ2यू2 के साथ हुई थी तीनों देशों के बीच सहयोग की शुरुआत

वैसे भारत, यूएई और अमेरिका के बीच एक सहयोग की शुरुआत जुलाई, 2022 में तब हुई थी, जब क्वाड की तर्ज पर ही आइ2यू2 (भारत, इजरायल, यूएई व अमेरिका) संगठन की शुरुआत की घोषणा की गई थी। इसके शीर्ष नेताओं की वर्चुअल बैठक भी हुई थी, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर काम करने का एलान किया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में इस संगठन पर खास ध्यान नहीं दिया है। लेकिन, अब यूएई व भारत को प्रमुख सैन्य साझेदार बनाकर और इनके साथ सैन्य सहयोग का एलान कर अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में एक तरह से अपनी नई रणनीति को भी सार्वजनिक किया है।

नोएडा में करोड़ों के भूखंड बचाने के लिए आठ दंपती ने लिया तलाक

जागरण संवाददाता, नोएडा

यमुना प्राधिकरण से आवंटित करोड़ों रुपये का भूखंड बचाने के लिए आठ दंपती ने सहमति से तलाक ले लिया है। सभी भूखंड चार हजार वर्गमीटर तक के हैं। यमुना प्राधिकरण ने कोरोना काल के दौरान 2020-21 में एमएसएमई में औद्योगिक श्रेणी के इन भूखंडों का आवंटन किया था। प्राधिकरण के नियमों के अनुसार दंपती में से किसी एक को ही भूखंड आवंटित किया जा सकता है।

कोरोनाकाल के दौरान औद्योगिक भूखंड योजना में 47 प्रकरणों में एक ही परिवार के लोगों को एक से अधिक भूखंडों का आवंटन हो गया था। प्राधिकरण ने भूखंडों की रजिस्ट्री कराने के लिए जांच की तो आवंटियों के दस्तावेज से फर्जीवाड़ा पकड़ में आया।

- नियमानुसार दंपती में से एक को ही आवंटित हो सकता है भूखंड

47 प्रकरणों में एक परिवार को एक से अधिक भूखंड आवंटित

कई ऐसे मामले भी हैं कि जिस कंपनी को भूखंड आवंटित हुआ, उसमें पति-पत्नी दोनों शामिल हैं। प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह को इन आवंटन की जांच सौंपी गई है। प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि जांच में ऐसे 32 आवंटन सामने आए हैं। इनका आवंटन 10 परिवार के सदस्यों के नाम हुआ है। 16 आवंटनों में एक ही परिवार के सदस्य दोनों फर्म, दोनों कंपनी या एक फर्म एक कंपनी के पदाधिकारी हैं। एक आवंटी ने भूखंड सरेंडर कर दिया है।

इस तरह किया गुमराह पेज>>7

1595 प्रवेश स्नातक में डीयू में स्पाट राउंड में हुए। स्पाट राउंड के लिए 24175 छात्रों ने आवेदन किया था। इस राउंड में छात्रों के पास सीट अपग्रेड करने या कोर्स बदलने का विकल्प नहीं था। प्रवेश के लिए उन्हें सीट फ्रीज करना जरूरी था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 25 सितंबर, 2024

आज का मौसम

बुधवार को सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
25 सितंबर	36.0	26.0
26 सितंबर	34.0	26.0
नोएडा		
25 सितंबर	32.0	26.0
26 सितंबर	30.0	25.0
गुरुग्राम		
25 सितंबर	36.0	26.0
26 सितंबर	33.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जल्द होगी लागू

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि सभी लंबित प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी देंगे। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी जल्द ही आगे बढ़ाई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपये देने के हमारे वादे से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। (राबू)

डीयू एसओएल स्नातक में 30 तक प्रवेश का मौका

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। एसओएल के बीए और बीकाम प्रोग्राम में नियमित कालेजों की तरह होड़ देखी जा रही है। इन्हीं में सर्वाधिक प्रवेश हुए हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और अब तक स्नातक कार्यक्रमों के लिए 96089 प्रवेश पूरे हो चुके हैं। इस साल 129582 छात्रों ने पंजीकरण कराया और यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। (जासं)

मुख्य न्यायाधीश बने हाई कोर्ट के दो जजों को दी गई विदाई

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर व न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को राजीव शकधर की हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और सुरेश कुमार कैत की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। (जासं)

एम्स में इलाज कराने के लिए एक दिन पहले से लग रही लाइन

रणविजय सिंह ● जागरण

नई दिल्ली: एम्स में यदि इलाज कराना है तो जल्दबाजी में न रहें, बल्कि धैर्य के साथ जाएं। साथ ही अपने साथ बिस्तर का इंतजाम भी रखें। क्योंकि ओपीडी पंजीकरण के लिए 20-22 घंटे पहले पहुंचकर सड़क पर समय बिताना पड़ सकता है। यह कोई कल्पना नहीं है। यदि बीमार चिकित्सा व्यवस्था का दृश्य देखना है तो एम्स चले जाएं। जहां अस्पताल की ओपीडी खत्म नहीं होती कि अगले दिन की ओपीडी के लिए इन दिनों रिंग रोड के सर्विस लेन में मरीजों की लाइन लग जाती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम मरीज कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके इलाज कराने को मजबूर हो रहे हैं।

यह हाल तब है, जब देश में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए नए-नए एम्स बनाए जा रहे हैं। फिर भी दिल्ली एम्स में भीड़ कम नहीं हो रही है। प्रतिदिन करीब 13,500 मरीजों का ओपीडी पंजीकरण होता है। एम्स की ओपीडी में इलाज के लिए पहले मरीज रात में पहुंचकर अस्पताल के परिसर में लाइन लगाते थे। अब सुबह करीब 11 बजे से ही एम्स के गेट नंबर छह के पास रिंग रोड के सर्विस लेन में बगैर अप्वाइंटमेंट वाले मरीज या उनके स्वजन लाइन में लगने लगते हैं। देर रात यह लाइन एम्स के गेट नंबर दो तक (करीब आधा किलोमीटर) पहुंच जाती है। कई बार मरीज लाइन में आगे लगने के लिए झगड़ पड़ते हैं। दिन और रात में 20-22 घंटे के इंतजार के बाद भी ओपीडी पंजीकरण हो पाएगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं होती। इसका कारण यह है कि एम्स में सभी विभागों ने ओपीडी में इलाज के लिए प्रतिदिन के स्लाट निर्धारित कर दिए हैं।

एम्स में ओपीडी पंजीकरण के लिए रिंग रोड की सर्विस लेन में बैठकर इंतजार करते मरीज और उनके स्वजन। जागरण

झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले सत्यम नामक युवक सर्विस लेन में लाइन में बैठकर पढ़ाई करते दिखे। उन्होंने बताया कि वह ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर ही यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मां की तबीयत खराब है। पहले गायनी विभाग में दिखाया था। इसके बाद मेडिसिन में और वहां से मनोचिकित्सा विभाग में स्थानांतरित किया गया। हर विभाग के लिए अलग-अलग ओपीडी पंजीकरण कराना पड़ता है। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे आकर लाइन में लगे। सुबह में ओपीडी पंजीकरण के लिए 35-40 मरीजों को टोकन मिला। पूरी रात जगने के बाद भी जब उनकी बारी आई तो पंजीकरण बंद हो गया। आनलाइन भी अप्वाइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है।

नोएडा की संगीता तिवारी ने बताया कि उन्हें गायनी से संबंधित बीमारी है। फालोअप के लिए वह दो दिन लगातार सुबह साढ़े पांच बजे पहुंचीं। दोनों दिन ओपीडी पंजीकरण नहीं हो पाया। पता चला कि तत्काल में ओपीडी पंजीकरण के लिए एक दिन पहले से लाइन लगती है। सुबह में गार्ड लाइन से मरीजों को अस्पताल में अंदर भेजते हैं। आगरा से बेटी के इलाज के लिए पहुंचीं कमला नामक महिला ने बताया कि बेटी के पेट में तिल्ली बढ़ गई है। जब भी आती हैं यही दिक्कत होती है। बिहार के बेतिया से पहुंचे नवेद आलम नामक नवयुवक ने बताया कि छोटे भाई के मुंह से ब्लड आता है। बिहार से डाक्टर ने एम्स में रेफर किया है। मंगलवार को ओपीडी कार्ड नहीं बन पाया। इसके बाद लाइन में लगे हैं। इस मामले पर एम्स के मीडिया डिविजन से पक्ष मांगा गया लेकिन एम्स को कोई जवाब नहीं मिला।

एम्स में जल्द शुरू होगा रोबोटिक सर्जरी से किडनी प्रत्यारोपण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: एम्स के सर्जिकल ब्लाक, कैंसर सेंटर सहित कई अन्य विभागों के आपरेशन थियेटर (ओटी) में रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी है। सर्जिकल ब्लाक में अगले माह अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन लग भी जाएगी, तब एम्स में रोबोटिक सर्जरी के जरिये किडनी प्रत्यारोपण होने लगेगा। मंगलवार को रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में एम्स के जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डा. वी के बंसल ने यह जानकारी दी। एम्स में अभी दो रोबोटिक मशीन हैं। इसमें एक मशीन मुख्य अस्पताल व दूसरी आर्थोपेडिक विभाग की ओटी में लगी है। सर्जिकल ब्लाक में अभी रोबोटिक मशीन नहीं है। इस कारण जनरल सर्जरी विभाग के मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। डा. बंसल ने बताया कि रोबोटिक मशीन से जटिल सर्जरी भी बगैर बड़े चीरा लगाए छोटे-छोटे छेद कर की जाती है। इससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं।

सीएम आतिशी ने कैबिनेट मंत्रियों और विभागाध्यक्षों के साथ की पहली बैठक, कहा-

सभी अपनी जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएं

दिल्ली सरकार और अफसर मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जरूरतमंद तक सुविधाएं पहुंचें

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद आतिशी ने मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों व दिल्ली सरकार के सभी विभागाध्यक्षों साथ सरकार के कामकाज को लेकर बैठक की। इस दौरान वह तेवर में दिखीं और अपने चार माह के एजेंडे के बारे में सभी को साफ-साफ बता दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के काम उनकी प्राथमिकता हैं और इसमें किसी तरह की कोताही वह बर्दाश्त नहीं करेंगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन व मुकेश अहलावत के साथ-साथ मुख्य सचिव धर्मेंद्र सहित सरकार के सभी विभागों के प्रमुख मौजूद थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली में तैनात अफसरों की पूरी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के प्रति है। दिल्ली के लोगों द्वारा दिए टैक्स से ही हम सभी के घर चलते हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम करें और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक भी सरकारी सुविधाएं पहुंचें और सरकार उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे। दिल्ली सरकार और अफसर मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में हर जरूरतमंद तक सरकारी सुविधाएं पहुंचें और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन मिल सके।

सीएम आतिशी ने अधिकारियों से कहा कि अफसरों के काम से दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में दिल्ली के सभी अफसरों की ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली के लोगों के बेहतरी के लिए काम करें। सरकार के रूप में हम अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे।

दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक करती मुख्यमंत्री आतिशी। सौजन्य : दिल्ली सरकार

'संकट मोचन का आशीर्वाद हमारे साथ'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: एक दिन पहले दिल्ली सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचीं, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि संकट मोचन के आशीर्वाद से हर बाधा से लड़ते हुए हम दिल्लीवालों के लिए काम करते रहेंगे। हनुमान जी हमारे संकट मोचन हैं, उन्होंने पिछले दो साल में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर आए हर संकट को दूर किया है। हनुमान जी केजरीवाल को विजयी बनाकर एक बार फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे।

आतिशी ने कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रेट्र

सप्ताहभर में डेंगू के 300 नए मामले, मलेरिया व चिकनगुनिया केस भी बढ़े

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली में डेंगू के कुल मामले हुए 1,229, इस महीने मलेरिया के 363 मामले सामने आए
- चिकनगुनिया के अब तक 43 मामले सामने आए, दक्षिणी दिल्ली है ज्यादा प्रभावित

राजधानी में तमाम जनजागरूकता के बाद भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सात दिनों में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं इस वर्ष अब तक डेंगू के कुल 1,229 केस सामने आ चुके हैं। पिछले वर्ष की तुलना में अब तक मलेरिया के मामले भी काफी अधिक हैं। दिल्ली में इस महीने तक मलेरिया के 363 केस सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर 2023 में यह आंकड़ा 294 था। पिछले साल मलेरिया के कुल मामले 426 थे। मलेरिया के सबसे अधिक केस पश्चिमी दिल्ली से आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, चिकनगुनिया के अब तक 43 मामले सामने आए हैं। यह पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 23 था। इस साल चिकनगुनिया के सबसे अधिक मामले दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र से आए हैं। इस वर्ष जनवरी से 21 सितंबर तक दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में डेंगू से लोक नायक अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं सितंबर में दिल्ली में डेंगू के 651 व पिछले माह 256 मामले सामने आए थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है। वर्ष 2023 में दिल्ली में सितंबर महीने तक डेंगू के 3,013 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2022 के 525 मामलों से काफी ज्यादा थे।

इस साल सबसे ज्यादा मामले नजफगढ़ जोन से 180 हैं। एक हफ्ते में इस इलाके में सर्वाधिक 45 केस सामने आ चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट और रेलवे जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा शासित गैर-एमसीडी क्षेत्रों में कुल 312 डेंगू के मामले सामने आए। इस आंकड़े में वे मरीज शामिल नहीं हैं, जिन्हें संक्रमण हुआ और वे दिल्ली के निवासी नहीं हैं या फिर जिन्होंने अधूरा या गलत पता दिया।

नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि निगम इस साल मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए अपने बहुआयामी प्रयासों के कारण डेंगू के मामलों की संख्या को कम रखने में सक्षम रहा है। इसमें घर-घर जाकर निरीक्षण, नियमित कीटनाशक का छिड़काव और जनजागरूकता अभियान शामिल हैं। मच्छर नियंत्रण कानूनों को लागू करने के लिए एमसीडी ने 1.14 लाख से अधिक कानूनी नोटिस जारी किए और ऐसे 39,338 लोगों के चालान काटे हैं, जिन्होंने अपनी संपत्तियों पर मच्छरों को पनपने दिया। आंकड़ों के अनुसार, नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों पर 24.82 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और 9,241 लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

गाजियाबाद में मतांतरण कराने पहुंचे पादरी समेत पांच हिरासत में

- मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों से की पूछताछ
- हिंदू संगठन के पदाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज

थाना नंदग्राम में मतांतरण की घटना को लेकर पहुंचे लोग। सौ. सुधी पाठक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

गाजियाबाद में एक परिवार का मतांतरण कराने पहुंचे पादरी समेत पांच को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूचना मिलने पर पादरी के समर्थक थाने पहुंचे तो हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों का समझाकर वापस भेजा। मंगलवार रात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

धर्म जागरण समन्वय संगठन के महानगर संयोजक नवीन सिंह ने बताया कि सोमवार रात उनको बजरंग दल के कार्यकर्ता पंकज ने सूचना दी कि रवि के घर में मतांतरण की प्रक्रिया चल रही है। वह कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि ईसाई समुदाय के कुछ लोग परिवार को बहकाकर धार्मिक अनुष्ठान करा रहे थे। ईसाई धर्म से जुड़ी प्रचार सामग्री भी मिली। पूछताछ में पता चला कि मतांतरण कराने वालों में डासना स्थित चर्च का पादरी जेराल्ड मैथ्यूज मैसी है। उनके साथ अन्य लोग क्षेत्र में मतांतरण कराते हैं। इसका लोगों ने विरोध किया। पुलिस आरोपितों को थाने लेकर आई। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

ईदगाह पार्क में लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, विरोध में दाखिल याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रतिमा स्थापना करने के विरुद्ध शाही ईदगाह प्रबंध समिति की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने समिति की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि ईदगाह की दीवारों के भीतर आने वाली पूरी संपत्ति शाही ईदगाह की संपत्ति थी। अदालत ने इस संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड (डीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर ध्यान दिया। निरीक्षण से यह भी पता चला कि विचाराधीन क्षेत्र डीडीए का है। पूर्व में अदालत ने अपने एक आदेश में डीडीए को पार्क का खसखाव जारी रखने को कहा था, साथ ही प्रस्तावित मूर्ति स्थापित नहीं करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा कि 13 सितंबर 2024 को किए गए निरीक्षण से उपरोक्त स्थिति की पुष्टि की गई है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ईदगाह सीमा के अंदर आसपास का क्षेत्र, पार्क/खुली जमीन डीडीए की है।

सुपरटेक के रुके प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची एनबीसीसी

- सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट को तीन चरणों में पूरा करने का रखा प्रस्ताव
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मेरठ, देहरादून, बेंगलुरु की हैं परियोजनाएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सुपरटेक लिमिटेड के 17 रुके या आंशिक रूप से निर्मित प्रोजेक्ट को विकसित और पूरा करने की मांग की। इन प्रोजेक्टों में वर्षों से करीब 27,000 खरीदार अटके हुए हैं।

ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, देहरादून और बेंगलुरु में शुरू किए गए थे। सुपरटेक के वित्तीय संकट में फंसने से इन आवासीय प्रोजेक्टों के निर्माण पर असर पड़ा। फिर 2021 से दिवालिया की कार्यवाही शुरू हो गई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को फ्लैट खरीदारों की ओर से पेश वकील एमएल लाहोटी ने बताया कि एनबीसीसी करीब 51,000 आवासीय यूनिट वाली रुकी परियोजनाओं को पूरा करने के प्रस्ताव के साथ आगे आया है।

एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने आम्रपाली समूह की तर्ज पर रुकी हुई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सुपरटेक लिमिटेड की दिवालिया कार्यवाही से संबंधित एक मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। पीठ ने मामले को 1 अक्टूबर को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि वह एनबीसीसी के प्रस्ताव पर विचार करेगी। एनबीसीसी ने हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को दिए आवेदन में सुपरटेक की लंबित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तें प्रस्तुत की थीं। एनसीएलएटी ने घर खरीदारों और अन्य हितधारकों से सुपरटेक लिमिटेड की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एनबीसीसी के प्रस्ताव पर आपत्तियां मंगाई थीं।

पहले चरण में ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित इको-विलेज-2, इको-विलेज-3, स्पोर्ट्स विलेज, जार सुइट्स और नोएडा के रोमानो, केपटाउन और इको-सिटी को पूरा करने का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में ग्रेटर नोएडा का इको-विलेज-1, नोएडा का नार्थआई, यमुना एक्सप्रेसवे का अपकंट्री और मेरठ का ग्रीन विलेज व मेरठ स्पोर्ट्स सिटी पूरा होने का प्रस्ताव दिया है। तीसरे चरण में गुरुग्राम के हिलटाउन, अराविले, रुद्रपुर का रिवरक्रेस्ट, देहरादून का दून स्क्वायर और बेंगलुरु का मीकासा शामिल है।

पेड़ कटाई मामले में अधिकारी व ठेकेदारों को मिली पेशी से छूट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के रिज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से संबंधित एक मामले में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रधान सचिव और निजी क्षेत्र के ठेकेदारों को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।

दक्षिणी रिज के सतबारी क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य के विरुद्ध अवमानना मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। निजी ठेकेदारों के वकील अनुपम लाड दास ने कहा कि उन्होंने कारण बताओ नोटिस पर अपने जवाब भी दाखिल किए हैं और बुधवार को उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जा सकती है। मंत्रालय के वकील ने भी ऐसा ही अनुरोध किया, जिसमें प्रधान सचिव के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी गई। प्रधान न्यायाधीश ने इस चरण में याचिका को स्वीकार कर लिया। पीठ बुधवार को मामले की सुनवाई कर सकती है।

बढ़ेगी सुविधा

टर्मिनल के साथ कार्गो व एयरोसिटी को भी आपस में जोड़ेगा आटोमेटेड पैसेंजर मूवर, परियोजना में करीब ढाई ह्जार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान

आइजीआइ के तीनों टर्मिनल को जोड़ेगा एपीएम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइजीआइ एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल आपस में एकीकृत परिवहन प्रणाली से जोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए आटोमेटेड पैसेंजर मूवर (एपीएम) सुविधा विकसित करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट प्रबंधन एजेंसी डायल ने काम करना शुरू कर दिया है। एजेंसी ने टेंडर जारी किया है। अनुमान के अनुसार इस योजना को मूर्त रूप देने में करीब ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यदि सब कुछ सही रहा तो यह परियोजना 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। एलिवेटेड लाइन की लंबाई करीब सात किलोमीटर होगी।

क्यों है जरूरी : आने वाले समय में टर्मिनल तीन को पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। विदेश से यहां उतरने वाले यात्रियों को यदि दिल्ली से देश के किसी भी स्थान के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है तो उसे या तो टर्मिनल-2 या फिर टर्मिनल 1 जाना होगा। अभी टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी है, जिसे तय करने के लिए केवल सड़क मार्ग ही विकल्प है।

मान लीजिए कि आप पटना से नई दिल्ली आ रहे हैं और आपका विमान टर्मिनल-1 पर लैंड करता है तथा एक घंटे बाद मुंबई की कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, जिसके लिए टर्मिनल 3 जाना है। अभी टर्मिनल-1 से टर्मिनल-3 जाने के लिए शटल बस सेवा, टैक्सी या कैब है। टैक्सी वाले मनमाना किराया लेते हैं, जबकि शटल बस सेवा नियत समय से ही चलेगी। शटल बस हर 20 मिनट से आधे घंटे के अंतराल पर ही चलती है। ऐसे में फौरन शटल बस मिलने में परेशानी उठानी पड़ेगी। टर्मिनल 3 व 2 कहने के लिए एक दूसरे के नजदीक हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी तय करने में यात्रियों को काफी दिक्कत होती है।

टर्मिनल 1 से 3 के बीच की दूरी तय करने के लिए बना कारिडोर। जागरण

****

डूसू चुनाव में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर हो कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- हाई कोर्ट ने डूसू प्रत्याशियों के विरुद्ध अयोग्यता नोटिस जारी कर वसूली करने का दिया आदेश
- पूछा- जब संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था तब क्या कर रहा था पुलिस व डीयू प्रशासन

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू), दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) पर गंभीर सवाल उठाया। कोर्ट ने डीयू, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो से पूछा कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की है।

इन टिप्पणी व सवालों के साथ अदालत ने मौखिक टिप्पणी में डीयू प्रशासन को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल उम्मीदवारों को अयोग्यता नोटिस जारी करने और नुकसान की वसूली करने के लिए कहा।

कोर्ट ने यहां तक कहा कि दिल्ली पुलिस को कानून लागू करना है, लेकिन अगर पुलिस और डीयू कुछ नहीं करना चाहता है, तो अदालत क्या कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि जब ऐसा किया जा रहा था तो पुलिस और डीयू प्रशासन क्या कर रहा था?

डूसू चुनाव के चलते डीयू के नार्थ कैंपस में मेट्रो की दीवार व साथ में बने सार्वजनिक शौचालय को भी पोस्टरों से पाट दिया गया है। ध्रुव कुमार

1700 लाख टन कूड़ा वर्तमान में देश के 2304 लैंडफिल साइटों पर इकट्ठा है। इस वजह से करीब 10 हजार हेक्टेयर जमीन घिरी हुई है। इस कचरे को हटाना सरकार के बड़ी चुनौती बना हुआ है।

राजग नेताओं ने सफल अमेरिकी यात्रा के लिए मोदी को दी बधाई

कहा, बढ़ाया भारत का मान, देश में बढ़ेंगे निवेश व रोजगार के अवसर

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, नरेन्द्र मोदी बड़े विश्वनेता के रूप में उभरे हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अमित शाह, नीतीश, नायडू, शिंदे और जीतन राम मांझी ने यात्रा को बताया सफल
- कुमारस्वामी बोले, प्रवासी भारतीयों के साथ पीएम के आत्मीय संबंधों की तस्वीरों को दिल छू लेने

यह दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीति के सिद्धांत को और मजबूत करता है, जिसने गत 10 वर्षों में भारत को सतत विकास के उदाहरणों से वैश्विक परिवर्तनकर्ता की भूमिका में आगे बढ़ाया है। सफल क्वाड शिखर सम्मेलन, भव्य 'मोदी और अमेरिका' जनसभा और संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन दुनिया भर में उनकी बेजोड़ लोकप्रियता को दर्शाता है। मोदी जी के नेतृत्व ने एक राष्ट्र के रूप में भारत के कद को बढ़ाया है, जिसकी हर कोई सुनता है, साथ ही एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भी स्थापित किया है जिसे हर देश मानवता के उत्थान में भागीदार के रूप में स्वीकार करता है। – अमित शाह, गृह मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा को सफल बताते राजग नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के जीतनराम मांझी, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलुगुदेसम पार्टी (टीडीपी) के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के नेता एचडी कुमारास्वामी ने एक्स पोस्ट में अमेरिका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों को भारत में निवेश बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में अहम बताया।

नीतीश कुमार के अनुसार, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ द्विपक्षीय निर्णयों से भारत में अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विकास के नए अवसर मिलेंगे। घोषणाओं और नए अवसरों से बिहार के लोग उत्साहित हैं। वहीं, एकनाथ शिंदे ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने जिन उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनमें से कई से महाराष्ट्र सरकार की बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री के प्रयास से जो निवेश आएगा, उससे निश्चित रूप से महाराष्ट्र को भी लाभ होगा। लगभग 300 प्राचीन कलाकृतियों वापस लाना साबित है कि बड़े नेता हमेशा अपने सांस्कृतिक मूल से जुड़े रहते हैं और प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के साथ काम करने को सौभाग्य बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में दिए उनके भाषण की तारीफ की। प्रधानमंत्री न सिर्फ दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सफल रहे, बल्कि एक बड़े विश्वनेता के रूप में भी उभरे हैं। केंद्रीय इस्पात व भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रवासी भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री के आत्मीय संबंधों की तस्वीरों को दिल छू लेने वाली बताया। एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति दुनिया का प्यार देखकर हर भारतीय गौरवांवित महसूस कर रहा है। पूरी दुनिया मोदी को भारत की आन-बान-शान कह रही है।

न्यूयार्क में सिखों के प्रतिनिधिमंडल से मिले प्रधानमंत्री मोदी

वाशिंगटन, प्रेट्र: पीएम नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका में सिख समुदाय के कई सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान सिखों ने मोदी सरकार द्वारा उनके समुदाय के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

न्यूयार्क में मोदी से मुलाकात के बाद 'सिख आफ अमेरिका आर्गनाइजेशन' के जसदीप सिंह जस्सी ने कहा, 'हम बहुत खुश थे। भेंट के बाद हमें बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ। जैसे ही वह कमरे में आए तो हमने सिखों के पारंपरिक जयकारे जो बोले से निहाल से... उनका अभिवादन किया और पीएम ने भी सत श्री अकाल.. से इसका जवाब दिया।' विस्कांसिन से प्रमुख सिख नेता दर्शन सिंह धालीवाल ने भी मोदी से भेंट की। जस्सी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा, ''मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी अन्य पीएम ने सिखों के लिए वह किया है जो मोदी कर रहे हैं,जिसमें करतार साहिब कारिडोर का उद्घाटन, गुरु नानक की 550वीं जयंती पर जश्न, भारत नहीं आ सकने वाले सिखों की काली सूची को खत्म करना और 1984 में कांग्रेस सरकार में हुए सिख नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाना शामिल है।'' उन्होंने कहा,हम जल्द ही उनसे मिलने व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एक और प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत जा रहे हैं।''

बांग्लादेश के विदेश मंत्री से हुई जयशंकर की भेंट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अंतरिम सरकार बनने के बाद पहली बार हुई भेंट
- द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर हुई बातचीत

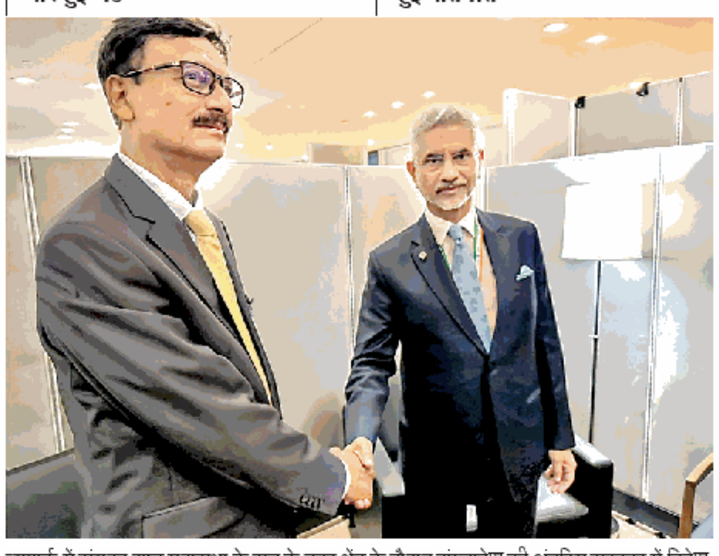

न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर भेंट के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे तौहीद हौसेन के साथ विदेश मंत्री एस.जयशंकर। प्रेट्र

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे तौहीद हौसेन से विदेश मंत्री एस. जयशंकर की पहली मुलाकात हुई है। इसमें हुए विमर्श के बारे में आधिकारिक तौर पर सिर्फ यह बताया गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की। मुलाकात न्यूयार्क में हुई, जहां दोनों देशों के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद भारत व बांग्लादेश के बीच यह सबसे बड़ी उच्चस्तरीय बैठक है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी अमेरिका में हैं और उनकी सरकार की तरफ से पीएम नरेन्द्र मोदी से भेंट का आग्रह भी आया था, पर ऐसा नहीं हो सका। मोदी अमेरिका से भारत पहुंच चुके हैं। 'दैनिक जागरण' ने पूर्व में यह खबर प्रकाशित की थी कि कैसे मोहम्मद यूनुस के कुछ बयानों को लेकर भारत बहुत सहज नहीं है।

जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा, 'बांग्लादेश के विदेश मामलों पर सलाहकार तौहीद होसैन के साथ बैठक हुई। हमारी वार्ता द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित रही।' सनद रहे कि पूर्व पीएम हसीना पांच अगस्त, 2024 से भारत में ही हैं। उनको सत्ता से बेदखल करने के बाद ढाका में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। प्रोफेसर यूनुस और उनकी सरकार के कई दूसरे नेताओं की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हसीना के विरुद्ध बांग्लादेश में लगभग 200 मामले दर्ज कराए गए हैं।

जी-4 के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक

जयशंकर ने जी-4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी बैठक की और मसौदा आधारित वार्ताओं के जरिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया। जी-4 देशों में ब्राजील, जर्मनी, भारत व जापान शामिल हैं। चारों देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। जयशंकर ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से भी भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर बात की।

जस्टिस नरेन्द्र को उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कलेजियम ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस नरेन्द्र जी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है।

उच्चतम न्यायालय के कलेजियम में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई ने कहा, उत्तराखंड हाई कोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं।

जस्टिस नरेन्द्र जी की नियुक्ति 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

वहीं, एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कलेजियम ने बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए नौ अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की है।

दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों को नहीं मिल सकेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ

नीलू रंजन ● जागरण

- दोनों राज्यों ने लागू नहीं की है आयुष्मान भारत योजना

70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस योजना के तहत मिलना है मुफ्त और कैशलेस इलाज

78 अस्पताल दिल्ली और 52 बंगाल में सूचीबद्ध है केंद्र सरकार की इस योजना के तहत

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली : दिल्ली और बंगाल के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा से वंचित रह जाएंगे। इन दोनों राज्यों ने छह साल पहले शुरू की गई इस योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को देने का फैसला लिया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इसे लांच करने की तैयारी में जुटा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना राज्यों और केंद्र दोनों के सहयोग से चलती है, जिसमें आने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करती है और 40 प्रतिशत राशि राज्यों को देनी होती है। पर्वतीय राज्यों के लिए यह अनुपात 90 और 10 प्रतिशत का है। यानी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं राज्यों के नागरिकों को मिल सकता है, जो इसमें हिस्सेदारी के लिए सहमत हों। उन्होंने कहा कि अभी तक 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। केवल बंगाल, दिल्ली और ओडिशा ने इसे लागू नहीं किया है। ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार योजना को लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन दिल्ली और बंगाल ने अभी तक इस योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

बड़ी बात यह है कि बंगाल और दिल्ली के बुजुर्गों को भले ही आयुष्मान योजना का लाभ न मिले, लेकिन इन दोनों राज्यों में इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में अन्य राज्यों के बुजुर्गों को मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है।

दिल्ली में 78 और बंगाल में 52 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। इन अस्पतालों में पहले से ही दूसरे राज्यों के आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को इलाज का लाभ मिल रहा है। जाहिर है अन्य राज्यों के बुजुर्ग भी इन अस्पतालों में इलाज के हकदार होंगे।

भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी दर कम होने का अनुमान : एसबीआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इस साल ही जनगणना शुरू होने की उम्मीद
- बच्चों की आबादी घट रही, बुजुर्गों की बढ़ रही

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) का अनुमान है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है। मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में एसबीआइ ने कहा, वर्ष 1971 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.20 प्रतिशत थी जो वर्ष 2024 में घटकर एक प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। इस हिसाब से वर्ष 2024 में भारत की आबादी 138-142 करोड़ के बीच रह सकती है। एसबीआइ का अनुमान है कि इस साल ही जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और वर्ष 2025 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर में वर्ष 2011 की तुलना में कमी आई है जबकि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश व बिहार के साथ उत्तर भारत के राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि में अधिक भूमिका निभाई है। एसबीआइ के अनुसार, धीरे-धीरे बच्चों की आबादी कम हो रही है और बुजुर्गों की बढ़ रही है। वर्ष 2024 में कुल आबादी में 0-14 साल के बच्चों की हिस्सेदारी 24.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2011 में यह 30.9 प्रतिशत थी। वहीं, बुजुर्गों की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में 10.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है और यह वर्ष 2031 तक बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो जाएगी। इस साल बुजुर्गों की आबादी 15 करोड़ होने का अनुमान है जिनमें 7.7 करोड़ महिलाएं होंगी। भारत में काम करने वाली आबादी (15-59 साल) की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2021 में यह हिस्सेदारी 64.4 प्रतिशत थी जो 2031 में 65.2 प्रतिशत हो जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, 2011 की जनगणना के मुताबिक 31.1 प्रतिशत आबादी शहर में रह रही थी जो वर्ष 2024 में 35-37 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 में 75-80 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में जल्द लगेगा सेमीकंडक्टर संयंत्र : जितिन प्रसाद

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को कहा, उत्तर प्रदेश में जल्दी ही सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र लगेगा। राज्य पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ उप्र उन गिन-चुने स्थानों में शामिल होगा,जहां सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई होगी।

जितिन प्रसाद ने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 21वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सहित सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख निवेश गंतव्य है। देश के भीतर उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों में से एक है और आने वाले समय में यह 'भारत का विकास इंजन' होगा। प्रसाद ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका के साथ चिप मैन्यूफैक्चरिंग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इस बात पर जोर है कि है कि ये प्रौद्योगिकियां आगे चलकर लोगों के दैनिक जीवन में अधिक-से-अधिक दिखाई देंगी और यह आवश्यक है कि हम इन प्रौद्योगिकियों को जल्द से जल्द समझें।'

आरटीआइ पोर्टल की स्थापना संबंधी याचिका पर 11 राज्यों से जवाब तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आंध्र प्रदेश समेत 11 राज्यों से जवाब तलब किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें 2023 के फैसले के अनुसार अभी भी अपने यहां सूचना का अधिकार (आरटीआइ) पोर्टल की स्थापना करनी है। नोटिस का जवाब 21 अक्टूबर तक दिया जाना है।

शीर्ष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में पिछले वर्ष 20 मार्च को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं हाई कोर्टों को तीन महीने के भीतर आरटीआइ वेबसाइट स्थापित करने का आदेश दिया था। अदालत का कहना था कि आनलाइन सुविधाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार होंगी।

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एवं जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता अनुज नकाडे के वकील की दलील पर संज्ञान लिया कि 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी आरटीआइ वेबसाइट स्थापित नहीं की हैं। पीठ ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता के वकील

- सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए दिया 21 अक्टूबर तक का समय
- कोर्ट ने गत वर्ष राज्यों को आरटीआइ वेबसाइट बनाने का आदेश दिया था

के हवाले से इन राज्यों के नाम दर्ज किए। ये हैं- आंध्र प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम, बंगाल, अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव और दादरा व नगर हवेली, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद पीठ ने इन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए।

नई तकनीक पर जोर दें तटरक्षक बल : राजनाथ

- रक्षा मंत्री ने 41वें आइसीजी कमांडर सम्मेलन का किया शुभारंभ
- भविष्य में समुद्री खतरों के प्रति सतर्क और तैयार रहना को कहा

नई दिल्ली में मंगलवार को तटरक्षक कमांडरों के 41वें सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को यहां 41वें भारतीय तटरक्षक (आइसीजी) कमांडर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तटरक्षक बल के मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित करते हुए राजनाथ ने आइसीजी को भारत का अग्रणी गार्ड बताया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में उभरती नई तकनीकों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि दुनिया इस समय एक प्रौद्योगिकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,क्वांटम टेक्नोलाजी और ड्रोन के इस युग में सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में समुद्री खतरों में वृद्धि होगी ऐसे में हमें सतर्क और तैयार रहना होगा।

रक्षा मंत्री ने कहा कि जन संसाधन का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन दुनिया को हमें प्रौद्योगिकी युक्त तटरक्षक बल के रूप में जानना चाहिए। उन्होंने नई तकनीक के नकारात्मक पक्ष से सावधान रहने के लिए आगाह किया।

राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी को दोधारी तलवार करार दिया और तटरक्षक बल से संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय, सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया।

उन्होंने सशस्त्र बलों और तटरक्षक बल को आधुनिक बनाने और मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तटरक्षक बल के लिए चार हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं।

कालेजों में भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षण की तैयारी शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- देश के 75 विश्वविद्यालयों में अगले महीने से शुरू होगा शिक्षकों का प्रशिक्षण
- छह माह में 10,000 शिक्षकों और एक हजार शोधार्थियों को किया जाएगा प्रशिक्षित

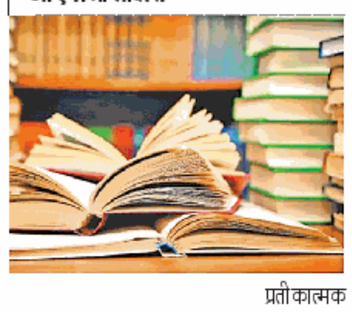

प्रतीकात्मक

देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थान अब भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक बनेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अक्टूबर से शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसमें कालेजों में पढ़ाने वाले 10,000 शिक्षकों व एक हजार शोधार्थियों को छह माह में भारतीय ज्ञान से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यूजीसी की इस पहल को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में की गई सिफारिशों के अमल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसमें छात्रों को प्रत्येक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने पर जोर दिया गया है। यह प्रशिक्षण देश के 75 विश्वविद्यालयों के जरिये दिया जाएगा और क्षमता के आधार पर संस्थानों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक चयनित संस्थान को 33 लाख रुपये की मदद भी दी जाएगी। यूजीसी के मुताबिक इसकी आधी राशि संस्थानों को चयन के साथ ही दे दी जाएगी। आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से प्रस्ताव मांगा है। फिलहाल यह प्रशिक्षण अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा। गौरतलब है कि मुख्य प्रशिक्षकों व विषय विशेषज्ञों की एक टीम तैयार पहले ही तैयार की जा चुकी है।

बड़ा कदम

सड़कों के निर्माण में ठोस अपशिष्ट के प्रयोग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, देशभर की 2304 लैंडफिल साइट पर जमा लगभग 1700 टन कूड़े के निस्तारण के लिए शुरू होंगे प्रयास

कचरे से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यों की सड़कें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शहरों के लिए समस्या का पहाड़ बन चुके कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन-2.0 से जोड़ते हुए कई माह से मंत्रालय इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहा था कि शहरी ठोस अपशिष्ट का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाए। अब सरकार ने पूरी गाइडलाइन बना ली है। कूड़े में से बड़ी मात्रा में निकलने वाली मिट्टी का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में करने के साथ ही राज्यों से भी कहा है कि वह भी सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जुड़ी सभी संस्थाओं के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को भी गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी नीति बनाने पर काम कर रही है कि प्रोसेस्ड सालिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, स्टील स्लैग (स्टील निर्माण के दौरान निकले वाला अपशिष्ट) और इंडस्ट्री वेस्ट का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाए। इसी के तहत फिलहाल शहरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के सड़क निर्माण में प्रयोग के लिए गाइडलाइन बना ली गई है। सरकार का आकलन है कि वर्तमान में लगभग 1700 लाख टन कूड़ा 2304 लैंडफिल साइटों पर इकट्ठा है। इस वजह से करीब 10 हजार हेक्टेयर जमीन घिरी हुई है। इसे देखते हुए ही गति शक्ति अभियान के तहत हाईवे निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ा गया है। हाईवे निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर खेतों से मिट्टी लेनी पड़ती है। ठोस अपशिष्ट का इस्तेमाल कर इससे काफी हद तक बचा जा सकता है।

प्रतीकात्मक

मंत्रालय ने बताया है कि ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग से निकलने वाली मिट्टी से हाईवे निर्माण के दो पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुके हैं। अब इस प्रक्रिया को अन्य हाईवे के निर्माण में अपनाया जाएगा। गाइडलाइन में इस प्रक्रिया को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि डीपीआर के स्तर के प्रोजेक्ट, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट और आगामी परियोजनाओं के लिए ठेकेदार, संबंधित प्राधिकरण और निकाय किस तरह से काम कर सकते हैं। सभी प्रकरणों में त्रिपक्षीय करार करने होंगे, ताकि ठोस अपशिष्ट से निकलने वाली मिट्टी की आपूर्ति निर्माण के लिए सुनिश्चित हो सके। राज्यों से इस व्यवस्था को अमल में लाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।

****

देश के 34 आयुर्वेद कालेजों की मान्यता पर रोक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : केंद्रीय आयुष मंत्रालय की सहमति पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एनसीआइएसएम नई दिल्ली ने देशभर के 34 मेडिकल कालेजों की मान्यता पर रोक लगा दी है। इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात के एक-एक आयुर्वेद कालेज, बिहार व पंजाब के दो-दो, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड के तीन-तीन कालेज, उत्तर प्रदेश के 17 आयुर्वेद मेडिकल कालेज शामिल हैं।

आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डा. राकेश पांडेय ने बताया कि इन 34 कालेजों में 31 निजी कालेज हैं और तीन शासकीय आयुर्वेद कालेज बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान (अजमेर) के हैं। देशभर में 474 मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कालेज हैं, जहां पर सेंट्रल व स्टेट कोटे की सत्र 2024-25 की नीट यूजी काउंसलिंग जारी है। जिनकी मान्यता रोकी गई है उन कालेजों में टीचिंग स्टाफ की कमी है। इसके साथ ही मरीजों की संख्या भी कम हो रही।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

आज सीमा पार तक जाएगा जम्मू-कश्मीर में मजबूत लोकतंत्र का संदेश

गगन कोहली ● जागरण

- राजौरी में एलओसी पर तारबंदी से आगे और अग्रिम चौकियों के बीच बने कई मतदान केंद्र
- छह जिलों की 26 सीटों पर पड़ने वाले वोट पाकिस्तान के षड्यंत्रों और दुष्प्रचार पर करेंगे चोट

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान संपन्न कराने के लिए मंगलवार को श्रीनगर के डल झील क्षेत्र में एक बूथ को जाते कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी। एपी

राजौरी : कभी आतंकी हमला तो कभी घुसपैठ का प्रयास। मगर आज बारी आम मतदाता की है। दुनिया देखेगी, जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की ताकत। बुधवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जम्मू संभाग में पाकिस्तानी की सीमा से सटे और आतंकी हिंसा का केंद्र रहे राजौरी और पुंछ जिलों के साथ रियासी जिले में भी मतदान होगा। रियासी में ही आतंकियों ने जून में श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था, जिनमें नौ लोगों की जान चली गई थी। इन तीन जिलों के अलावा कश्मीर में श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल जिलों में भी मतदाता होगा। अनुच्छेद-370 हटने के बाद पहली बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में इन छह जिलों की 26 विधानसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले वोट सीमा पार पाकिस्तान के नापाक षड्यंत्रों और उसके दुष्प्रचार पर सीधी चोट करेंगे। मतदान को पूरी तरह निष्पक्ष व सुरक्षित बनाने के लिए चुनाव आयोग, प्रशासन और सुरक्षाबलों ने पूरी तैयारी कर ली है।

तारबंदी के आगे बने हैं मतदान केंद्र : राजौरी में 20 पंचायतों के 22 गांव एलओसी पर और उसके पास स्थित हैं और सीधे पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की रेंज में आते हैं। इन गांवों में दो मतदान स्थल सेर व मकड़ी एलओसी पर तारबंदी से आगे व अग्रिम चौकियों के बीच स्थित हैं। यहां करीब 1500 मतदाता हैं। राजौरी जिले के 51 व पुंछ जिले के 66 मतदान केंद्र एलओसी पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए विशेष बुलेट प्रूफ वाहनों को भी तैयार रखा गया है।

उमर अब्दुल्ला नहीं लेना चाहते थे कोई रिस्क

उमर अब्दुल्ला।

गांदरबल से उतरे उमर अब्दुल्ला अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनके दादा शेख अब्दुल्ला, पिता डा. फारूक अब्दुल्ला और वह खुद यहां से विधायक रहे, लेकिन इस बार भी उन्हें पीडीपी के बशीर अहमद मीर से टक्कर लेनी पड़ रही है। बशीर ने यहां उन्हें 2014 में हराया था। निर्दलीय इशफाक अहमद व सरजनी बरकती और शेख आशिक ने भी मुकाबले फंसा बना दिया। बड़गाम में भी उन्हें पीडीपी के सैयद मुंतजिर मेहदी से चुनौती मिल रही है। नेकां 1977 के बाद से इस सीट पर कभी नहीं हारी।

नौशहरा में रैना को नेकां से उलझन

रविंद्र रैना। फाइल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशहरा की लड़ाई में उलझे हुए हैं। यहां कांग्रेस से गठबंधन में नेकां के सुरेंद्र चौधरी ने पेंच फंसा दिया। चौधरी पीडीपी से भाजपा होते हुए नेकां में शामिल हुए हैं। पिछले चुनाव में रैना ने यह सीट जीती थी तब चौधरी उनके साथ थे। पीडीपी ने यहां हक नवाज को उतारा है।

करा और बुखारी पर सीट जीतने का दबाव

तारिक हमीद करा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद करा और जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी का कद इसी चुनाव परिणाम से तय होगा। करा पर पार्टी को जिताने ही नहीं, खुद की सीट भी जीतने का दबाव है। वह सेंट्रल शाल्टेंग से चुनाव लड़ रहे हैं।

रियासी में चुनाव कर्मियों का वाहन खाई में गिरा, दो की मौत

संवाद सहयोगी ● जागरण

टुकसन क्षेत्र में खाई में गिरा वाहन। जागरण

रियासी: रियासी जिले की माहौर तहसील से मंगलवार को चुनाव कर्मियों को लेकर गुलाबगढ़ शडोल की तरफ जा रही टाटा सूमो टुकसन क्षेत्र में चढ़ाई पर अचानक बंद होकर पीछे की तरफ लुढ़कने लगी और गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में वाहन चालक व एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई, जबकि जोनल मस्जिट्रेट समय रहते वाहन से कूद कर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन उन्हें भी हल्की चोट लगी है। मृतक वाहन चालक जावेद इकबाल आयु 30 पुत्र बशीर अहमद निवासी खोड़ गुलाबगढ़ जिला रियासी और पुलिसकर्मी एजाज खान आयु 30 वर्ष निवासी कोटरंका जिला राजौरी का रहने वाला था।

जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग के रियासी जिले में स्थित धरमाड़ी सरकारी डिग्री कालेज के असिस्टेंट प्रो. अजय कुमार की शडोल जोन में बतौर जोनल मजिस्ट्रेट चुनाव ड्यूटी लगाई थी। मतदान से एक दिन पहले अजय कुमार और उनके साथ बतौर सुरक्षाकर्मी एजाज खान टाटा सूमो में सवार होकर शडोल की तरफ रवाना हुए। वाहन जब टुकसन के जेब्रा मोड़ पर पहुंचा तो चढ़ाई के दौरान अचानक बंद हो गया और पीछे की तरफ जाने लगा। चालक ने ब्रेक लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

भाजपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन दल बना रहे रोचक मुकाबला, बागियों की वजह से दिग्गजों की साख दांव पर

उत्तर हरियाणा की 27 विधानसभा सीटों पर हार-जीत बदल देती है सत्ता, धुरंधरों की जोर-आजमाइश जारी

चुनावी विश्लेषण उत्तर हरियाणा

सुधीर तंवर ● जागरण

नायब सैनी

कंवरपाल गुर्जर

सुभाष सुधा

असीम गोयल

महिपाल ढांडा

ज्ञानचंद गुप्ता

चंद्र मोहन

अनिल विज

- भाजपा-कांग्रेस में सीधी टक्कर, कहीं इनेलो-बसपा और जजपा-आसपा गठबंधन तो कहीं बागी बना रहे त्रिकोणीय मुकाबला
- पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत की 27 विधानसभा सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर
- कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के मंत्रियों कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, असीम गोयल व महिपाल ढांडा को मिल रही कड़ी चुनौती
- ज्ञानचंद गुप्ता, चंद्र मोहन विश्नोई, अनिल विज और निर्मल सिंह कड़े मुकाबले में फंसे

निर्मल सिंह

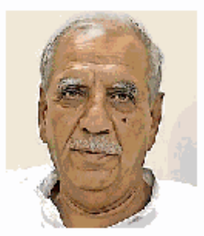

अशोक अरोड़ा

कमलेश ढांडा

पिछले विधानसभा चुनावों में स्थिति

जिला	कुल विस सीटें	भाजपा	कांग्रेस	जजपा	अन्य
पंचकूला	2	1	1	0	0
अंबाला	4	2	2	0	0
यमुनानगर	4	2	2	0	0
कुरुक्षेत्र	4	2	1	1	0
कैथल	4	2	0	1	1
करनाल	5	3	1	0	1
पानीपत	4	2	2	0	0

किसान आंदोलन का असर कम, स्थानीय मुद्दे हावी

लोकसभा चुनाव में हावी रहा किसान आंदोलन का असर विधानसभा चुनावों में कम दिख रहा है। स्थानीय मुद्दे हावी हैं, जिनमें अधिकतर विकास कार्यों से जुड़े हैं। खस्ताहाल सड़कें और गलियां, सफाई व्यवस्था, बिजली-पानी बड़ा मुद्दा है।

उत्तर हरियाणा: हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से घिरे उत्तर हरियाणा की 27 विधानसभा सीटें दो बार से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती आई हैं। मौजूदा विधानसभा चुनाव में न यहां कोई खास लहर दिख रही और न ऐसा बड़ा मुद्दा, जो चुनावों को पूरी तरह किसी के पक्ष में मोड़ दे। अधिकतर सीटों पर प्रमुख राष्ट्रीय दलों-भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, जबकि कुछ सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन तथा जननायक जनता पार्टी (जजपा) और आजाद समाज पार्टी (आसपा) का गठबंधन तो कहीं बागी प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं।

हरियाणा का सिरमौर कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके चार मंत्रियों के साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। शहरों में मजबूत पकड़ वाली भाजपा को शहरी क्षेत्रों में भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में कांग्रेस मजबूत दिख रही है। पंचकूला में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी तरह, कालका में भाजपा की शक्ति रानी शर्मा और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी में सीधा मुकाबला है।

लाडवा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कांग्रेस के मेवा सिंह से चुनौती मिल रही है। नायब सिंह सैनी को उनकी छवि और थोड़े समय में कराए गए कई कामों का लाभ भी मिलने की पूरी संभावना है। थानेसर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा राज्यमंत्री सुभाष सुधा टक्कर दे रहे हैं तो जगाधरी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कांग्रेस के अकरम खान के साथ कांटे का मुकाबला है। अंबाला छावनी में पूर्व मंत्री अनिल विज को निर्दलीय चित्रा सरवारा कांटे की टक्कर दे रही हैं।

इसी तरह, अंबाला शहर में राज्यमंत्री असीम गोयल के लिए कांग्रेस के निर्मल सिंह से पार पाना आसान नहीं होगा। पानीपत ग्रामीण में राज्यमंत्री महिपाल ढांडा और कांग्रेस के सचिन कुंडू में सीधा मुकाबला है।

कलायत में पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा के साथ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण, इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा और आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा मुकाबले को चतुष्कोणीय बना रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनावों में मोदी लहर पर सवार भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए प्रदेश में कुल 47 सीटें जीती थी, जिनमें 22 सीटें उत्तर हरियाणा के सात जिलों में मिली। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में भाजपा की पकड़ ढीली पड़ी तो 14 सीटों पर ही कमल खिला। बहुमत से दूर हुई भाजपा को जजपा की मदद से सरकार बनानी पड़ी। जीटी रोड बेल्ट में कम हुए प्रभाव की भरपाई की रणनीति के तहत ही भाजपा ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली के माध्यम से प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया है, ताकि मतदाताओं को साधा जा सके।

गलतफहमी में ना रहें कांग्रेस-भाजपा हम रीजनल नहीं, ओरिजनल पार्टी

हरियाणा में जब भी पूर्व उप प्रधानमंत्री स्व. देवीलाल की राजनीतिक विरासत की बात आती है तो सबसे पहले इनेलो प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और फिर उनके बेटे अभय सिंह चौटाला का नाम आता है। ताऊ देवीलाल ने जिस तरह अपने बेटे ओमप्रकाश चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक उसी तरह इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। इनेलो के दोफाड़ होने के बाद अभय सिंह चौटाला ने इस पार्टी को बिखरने नहीं दिया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का मामला हो या फिर विधानसभा से सड़क तक किसानों, युवाओं और गरीबों के हक की आवाज बुलंद करने का मामला। वह हर मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ खड़े नजर आए। इनेलो में प्रधान महासचिव का दायित्व संभाल रहे अभय सिंह चौटाला के सामने कई ऐसे मौके आए, जब उनके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला की ओर से इनेलो व जजपा के एक होने के प्रस्ताव आए, लेकिन इसके लिए न तो अभय सिंह चौटाला राजी हुए और न ही ओमप्रकाश चौटाला ने कभी अनुमति दी। चुनावी रण में अब इनेलो और बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस गठबंधन की ओर से अभय सिंह चौटाला राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा हैं। विधानसभा चुनाव में मुद्दों से लेकर सत्ता तक पहुंचने के प्रयासों पर दैनिक जागरण के राज्य ब्यूरो प्रमुख अनुराग अग्रवाल ने हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अभय सिंह चौटाला से विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश।

साक्षात्कार

● प्रदेश में पांच बार सत्ता चलाने वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 20 साल से सत्ता से दूर है। सत्ता से इतनी लंबी दूरी को कैसे देखते हैं?

– मेरी रगों में ताऊ देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला का खून दौड़ रहा है। ताऊ देवीलाल जैसे लोग राजनीति में बहुत कम होते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद तक ठुकरा दिया था। ताऊ देवीलाल ने जिंदगी भर किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग के कल्याण की दिशा में काम किया। उनके अधूरे कार्यों को ओमप्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाया। अब मैं उन दोनों की राह पर हूं। इसलिए संघर्ष मेरे लिए नई बात नहीं है। मेरे खून की बूंद-बूंद में संघर्ष है। जनता के हितों के आगे हम कुर्सी की परवाह नहीं करते। मैंने हर वर्ग के लोगों के मुद्दे उठाए। मुझे कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की सरकारों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं न तो कभी दबा, न डरा और न कभी झुका।

● तीन कृषि कानूनों के विरोध में आपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। आप फिर जीतकर आ गये तो इस्तीफा देने का फायदा ही क्या हुआ?

– मैंने किसी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तीफा नहीं दिया था। मैंने वास्तविक रूप से किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा ने उपचुनाव में मुझे हराने के लिए हाथ मिला लिये थे। फिर भी वह मुझे चुनाव नहीं हरा सके। पूरे देश में मैं अकेला ऐसा विधायक था, जिसने इस्तीफा देने की पहल की। यदि कांग्रेस और भाजपा के विधायक किसानों के इतने ही हितैषी थे तो उन्होंने ऐसी पहल क्यों नहीं की। उल्टा, मेरे विरुद्ध हो गये। किसानों की एकजुटता और मेरे इस्तीफा देने का असर यह हुआ कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह किसानों की एकजुटता और वोट की ताकत का ही नतीजा है।

● इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आज प्रदेश में राजनीतिक रूप से कहीं ठहरता दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या सोचते हैं?

– यह इन दलों की गलतफहमी है। इनेलो और बसपा का गठबंधन सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं है। यह किसान, मजदूर, गरीब और कमेरे वर्ग का गठबंधन है, जो किसी भी सत्ता को बनाने में और किसी भी सत्ता को गिराने में अहम भूमिका निभाता रहा है। कांग्रेस और भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इन दलों के नेताओं को अपने दिल्ली दरबार में हाथ जोड़कर मांगने के लिए खड़ा देखा जा सकता है, लेकिन हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। राज्य में इनेलो ने हमेशा गरीब, जरूरतमंद और आम आदमी की सरकार चलाई है। ताऊ देवीलाल और ओमप्रकाश चौटाला ने लोगों की सरकार लोगों के हिसाब से चलाई।

● कांग्रेस और 10 साल के भाजपा के राज को आप कैसे देखते हैं?

– हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जमीनों के सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) यानी प्रापर्टी डीलिंग की सरकार चलाई। उसी तर्ज पर भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसान, दलित और गरीब विरोधी फैसले लिये। अब समय बदलाव का है। लोगों को समझ आ चुका है। राज्य में इनेलो और बसपा गठबंधन ताऊ देवीलाल व ओमप्रकाश चौटाला के साथ बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर की नीतियों की सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है।

● कांग्रेस की वरिष्ट दलित नेता कुमारी सैलजा को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी उनके प्रति सहानुभूति जताई है।

– कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतिहास रहा है कि वे किसी भी दलित नेता को अपनी पार्टी में उभरने नहीं देते। पहले राहुल गांधी के करीबी अशोक तंवर के साथ मारपीट कर उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब सोनिया गांधी की करीबी कुमारी सैलजा को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हुड्डा कांग्रेसी नहीं, बल्कि भाजपा के एजेंट के रूप में राज्य में काम कर रहे हैं। **● पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इनेलो समेत विभिन्न क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। उनकी नजर में इनेलो, जजपा, हलोपा और हजपा जैसे दल सिर्फ वोटकाटू दलों की भूमिका में होते हैं**

– यही तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलतफहमी है। हम रीजनल (क्षेत्रीय) पार्टी नहीं, बल्कि ओरिजनल (वास्तविक) पार्टी हैं। नेशनल दलों की सरकारें फैसलें नहीं ले पातीं। वह दिल्ली की राजनीति और दिल्ली की केंद्र सरकार के फैसलों से जुड़ी होती हैं। चाहकर भी प्रदेश का विकास जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं कर पाती। राज्य में जब भी लोकदल की सरकार रही, पूरे प्रदेश में सरकार चलकर लोगों के द्वार तक गई और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। इसलिए किसी भी बड़े दल या नेता को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद नहीं होता। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें पहले भी थी और अब भी हैं।

● कांग्रेस और भाजपा के बीच सत्ता के रण में इनेलो-बसपा गठबंधन को आप कहां खड़ा पाते हैं

– पहले तो मैं आपको बता दूं कि राज्य में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। हरियाणा में हंग असेंबली (त्रिशंकु) विधानसभा बनेगी। इनेलो-बसपा गठबंधन को 20 से 25 सीटों पर जीत मिलने वाली है। तब हम सरकार बनाने के लिए किसी दल के पास नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे दलों को हमारी सरकार में शामिल होने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा।

● कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि इनेलो की एक भी सीट राज्य में नहीं आएगी।

– आपने ठीक ध्यान दिला दिया। आप सुरजेवाला, जय प्रकाश और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत विभिन्न कांग्रेस नेताओं की वीडियो उठाकर देखो। यह लोग नौकरियां अभी से बेचने लगे हैं। कोटा सिस्टम पर आधारित सरकार की बात कर रहे हैं। **● कांग्रेस और भाजपा से कहीं आगे बढ़कर आपके गठबंधन ने साढ़े सात हजार रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया है। राज्य में 35 लाख लोग पेंशन लेते हैं। इतने बजट का इंतजाम कैसे होगा**

– मैंने पहले भी कहा था कि हमें सरकार चलाने के लिए दिल्ली की जरूरत नहीं होती। ताऊ देवीलाल ने सामाजिक कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे फैसले लिए थे, जो आज की जरूरत बन गये हैं। ताऊ ने सौ रुपये पेंशन आरंभ की थी, जो आज के दस हजार रुपये के बराबर है। किसानों का कर्जा माफ किया था। हमारी गठबंधन की सरकार उसी परिपाटी पर ताऊ देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी और धन की कमी इसमें बाधा नहीं आएगी।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफार्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

हुड्डा व कुमारी सैलजा की पुरानी तस्वीर प्रसारित

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनाव पांच अक्टूबर को होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की कांग्रेस से नाराजगी की खबरें आईं जिसे भाजपा ने मुद्दा बनाया। कांग्रेस से चल रही कथित अनबन के बीच एक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है जिसमें कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी सैलजा साथ नजर आ रहे हैं। यूजर्स इस तस्वीर को हाल-फिलहाल का बताकर कुमारी सैलजा और कांग्रेस के बीच सुलह का दावा कर रहे हैं।

पड़ताल: पोस्ट की पड़ताल करने के दौरान हमें एक्स यूजर प्रमोद कुमार सिंह की पोस्ट दिखी। उन्होंने 22 सितंबर को भूपेंद्र हुड्डा की पांच साल पुरानी पोस्ट के स्क्रीनशाट को शेयर करते हुए प्रसारित तस्वीर को पुराना बताया। जांच में हमे पता चला कि भूपेंद्र हुड्डा ने 24 सितंबर, 2019 को इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए कुमारी सैलजा को उनकी जन्मतिथि की बधाई दी थी। हमें 23 सितंबर को जारी कुमारी सैलजा के साक्षात्कार का एक वीडियो भी मिला जिसमें उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को नकार दिया था।

क्या हो रहा है प्रसारित

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने 22 सितंबर को प्रसारित तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, 'इस फोटो ने भाजपा और इनेलो में आग सी लगा दी है। खट्टर, मोदी जी, शाह जी, अभय चौटाला सब परेशान क्यों हैं?' कई अन्य यूजर्स भी समान दावे के साथ इसे शेयर कर रहे हैं।

निष्कर्ष: कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुमारी सैलजा की यह तस्वीर करीब पांच साल से इंटरनेट पर मौजूद है।

झूठी खबर और अफवाहों का सच जानने के लिए विश्वास न्यूज के वाट्सएप चैनल को फालो करने के लिए कोड स्कैन करें।

राहुल गांधी में महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझ की कमी: रेड्डी

जी किशन रेड्डी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को राजा बताने के बयान पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जम्मू: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि बालक बुद्धि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर समझ की कमी है। बता दें कि मोदी 28 सितंबर को जम्मू आ रहे हैं और उनकी यहां एमए स्टेडियम में रैली है। राहुल गांधी के उपराज्यपाल को राजा व बाहरी बताने के बयान पर पलटवार करते हुए रेड्डी ने कहा कि उन्हें इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि राज्यपाल या उपराज्यपाल उसी राज्य के नहीं होते हैं। उन्हें सोच समझकर ही बयान देने चाहिए। राहुल कहते हैं कि उपराज्यपाल बाहर के हैं। वह बताएं कि उनकी सरकारों ने उसी प्रदेश से कितने उपराज्यपाल और राज्यपाल बनाए हैं और सूची भी जारी करें।

हरियाणा के चुनाव में नूंह की सांप्रदायिक हिंसा का मामला उठा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

नूंह (मेवात) में सांप्रदायिक हिंसा का मामला विधानसभा चुनाव में गरमा गया है। आरएसएस से जुड़े संगठन बजरंग दल की अगुवाई में 31 जुलाई को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा रखी गई थी, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा के दौरान छह लोग मारे गये थे। हिंसा के मुख्य आरोपितों में फिरोजपुर झिरका के तत्कालीन कांग्रेस विधायक एवं मौजूदा प्रत्याशी मामन खान (जमानत पर) हैं। फिरोजपुर झिरका के घाटा गांव में एक जनसभा के दौरान मामन खान यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किए हैं, उन्हें मेवात छोड़ना पड़ेगा। दी जाट एसोसिएशन ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि खुलेआम हिंदुओं के कत्ल की चेतावनी दी जा रही है।

राहुल के हस्तक्षेप से दूर हुई सैलजा की नाराजगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विवाद के चलते प्रचार अभियान से दूर चल रहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा को मना लिया गया है। टिकट बंटवारे में अनदेखी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने देने और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराज चल रही सैलजा को मनाने के लिए राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे को जिम्मेदारी सौंपी थी। खुद मोबाइल पर मैसेज भेजकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष से मिलने को कहा। खरगे ने सैलजा को सीएम के चेहरे के रूप में उनके नाम पर चर्चा करने का भरोसा दिलाया। तब सैलजा प्रचार के लिए तैयार हुईं। फिलहाल कांग्रेस बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी सीएम का चेहरा घोषित किए बगैर चुनाव लड़ रही है। अब वह गुरुवार को नरवाना से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी।

दरअसल, हरियाणा कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी के दौरों का जो शेड्यूल तैयार किया था, उसमें सैलजा-सुरजेवाला समर्थकों के नाम नहीं थे। इस पर भी सैलजा ने आपत्ति जताई। फिर प्रचार कार्यक्रम दोबारा बनाया गया। अब राहुल 26 सितंबर को सबसे पहले सैलजा समर्थक के लिए वोट मांगने असंध पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि राहुल ने सैलजा का मान रखने और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए ही असंध से प्रचार अभियान की शुरुआत करने पर सहमति जताई है। सैलजा के साथ हुड्डा भी चुनाव प्रचार के दौरान राहुल के साथ होंगे।

अपनी जन्मतिथि पर मंगलवार को नई दिल्ली में आवास पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा। प्रेट्र

****

25 सितंबर यानी भाजपा के सह संस्थापक पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस को अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए घर-घर संपर्क भी किया जा रहा है।

इस्तीफा दें सिद्दरमैया, जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच होने दें : भाजपा

जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज होने के बाद भाजपा हुई हमलावार

चंद्रशेखर बोले- राहुल गांधी क्यों नहीं करते भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अपने नेताओं पर कार्रवाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वी वाई विजयेंद्र संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए। प्रेट्र

राजीव चंद्रशेखर। फाइल

मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की घेरेबंदी भाजपा ने तेज कर दी है। राज्यपाल द्वारा दी गई जांच की अनुमति के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद और आक्रामक हुई भाजपा ने मांग की है कि यदि नैतिकता बची है तो सीएम तुरंत इस्तीफा दें ताकि घोटाले की निष्पक्ष-स्वतंत्र जांच हो सके। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस सहित आइएनडीआइए के नेताओं ने राजनीति की नैतिकता को तार-तार कर दिया है। भाजपा को अहसास था कि भ्रष्टाचार का यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। इसी के मद्देनजर कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने लगभग दो माह पहले मैसुरु क्षेत्र में एक सप्ताह की पदयात्रा की थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जहां प्रदेश में फिर से मामला गर्म होगा वहीं दिल्ली में राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, मुडा भूमि घोटाले, वाल्मीकि विकास घोटाले आदि पर प्रेस कांफ्रेंस करके देश की जनता को बताएं कि कांग्रेस के नेता सत्ता में आते ही गरीबों के संसाधनों को क्यों लूटने लग जाते हैं? राहुल अमेरिका में जगह-जगह जाकर भारतीय संविधान-लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के नेता सिद्दरमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि मुडा घोटाले में सिद्धरमैया के खिलाफ पर्याप्त सुबूत हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल ने बिस चुनाव में ढेरों झूठे वादे कर कर्नाटक में सत्ता हथियाई मगर आज स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसियों को कर्नाटक की जनता के कल्याण या विकास से कोई सरोकार नहीं है। वाल्मीकि आदिवासी विकास निगम घोटाले में 180 करोड़ रुपये से अधिक का अवैध हस्तांतरण

राज्यपाल ने 16 अगस्त को सीएम के खिलाफ जांच को मंजूरी दी थी

प्रथम पृष्ठ से आगे

राज्यपाल ने कई शिकायतें मिलने के बाद 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत सीएम के खिलाफ जांच को मंजूरी दी थी। सिद्दरमैया ने राज्यपाल के आदेश की वैधता को 19 अगस्त को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि वैधानिक प्रविधानों तथा मंत्रिपरिषद की सलाह बिना ये मंजूरी आदेश दिया गया। उधर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि सिद्दरमैया के इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। वे बेदाग निकलेंगे।

शामिल था। सिद्दरमैया के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को भी डिफेंस एयरोस्पेस पार्क में नियमों को तोड़-मरोड़कर भूमि उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि आइएनडीआइए के घटक दलों में भी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।

'धनबल का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे'

राज्य ब्यूरो, जागरण ● रांची

- भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की लगाई क्लास
- राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण आचरण के खिलाफ किया गया आगाह

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू के साथ झारखंड दौरे पर हैं। एएनआइ(फाइल)

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव पूरी तरह पक्षपातरहित, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को रेडिसन ब्लू होटल में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग से स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव में किसी भी तरह के प्रलोभन के विरुद्ध आयोग का जीरो टालरेंस होगा। विधानसभा चुनाव लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रविधानों एवं आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार संपन्न कराए जाएं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डा. सुखबीर सिंह संधु भी उपस्थित थे। आयोग ने इस क्रम राज्य सरकार और जिला प्रशासन को पक्षपातपूर्ण आचरण के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने प्रलोभन के खिलाफ जीरो-टालरेंस लागू करने तथा धनबल पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग का जोर सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने पर भी रहा। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्थानीय संस्कृति, खेल और प्रभावशाली लोगों को सम्मिलित करते हुए स्वीप गतिविधियों में मतदाताओं को सम्मिलित करने को कहा। आयोग ने बैठक के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और चिंताओं की विशेष रूप से समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें। निष्पक्ष आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें ताकि सभी दलों को समान अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को मतदाताओं के लिए सुविधाजनक मतदान का अवसर प्रदान करने की जरूरत है। मतदान को लेकर जागरूकता के लिए स्थानीय प्रभावशाली आइकान को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश: आयोग ने पिछले चुनावों में रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम आदि में मतदान प्रतिशत कम होने पर चिंता जताई। साथ ही शहरी उदासीनता को दूर करने के लिए बोकारो, धनबाद, रांची आदि जैसे शहरी क्षेत्रों में आउटरीच गतिविधियों को तेज करने के लिए कहा।

फर्जी खबरों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रखें कड़ी नजर: आयोग ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे फर्जी खबरों के लिए इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर रखें। फर्जी खबरों पर उचित एवं त्वरित कानूनी कार्रवाई करें।

सभी दलों के लिए समान रूप से हों सुलभ: आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्तों को विशेष रूप से सभी राजनीतिक दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और उनकी शिकायतों और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से उनसे मिलने का भी निर्देश दिया।

आरक्षण पर कांग्रेस व राहुल गांधी की नीति दोगली : मायावती

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ: आरक्षण और जाति आधारित गणना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर हमला जारी है। उन्होंने मंगलवार को फिर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी की नीति अस्पष्ट और दोगली है।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि केंद्र में रहते हुए कांग्रेसी सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई। अब सत्ता से बाहर होने पर जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाना, यह सब ढोंग नहीं तो और क्या है? उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस व राहुल गांधी की एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण नीति अस्पष्ट, दोगली और छलकपट की है। अपने देश में इनके वोट के लिए ये आरक्षण का समर्थन करने के साथ इसको 50 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाने की वकालत करते हैं और विदेश जाकर आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के इस दोहरे मापदंड से लोग सचेत रहें।

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाएगी : अमित शाह

कहा, भाजपा के पास हैं चुनाव जीतने के लिए ऊर्जावान बूथ कार्यकर्ता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट की गई। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में भाजपा ही सरकार बनाएगी। वह मंगलवार को नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। शाह महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर नागपुर पहुंचे हैं। दो दिन में वह नागपुर के अलावा छत्रपति संभाजी महाराज नगर, कोल्हापुर एवं नासिक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक नब्ज टटोलेंगे। इस दौरे की शुरुआत नागपुर से करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए ऊर्जावान बूथ कार्यकर्ता एवं मजबूत संगठन है। चुनाव आने पर अन्य राजनीतिक दल सभा एवं रोड शो करना शुरू करते हैं। लेकिन भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करती है। न्होंने राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि विकास खत्म होने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन, भाजपा ऐसा नहीं होने देगी।

'रिक्लेम द नाइट' में शामिल हुईं महिलाओं को कानूनी सहायता देगी माकपा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : माकपा ने कोलकाता के आरजी कर कांड के विरोध में हुए 'रिक्लेम द नाइट' अभियान में शामिल हुईं उन महिलाओं को कानूनी सहायता देने की बात कही है, जिन्हें पुलिस की ओर से अशांति फैलाने के आरोप में नोटिस भेजे जा रहे हैं। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बताया कि इसके लिए महिला अधिवक्ताओं की एक टीम तैयार की गई है। जिन महिलाओं को भी पुलिस की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है, वह इस टीम से मदद के लिए संपर्क कर सकती हैं। मालूम हो कि पुलिस की ओर से हाल में 'रिक्लेम द नाइट' के आयोजन से जुड़ीं पांच महिलाओं को नोटिस भेजा गया था। पहली बार 14 अगस्त फिर चार व नौ सितंबर की रात कोलकाता समेत पूरे बंगाल में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थीं। आयोजकों का कहना है कि पुलिस डराने-धमकाने के लिए ऐसा कर रही है। अभियान से पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी।

घटनास्थल पर देखे गए जूनियर डाक्टर काफी दिनों तक थे अनुपस्थित

- सीबीआइ ने पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर से फिर की पूछताछ

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में नौ अगस्त को दरिंदगी की शिकार पीड़िता का शव बरामद होने के बाद घटनास्थल सेमिनार हाल में जुटी भीड़ में उपस्थित प्रशिक्षु डाक्टर डा. अभिक दे आठ अगस्त से लगातार 20 दिनों तक अनुपस्थित थे। सरकारी अस्पताल एसएसकेएम के स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डाक्टर अभिक दे ने इसके लिए किसी को सूचित करने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी। एसएसकेएम के डीन अभिजीत हाजरा ने राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में इसका जिक्र किया है। सीबीआइ डा. दे की अनुपस्थिति के कारणों की पड़ताल कर रही है। वहीं सीबीआइ ने मंगलवार को कोलकाता के सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित अपने कार्यालय में पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर डा. अपूर्ब बिश्वास से डेढ़ घंटे पूछताछ की। डा. अपूर्ब बिश्वास ने दावा किया है कि टीएमसी विधायक निर्मल घोष के करीबी व पूर्व पार्षद संजीब मुखोपाध्याय ने धमकी दी थी कि अगर उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो खून की नदी बहेगी। पीड़िता के दो सहपाठियों से भी पूछताछ हुई है।

लगेंगे 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे

सुरक्षा के मद्देनजर आरजी कर अस्पताल की सभी इमारतों की हर मंजिल को सीसी कैमरे की निगरानी में लाया जाएगा। इसके लिए शुरुआत में अस्पताल में 500 से ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। 100 कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। अस्पताल में फिलहाल 190 सीसी कैमरे हैं।

केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर 2017 उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों से जवाब तलब किया जिसमें उसने शीर्ष कोर्ट के 2019 के आदेश पर प्रदान की गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने की मांग की है। निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी एवं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि केंद्र की याचिका पीड़िता एवं उसके परिवार के सदस्यों को सौंपी जाए। साथ ही टिप्पणी की कि शायद ही उन्हें कोई खतरा है, वह मामले को बंद करना चाहेगी। केंद्र के वकील ने कहा कि पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों के खतरे के विश्लेषण के अनुसार सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उप्र की वकील रुचिरा गोयल ने कहा कि मुकदमे समेत सभी चीजें दिल्ली स्थानांतरित की जा चुकी है। पीठ द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि पीड़िता दिल्ली में रहती है।

किसान हित में केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लाए : कंगना

जागरण संवाददाता, मंडी

कंगना रनौत

कहा-मेरे बयान का विरोध होगा, अकेली लड़ रही हूं टुकड़े-टुकड़े गैंग से

हिमाचल के मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने केंद्र सरकार से किसान हितैषी तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग की है। सोमवार को मंडी में सात दिवसीय ख्योड़ नलवाड़ मेला के समापन पर कंगना रनौत ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे इस बयान का विरोध होगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका है। तीनों कृषि कानूनों का कुछ ही राज्यों में विरोध हुआ था। तीनों कानूनों को वापस लाने के लिए किसानों को खुद आगे आना चाहिए। मैं किसान परिवार से संबंध रखती हूं। किसानों का दर्द समझती हूं। मेरे विरुद्ध किसानों को भड़काया गया। एक दिन सच्चाई सामने आएगी तो किसान भी समझ जाएंगे कौन सही कौन गलत था। उन्होंने कहा कि फिल्मी करियर दांव पर लगा दिया है। जान जोखिम में डाल टुकड़े-टुकड़े गैंग से अकेले लड़ रही हूं। यह लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगी। कंगना रनौत ने रविवार को मनाली में कहा था कि केंद्र से जो मदद आ रही है और कांग्रेस सरकार जो ऋण ले रही है, वह सोनिया गांधी को दी जा रही है। इस पर हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बयान नहीं हो सकता। कंगना के इस बयान से यह पता चलता है कि वह ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं। **काले कानूनों की वापसी नहीं होगी : कांग्रेस:** कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और काले कानून वापस हुए। अब वापसी का प्लान बना रहे हैं।

महाराष्ट्र में तिरंगा संविधान रैली निकालकर एआइएमआइएम ने दिखाई अपनी ताकत

ओमप्रकाश तिवारी ● जागरण

- रैली को निकालकर एआइएमआइएम ने मविआ को दिया संदेश, यदि मविआ में शामिल न किया गया तो मुस्लिम बहुल सीटों पर बिगाड़ देंगे खेल

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील। फाइल

मुंबई: आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) की सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज नगर से मुंबई तक निकाली गई तिरंगा संविधान रैली वास्तव में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसका शक्ति प्रदर्शन थी। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में हुआ यह शक्ति प्रदर्शन घोषित रूप से तो एक धर्मगुरु रामगिरि महाराज एवं भाजपा विधायक नीतेश राणे के बयानों के विरोध में उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर था। लेकिन, इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के मुस्लिमों को एआइएमआइएम के पक्ष में लामबंद करना था। कुछ सप्ताह पहले महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश महंत रामगिरि महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक बयान दिया था। उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एआइएमआइएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में उसी समय छत्रपति संभाजी महाराज नगर (पूर्व नाम औरंगाबाद) सहित मराठवाड़ा एवं उत्तर महाराष्ट्र के कई और शहरों में पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान होने की बात प्रचारित कर प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद ही भाजपा विधायक नितेश राणे ने दो अलग-अलग सभाओं में बोलते हुए कहा था कि संत रामगिरि महाराज को कुछ हुआ तो हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। हालांकि अपने बयान के बाद संत रामगिरि महाराज स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी बात बंगलादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में कही थी। फिर भी उनके विरुद्ध अलग-अलग शहरों में एफआअआर दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि रैली मुंबई में प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन इम्तियाज जलील मुस्लिम समाज सहित सभी राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति दिखाने में सफल रहे।

असदुद्दीन ओवैसी कई बार एआइएमआइएम को महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (मविआ) में शामिल करने का प्रस्ताव दे चुके हैं। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई है। अब यह शक्ति प्रदर्शन कर वह दिखाना चाहते हैं कि यदि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मविआ का हिस्सा नहीं बनाया गया तो वह राज्य की मुस्लिम बहुल सीटों पर मविआ का खेल बिगाड़ देंगे।

स्कूल से लौट रही छात्रा को कार में खींचा, होटल में सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ

- लखनऊ के सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज, एक हिरासत में और दूसरा फरार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बेखौफ बदमाशों ने स्कूल से घर लौट रही 14 वर्षीय छात्रा को जबरन कार में खींचा और फिर होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपितों ने नाबालिग का वीडियो बनाया और शिकायत करने पर प्रसारित करने की धमकी भी दी। बेसुध हो चुकी छात्रा को आरोपित घर के पास फेंककर फरार हो गए। सरोजनीनगर थाने की पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एक आरोपित दानिश को हिरासत में लिया है, जबकि दूसरे आरोपित आमीन की तलाश में टीम लगाई गई हैं।

छात्रा के पिता ने पुलिस को बताया कि सोमवार को शाम साढ़े चार बजे उनकी बेटी बदहवास हालत में रोते हुए मिली। कारण पूछा तो उसने बताया कि दोपहर एक बजे स्कूल से लौटते समय पड़ोस में रहने वाले दानिश और आमीन ने रोक लिया। वह कुछ समझती उससे पहले दोनों ने उसे जबरन कार में खींच लिया। मदद मांगने के लिए चीखी, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया। आरोपित उसे लेकर लोकबंधु अस्पताल के पास होटल पैराडाइज शांति इन पहुंचे। आमीन उसका बैग लेकर कमरे में चला गया। फिर दानिश ने उससे कहा कि बैग लेना है तो कमरे में चलना पड़ेगा। इसके बाद वह छात्रा को लेकर होटल के कमरे में गया। आरोप है कि कमरे में दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव प्रजापति ने बताया कि दुष्कर्म की धाराओं और एससी-एसटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उपायुक्त दक्षिणी केशव कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर एक आरोपित को हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

बिहार में मंत्री के फेसबुक की कविता पर दिनभर उबाल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● पटना

ग्रामीण कार्य मंत्री डा. अशोक चौधरी के फेसबुक पर री-पोस्ट की गई कविता से पैदा हुआ विवाद मंगलवार को दिनभर उबलकर शाम तक शांत हो गया। इस दौरान जदयू के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि यह कविता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्रीत है। कविता की चर्चा इतनी तेज हुई कि चौधरी मुख्यमंत्री निवास बुला लिए गए। वहां से निकले तो उन्होंने अपने फेसबुक पर मुख्यमंत्री के साथ वाला एक फोटो पोस्ट किया। लिखा-आज की तस्वीर। गीत का मुखड़ा भी लिखा-कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।

चौधरी ने मंगलवार को मार्निंग मोटिवेशन टैग के साथ एक कविता पोस्ट की। विवाद होने पर बताया कि यह कविता उनके मित्र की पत्नी की है। मित्र ने भेजा था। हमें अच्छी लगी। री-पोस्ट कर दी। कविता है -बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगें तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए.....। चौधरी ने कहा कि नीतीश और वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। बाकी लोगों की वे परवाह नहीं करते।

कविता पढ़ने के बाद कुछ पत्रकार जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार के पास पहुंचे। कहा कि फेसबुक की यह कविता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर इशारा करती है। नीरज ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर कोई छद्म रूप से प्रहार नहीं कर सकता है। सीधा प्रहार करे और जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे।

बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी द्वारा फेसबुक पर साझा किया गया चित्र, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके कंधों पर हाथ रखकर स्नेह जताते हुए दिख रहे हैं। एक्स @AshokChoudhaary

चौधरी गए मुख्यमंत्री निवास

इन्हीं चर्चाओं के बीच डा. अशोक चौधरी दोपहर मुख्यमंत्री निवास गए तो प्रचारित हुआ कि उन्हें तलब किया गया है। मुलाकात का विवरण चौधरी ने ही पत्रकारों को दिया। कहा कि वह प्रतिदिन मुख्यमंत्री निवास आते-जाते रहते हैं। उनके कहने का आशय यही था कि उनके मुख्यमंत्री निवास जाने से कविता प्रकरण का कोई संबंध नहीं है। जहां तक कविता का प्रश्न है, वह सामान्य है। उन बच्चों पर है, जो अभिभावक की बात नहीं मानते हैं।

2025 में फिर से नीतीश का लक्ष्य

डा. अशोक चौधरी ने कहा- नीतीश हमारे मानस पिता हैं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया। वे देश के पहले अनुसूचित जाति के नेता हैं जिन्हें बिना किसी सदन का सदस्य रहे दो बार मंत्री बनाया गया। दाएं-बाएं नहीं, हमारा लक्ष्य साफ है। 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ज्ञानी होते हैं। उन्हें कविता में मुख्यमंत्री के प्रति दूसरा भाव नजर आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

कोलकाता की सड़कों से विरासती ट्रामों को हटाने के निर्णय का कड़ा विरोध

कोलकाता के सड़कों पर दौड़ती ट्राम। फाइल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : कोलकाता की सड़कों से 150 वर्षों की विरासत वाली ट्रामों को हटाने के ममता सरकार के निर्णय का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। भाजपा व माकपा ने इसकी कड़ी आलोचना की है। कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन और पर्यावरणविद् भी इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। मालूम हो कि बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहशीष चक्रवर्ती ने कहा था कि धीमी गति के कारण एक रूट को छोड़कर बाकी सभी रूटों पर ट्राम सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। एस्प्लेनेड-खिदिरपुर रूट पर इसे ज्वायराइड के तौर पर चलाया जाएगा। मालूम हो कि कोलकाता देश का एकमात्र शहर है, जहां अभी भी ट्रामें चलती हैं। ट्रामों को बचाने के लिए हैशटैग अभियान भी शुरू किया है।

1873 में घोड़ागाड़ी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी

26 सितंबर को पांच ट्राम डिपो के सामने प्रदर्शन करेंगे कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन के सदस्य

1 ट्राम एक स्टेशन से निकलती है व 2 मिनट तक त्वरित होकर 12 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है।

'ट्राम कोलकाता की विरासत व पर्याय है। हम इसे बचाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने सरकारी परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। सरकारी बसें अब मुश्किल से नजर आती हैं। यह सरकार सबकुछ बंद कर देने की नीति में विश्वास करती है।'

- शमिक भट्टाचार्य, रास सदस्य, भाजपा

राज्य सरकार ट्राम डिपो की जमीन सिंडिकेट को बेचने की फिराक में है। 36 नंबर रूट पर ट्राम के ओवरहेड तार को वह पहले ही बेचकर खा चुकी है। सीयूटीए की ओर से ट्राम डिपो के घेराव की जो कार्यसूची है, पार्टी उसका समर्थन करेगी। बंगाल सरकार को कदम नहीं उठाने देगी।

- मोहम्मद सलीम, राज्य सचिव, माकपा

इस घोषणा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बिना किसी सर्वेक्षण व अध्ययन के यह निर्णय लिया गया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर सरकार ट्रैफिक जाम कम करने के प्रति गंभीर है तो वह अतिक्रमण हटा सकती है और सड़कें चौड़ी कर सकती है। ट्राम से प्रदूषण नहीं होता है। - देवाशीष भट्टाचार्य, अध्यक्ष, कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन

आनलाइन गेमिंग की नई सुबह पर सट्टेबाजी का साया

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली: आनलाइन सट्टेबाजी और जुए का विशाल कारोबार इकोनमी की एक उभरती सुबह पर ग्रहण लगा सकता है। दुनिया में सबसे अधिक गेमरों की संख्या, सबसे सस्ता इंटरनेट, तकनीक में महारत ने भारत को आनलाइन गेमिंग का सबसे बड़ा बाजार बनने का मौका दिया है, लेकिन सट्टेबाजी और जुए के खेल ने यूजर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के अलावा इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी गंभीर चुनौतियां पैदा की हैं। ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ अनुराग सक्सेना की चिंता यह है कि गेमिंग और जुए-सट्टेबाजी के बीच धुंधली रेखा के कारण लोगों को पता ही नहीं है कि वे गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी में फंस रहे हैं। अवैध सट्टेबाजी वाली देशी-विदेशी कंपनियां और वेबसाइटें जीरो जीएसटी, इनाम पर जीरो आयकर का लालच देती हैं और पहली बार गेमिंग की तरफ जा रहा व्यक्ति यह जान ही नहीं पाता है कि उन्हें जुए और सट्टेबाजी की ओर ले जाया जा रहा है। कई विदेशी अवैध प्लेटफार्म वर्चुअल फुटबाल, हाकी और ताइक्वांडो खेलने और उन पर दांव लगाने का अवसर भी दे रहे हैं।

इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे माध्यमों पर सैकड़ों लोग रोज इन सट्टेबाजी एप द्वारा ठगे जाने की शिकायत करते हैं। इनके लिए सुनवाई का कोई तंत्र नहीं है, क्योंकि अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों में समस्या निवारण का कोई मंच नहीं है। अनुराग सक्सेना कहते हैं 'प्रोफेशनल गेमर तो सट्टेबाजी और जुए वाले प्लेटफार्म से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके अवैध होने की जानकारी है, लेकिन आम लोगों के लिए किसी गेमिंग एप पर आइएसआइ मार्क या एफएसएसआइ का ठप्पा लगे होने जैसा कुछ नहीं है जिससे वे अंतर समझ सकें।' पूरे देश में चर्चित रहे महादेव एप घोटाले की जांच में सामने आया था कि शुरुआत में इस प्लेटफार्म से लोग लूडो, ताश, शतरंज और सांप-सीढ़ी जैसे गेमों के जरिये ही जुड़े थे और फिर इसी प्लेटफार्म पर सट्टेबाजी के जाल में फंस गए।

दूसरा उदाहरण तेलंगाना का है, जहां सरकार की ओर से कौशल वाले खेलों समेत समस्त आनलाइन गेमिंग पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के कारण अवैध सट्टेबाजी की बाढ़ आ गई। एक चीनी फर्म द्वारा संचालित 1,200 करोड़ रुपये का सट्टेबाजी और जुए का रैकेट पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि इस रैकेट के शिकार वे लोग भी हुए जो गेम खेलने की अपनी आदत के चलते सट्टेबाजी के जाल में फंस गए।

एशियाड में भारत के लिए ई-स्पोर्ट्स (कलेक्टिव कार्ड गेम हर्थस्टोन) में कांस्य पदक जीतने वाले तीर्थ मेहता कहते हैं 'ई-स्पोर्ट्स अवैध कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की एक बड़ी चुनौती है। अवैध कंपनियां टैक्स की बचत भी कर रही हैं और भारत से पैसे भी ले जा रही हैं। आनलाइन गेमिंग में अव्वल बनने के लिए सरकार को टैक्स ढांचे में सुधार के साथ एक मददगार नीति लानी होगी।'

आनलाइन गेमिंग में भारत का भविष्य

60 करोड़ कुल यूजर्स

9.5 अरब डाउनलोड हुए मोबाइल गेमिंग एप

89.3 करोड़ यूजर्स होने का अनुमान 2028 तक

38.4 लाख करोड़ व्यापार होने का अनुमान है 2034 तक

20% है आनलाइन गेम में भारत की हिस्सेदारी

आम लोग अवैध सट्टेबाजी और जुए वाले प्लेटफार्म के बारे में नहीं जानते। इसका समाधान आनलाइन गेमिंग की एक व्हाइट लिस्ट (वैध) बनाकर किया जा सकता है।

अनुराग सक्सेना, ई गेमिंग फेडरेशन के सीईओ

सट्टेबाजी एप के अवैध धंधे को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा की जरूरत है। सरकार को उन्हें भारतीय कानून मानने के लिए विवश करना होगा। तभी हम लोगों को इससे निजात दिला पाएंगे।

पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट

भारत की बढ़ती हनक

कुल कारोबार *(हजार करोड़ रुपये में)*

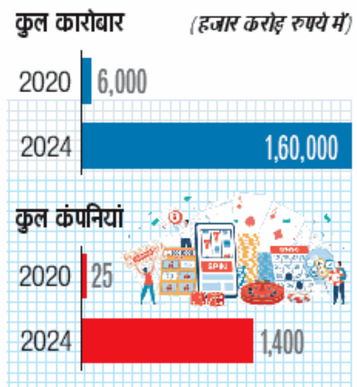

कुल कंपनियां

जानलेवा बनी आनलाइन गेम की लत

- इस साल मार्च में कर्नाटक में दर्शन बाबू नामक इंजीनियर की 23 साल की पत्नी ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि दर्शन बाबू को 2021 से आइपीएल से जुड़े आनलाइन गेम की लत लग गई थी और वह लगातार पैसा हार रहे थे। वे कर्ज में फंसते चले गए और उनके घर पर उधार वापस मांगने वालों का तांता लगा रहता था
- इस साल जुलाई में बेंगलुरु में ही रियल एस्टेट फर्म के 37 साल के मैनेजर ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आनलाइन गेमिंग में वह 65 लाख रुपए हार चुके थे।
- पुणे में एक किशोर ने आनलाइन गेमिंग में चक्कर में फ्लैट की बालकनी से कूदकर तो चेन्नई में आनलाइन गेम रमी में 24,000 के नुकसान की वजह से एक शख्स ने अपनी जान दे दी।

अंतर समझना जरूरी

एशियाड में भारत के लिए ई-स्पोर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाले **तीर्थ मेहता** कहते हैं 'ई-स्पोर्ट्स में भारत बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन लोगों को आनलाइन गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स और सट्टेबाजी का अंतर समझना चाहिए।'

2.5 लाख लोग कार्यरत होंगे भारत की गेमिंग इंडस्ट्री में अगले कुछ वर्षों में

भारत के शीर्ष गेमर्स

- नमन माथुर- @ig_mortal
- अनिमेश अग्रवाल- @8bit_thug
- मिथिलेश पाटणकर- @mythpat
- पायल धारे- @payal_is.everything
- अंशु बिष्ट- @gamerfleetog

में भारत बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि यहां इसे प्रोत्साहन मिलने की हर सुविधा उपलब्ध है। ओलिंपिक में भी इसके शामिल होने के आसार हैं। लेकिन लोगों को आनलाइन गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स और सट्टेबाजी का अंतर समझना चाहिए।' कंसलटेंसी फर्म रेड सियर की रिपोर्ट के मुताबिक आइपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान फैंटेसी गेमिंग प्लेटफार्मों पर छह करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। इनमें से 65 प्रतिशत छोटे शहरों और कस्बों के लोग हैं। स्पष्ट है, आनलाइन सट्टेबाजी का जोखिम एक बड़े सामाजिक खतरे की ओर बढ़ रहा है।

विंजो गेमिंग एप की सह-संस्थापक सौम्या सिंह राठौर कहती हैं,' आनलाइन गेमिंग की वैध कंपनियां भारत में 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी दे रही हैं और इस वजह से इन कंपनियों के समक्ष उन

सिपाही भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे तीन को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत

जागरण संवाददाता, रोहतास : बिहार में रोहतास के सोनी गांव के समीप मंगलवार की सुबह कर्मचारी चयन आयोग की कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए दौड़ का अभ्यास कर रहे तीन युवकों को ट्रक ने रौंद दिया। इसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतकों की पहचान दीपक व सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है। सत्येंद्र सोनी गांव में ही अपने नाना के घर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को आरा-सासाराम मार्ग पर रख जाम कर दिया। दो घंटे बाद मौके पर पहुंचकर बीडीओ व सीओ ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया, तब ग्रामीणों ने जाम हटाया। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक व सत्येंद्र लिखित परीक्षा में सफल हो गए थे। अगले माह ही शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी थी। इसके लिए वह प्रतिदिन सड़क किनारे दौड़ लगा रहे थे। उनके साथ कई अन्य युवक भी दौड़ रहे थे। विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने तीन युवकों को कुचल दिया।

न्यूज गैलरी

'स्कूल सुरक्षा पर दिशानिर्देश अधिसूचित करें राज्य'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे स्कूलों की सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को अधिसूचित करें। बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ की याचिका में अदालत से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 'स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश-2021' दिशानिर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने अदालत को बताया कि आज तक, केवल पांच राज्यों ने इनको अधिसूचित किया है। (प्रेट्र)

संभल में कुत्तों ने छह वर्षीय बच्चे को नोचकर मार डाला

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में आवारा कुत्तों के झुंड ने घर के पास बाग में खेल रहे छह वर्षीय शान मोहम्मद को बुरी तरह नोचकर मार डाला। चीखें सुनकर पड़ोसियों ने कुत्तों को भगाया। अस्पताल ले जाने तक उसकी मौत हो गई। मजदूरी करने वाले अशरफ अली का बेटा शान कक्षा तीन का छात्र था। बुखार की वजह से मंगलवार को उसे स्कूल नहीं भेजा था। मां अफशीन सात वर्षीय बेटी आयत को स्कूल छोड़ने गई थी। इसी बीच शान घर से निकलकर पड़ोस में आम के बाग में खेलने पहुंच गया। वहां पर कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। (जासं)

पेन नहीं देने पर सातवीं के छात्र को सहपाठी ने मारा चाकू

पश्चिमी चंपारण : बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के दुर्गाबाग मोहल्ला में मंगलवार की सुबह सातवीं में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र को सहपाठी ने चाकू मार गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पीठ पर दो जगह व दाहिने हाथ पर जख्म के निशान हैं। जख्मी छात्र का सरकारी अस्पताल में उपचार हो रहा है। दोनों एक निजी स्कूल के छात्र हैं। (जासं)

केंद्र ने कहा-इस हफ्ते न हो वैवाहिक दुष्कर्म केस की सुनवाई

नई दिल्ली : केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इस सप्ताह इस विवादास्पद कानूनी प्रश्न पर सुनवाई न की जाए कि क्या पति को दुष्कर्म के अपराध के लिए अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए अगर वह अपनी पत्नी, जो नाबालिग नहीं है, को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। इस आशय की दलील सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिन की कार्यवाही के अंत में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दी। (प्रेट्र)

हिमचाल के कुल्लू में नक्शे के अनुसार नहीं बनी मस्जिद, 30 को फिर प्रदर्शन

दविंद्र ठाकुर ● जागरण

कुल्लू: हिमाचल के कुल्लू में अखाड़ा बाजार स्थित मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठन 30 सितंबर को फिर से प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में ज्यादा लोग पहुंचें, इसके लिए देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारी लोगों से संपर्क साध रहे हैं। मंच का आरोप है कि अखाड़ा बाजार में मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है। मस्जिद का निर्माण नक्शे के अनुसार, नहीं किया गया है। देवभूमि जागरण मंच ने कुल्लू में 14 सितंबर को अखाड़ा बाजार मस्जिद के विरोध प्रदर्शन कर कुछ दूरी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर मस्जिद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय देते हुए भूमि की निशानदेही की मांग की थी।

मस्जिद की निशानदेही 27 को : जिला प्रशासन मस्जिद की भूमि की निशानदेही 27 सितंबर को करवाएगा। इसके बाद पता चलेगा कि यह जमीन किसकी है। उस दिन शुक्रवार है। मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं। ऐसे में प्रशासन पुलिस सुरक्षा में निशानदेही करवाएगा।

कुल्लू के अखाड़ा बाजार में श्रीराम गली में बनी जामा मस्जिद। जागरण

2000 में पास हुआ था नक्शा : कुल्लू के अखाड़ा बाजार में श्रीराम गली में जामा मस्जिद के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद ने 21 जून, 2017 को अवैध निर्माण की शिकायत की थी। मस्जिद का नक्शा टीसीपी विभाग ने 14 जुलाई, 2000 को पास किया था और दो साल में निर्माण की मंजूरी दी थी। नगर परिषद ने 23 जून, 2017 को निरीक्षण किया तो उस समय भी निर्माण कार्य जारी था। कार्य नक्शे के अनुसार नहीं पाया था। इस पर नगर परिषद ने 28 जून, 2017 को मस्जिद प्रबंधन को नोटिस जारी किया था। 2017 में पुलिस ने भी छानबीन की थी, जिसमें मौलवी ने बयान दिया था कि यह निर्माण कार्य 15 वर्ष पहले किया गया था। फिर देवभूमि जागरण मंच ने 29 नवंबर, 2017 को नगर परिषद को निर्माण कार्य बंद करवाने के लिए ज्ञापन दिया था।

30 सितंबर को देवभूमि जागरण मंच की ओर से हिंदू समाज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। धर्म जागरण यात्रा निकाली जाएगी। इस बार जिलाभर से लोग इस यात्रा में भाग लेंगे।

- क्षितिज सूद, अध्यक्ष देवभूमि जागरण मंच

मस्जिद की जांच को लेकर 27 सितंबर को निशानदेही की जाएगी। इसके बाद पता चलेगा कि यह भूमि किसकी है। अवैध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- विकास शुक्ला, एसडीएम कुल्लू

युवक को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांध जूतों से पीटा, महिला के कपड़े भी पहनाए

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान के बारां जिले में एक युवक को निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद उसे जूतों की माला पहनाकर महिलाओं के कपड़े भी पहनाए गए। आरोपितों में पीड़ित की पत्नी और उसके स्वजन ही शामिल है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को आरोपितों के कब्जे से छुड़वाया। पुलिस ने मामले में सोमवार को छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई पर आरोपितों के परिवार की एक महिला को अपने साथ जबरन ले जाने का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस को दिए बयान में खुद को बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है। मारपीट करने, निर्वस्त्र कर जूतों की माला और महिला के कपड़े पहनाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। मामले में 23 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज हुई है। सदर पुलिस थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़ित जगमोहन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसको मोबाइल पर फोन कर बुलाया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो आधा दर्जन लोगों ने उसे पकड़कर कपड़े फाड़ दिए।

छत्तीसगढ़ में एआइ की मदद से पकड़े जाएंगे फर्जी परीक्षार्थी

संदीप कुमार तिवारी ● नईदुनिया

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग किया जाएगा। इस प्रक्रिया में परीक्षा के दौरान लाइव वीडियो और फोटो के माध्यम से किसी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाले अन्य व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग और बायोमीट्रिक डिवाइस से उनका आनलाइन वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया जाएगा।

2021 की परीक्षा में भाई-भतीजावाद का आरोप लगने के बाद सीजीपीएससी ने यह तरीका अपनाया है। इसका प्रयोग परिवहन विभाग की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में एक सितंबर को 16 केंद्रों में किया जा चुका है, जो सफल रहा। इसके अलावा परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए सीजीपीएससी ने केंद्रीय कानून को अपनाने का निर्णय किया है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ गड़बड़ी करने के आरोप में सीबीआइ जांच चल रही है।

2021 की परीक्षा में गड़बड़ियां सामने आने के बाद आयोग ने लिया निर्णय

हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सीजीपीएससी की परीक्षा व्यवस्था यूपीएससी की तर्ज पर पूरी तरह से पारदर्शी हो। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री व मंत्री, तकनीकी शिक्षा

एआइ तकनीक से अभ्यर्थी के परीक्षा कक्ष में खींची गई तस्वीर और अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन के समय अपलोड की गई तस्वीर का 102 बिंदुओं को आधार बनाकर मिलान किया जाएगा। दोनों में अंतर मिलने पर खींची गई तस्वीर का देशभर में पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में शामिल पांच लाख अभ्यर्थियों की तस्वीर से मिलान किया जाएगा।

पंजाब-हरियाणा ने केंद्र को दिया भरोसा, नहीं जलने देंगे पराली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर पीएम के प्रधान सचिव ने राज्यों के साथ की बैठक
- पराली को जलने से रोकने सहित वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश

पंजाब में पराली जलने के मामले भले ही लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डा पीके मिश्रा की ओर से बुलाई गई बैठक में पंजाब और हरियाणा ने केंद्र को यह भरोसा दिया है कि वह पराली को नहीं जलने देंगे। दोनों राज्यों ने पराली प्रबंधन को लेकर अपनी कार्ययोजना भी केंद्र के साथ साझा की है। इसमें पंजाब ने 19.52 मिलियन टन और हरियाणा ने 8.10 मिलियन टन धान के भूसे के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हालांकि, इसके बाद भी प्रधान सचिव ने पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे पराली जलने सहित वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकने को कड़े कदम उठाएं।

दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर डा. मिश्रा की ओर से सोमवार शाम को बुलाई गई इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के मुख्य सचिव सहित दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आदि के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। देखना होगा कि इस बैठक में किए गए अपने वादों पर राज्य खरे उतरते हैं या फिर हर साल की तरह दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर होने वाली यह रूटीन बैठक ही बनकर रह जाएगी।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा ने अपनी तैयारियों को भी साझा किया। पंजाब ने पराली को खेतों में ही नष्ट करने के लिए करीब 25 हजार कस्टम हायरिंग सेंटरों के जरिये डेढ़ लाख से अधिक मशीनें मुहैया कराने की भी जानकारी दी है। वहीं, हरियाणा ने 6794 कस्टम हायरिंग सेंटरों के जरिये करीब 90 हजार मशीनों को मुहैया कराने की जानकारी दी।

पंजाब में पराली जलाने से दस दिन में चार गुना बढ़ा प्रदूषण

जागरण संवाददाता, पटियाला : पंजाब में 15 सितंबर से धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाने का क्रम तेजी से जारी है। स्थिति यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दस दिन में पराली जलाने के मामले करीब दस गुना अधिक हो गए हैं। वर्ष 2023 में 24 सितंबर तक पराली जलाने के मात्र आठ मामले थे, जबकि इस वर्ष दस गुना बढ़कर 81 हो गए हैं। इससे राज्य में प्रदूषण भी बढ़ा है। मात्र दस दिन में राज्य के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में करीब चार गुणा वृद्धि दर्ज की गई है।

पंजाब का मंडी गोबिंदगढ़ मंगलवार को सबसे प्रदूषित रहा। मंडी गोबिंदगढ़ का औसत एक्यूआइ 225 और अधिकतम एक्यूआइ 430 दर्ज किया गया। इससे पहले जब पराली नहीं जलाई जा रही थी तो 14 सितंबर को मंडी गोबिंदगढ़ का औसत एक्यूआइ 50 और अधिकतम एक्यूआइ 111 था। पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने के 12 मामले सामने आए। इन 12 मामलों में से चार अमृतसर, एक फिरोजपुर, चार कपूरथला और तीन मोहाली जिले से हैं।

कुशीनगर में नकली नोट, बम व असलहा के साथ दो सपा नेता समेत 10 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर

- उप्र-बिहार की सीमा पर फैलाया था जाल, भारत-नेपाल के नकली नोट, सिम, आधार, एटीएम कार्ड, आठ लैपटाप बरामद

कुशीनगर में गिरफ्तार तस्कर थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए। जागरण

नकली नोटों की तस्करी में लिप्त दो सपा नेताओं समेत 10 तस्करों को उत्तर प्रदेश की कुशीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास साढ़े पांच लाख से अधिक की नकली नोट, तीन हजार के नेपाली नोट, अवैध असलहे, कारतूस, सिम, आधार, एटीएम कार्ड, आठ लैपटाप व सुतली बम बरामद हुए हैं। तस्करों में शामिल मोहम्मद रफीक उर्फ बबलू खान सपा लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव तथा नौशाद खान सपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव है। गिरफ्तार औरंगजेब भी राजनीति में सक्रिय था। सपा जिलाध्यक्ष शुकरुल्लाह अंसारी ने बताया कि दोनों पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा फंसाया गया है।

एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि नकली नोटों के तस्करों की धरपकड़ के लिए सीमावर्ती थानों और साइबर सेल को जिम्मेदारी दी गई थी। शनिवार की देर रात छापेमारी कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर रविवार की रात सात और तस्करों को दबोचा गया। बिहार के सिवान का रहने वाला जितेंद्र यादव, गोपालगंज कुचायकोट का मनीष कुमार सिंह उर्फ छोटू, कमरुद्दीन व एक अज्ञात तस्कर फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

नेपाल के रास्ते जाली नोटों की तस्करी : पुलिस के अनुसार रफीक नेपाल के रास्ते जाली नोटों की तस्करी करा रहा था। औरंगजेब वर्ष 2005 में फर्जी प्रमाण-पत्र पर पंचायत मित्र बन गया था, जिसे बाद में जांच के बाद निकाल दिया गया।

चिंता की बात

खेत से बाजार तक धान क्षति, रबी की बुआई में भी विलंब तय, अक्टूबर मध्य तक भी बारिश होती रही तो खेतों में पानी जमा होने से रबी फसलों की बुआई भी प्रभावित हो सकती है

अगैती फसलों पर आफत बरसाकर वापस जा रहा मानसून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के पश्चिमी हिस्से से मानसून की वापसी प्रारंभ हो गई है। इस बार सामान्य से छह प्रतिशत ज्यादा बारिश के साथ देर से लौटते मानसून के चलते बिहार, झारखंड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पछैती फसलों को तो फायदा होगा, किंतु उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में पककर तैयार अगैती फसलों को क्षति होने लगी है। पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की फसल तैयार है। अधिक बारिश से खेतों में खड़ी फसल गिर सकती है। मानक से ज्यादा नमी से मंडियों में बिक्री में परेशानी हो सकती है। खेतों के अधिक गीला होने से दलहन एवं तिलहन फसलों की बुआई में भी देरी होगी। अरहर और उड़द को क्षति पहुंचना तय है। मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र में सोयाबीन

प्रतीकात्मक।

भी चपेट में आ सकती है।

देश में जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा सामान्य का आंकड़ा पार कर चुकी है, हालांकि इसका वितरण सामान्य नहीं रहा। बिहार-छत्तीसगढ़ समेत देश के कुछ हिस्सों में कम तो राजस्थान-गुजरात समेत दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई। कई राज्य बाढ़ प्रभावित हैं। बिहार-पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई-अगस्त में धान की रोपाई के बाद अभी पानी की जरूरत है। पौधों में बालियां आने लगी हैं। तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो खड़ी फसल गिर सकती है और उत्पादन दर में कमी आ सकती है। जून-जुलाई में लगाई गई कपास, सोयाबीन, मक्का एवं दलहन की फसल भी लगभग तैयार है, परंतु जहां-तहां अत्यधिक बारिश की चपेट में आ रही है। अगर अगले तीन हफ्ते तक बारिश जारी रही, तो गेहूं, मसूर, सरसों एवं चना बोने में भी विलंब संभव है। अक्टूबर मध्य तक भी बारिश होती रही तो खेतों में पानी जमा होने से रबी फसलों की बुआई भी प्रभावित हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग राजस्थान-गुजरात से मानसून की वापसी का अनुमान जारी कर चुका है। पंजाब-हरियाणा के कुछ हिस्सों को भी वर्षा से निजात मिल चुकी है। हालांकि दिल्ली में अभी वर्षा की स्थितियां बनी हुई हैं। दिल्ली से मानसून वापसी की अनुमानित तिथि 23 सितंबर होती है, लेकिन इस बार हफ्ते भर विलंब से वापसी होगी। पूरे देश से अक्टूबर मध्य तक पूर्ण विदाई का अनुमान है।

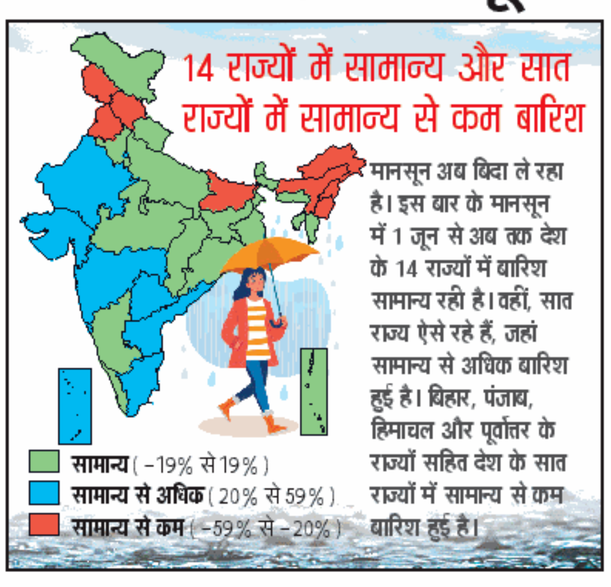

****

नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने आटो को रौंदा, आठ की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह

- मप्र में दमोह जिले का मामला
- दो घायलों की स्थिति गंभीर

मध्य प्रदेश में दमोह जिले के समन्ना गांव के पास मंगलवार दोपहर दो बजे नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने सवारियों से भरे आटो को पीछे से टक्कर मारकर रौंद दिया। हादसे में आटो सवार आठ लोगों की मौत हो गई। दो गंभीर घायलों को कारिडोर बनाकर जबलपुर के मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वाले और घायल रिश्तेदार हैं।

चाट का ठेला लगाकर जीवन-यापन करने वाला राकेश गुप्ता का परिवार दमोह शहर के शोभा नगर में रहता था। परिवार व रिश्तेदार के 10 सदस्य आटो में सवार होकर दमोह से 18 किमी दूर बांदकपुर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी के अनुसार छतरपुर के बकस्वाहा निवासी ट्रक ड्राइवर नीरज सिंह लोधी शराब के नशे में धुत होकर तेज गति से ट्रक चला रहा था। उसने आटो को रौंद दिया। सूचना मिलने पर कलेक्टर सुधीर कोचर एवं वह पहुंचे और ट्रक की चपेट में आए आटो को क्रेन से निकलवाया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मरने वालों के स्वजन को दो-दो लाख और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की है। साथ ही जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार बड़े आटो में अधिकतम पांच सवारियां की बैठाई जा सकती हैं, जबकि दुर्घटनाग्रस्त आटो में 10 सवारियां थीं। आटो की फिटनेस-बीमा की जानकारी संकलित कराई जा रही है।

209 आपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में सात वर्षों में अब तक। इनमें 163 इनामी बदमाश थे, 46 बदमाश ऐसे थे, जिन पर इनाम घोषित नहीं था।

न्यूज गैलरी

सुकमा में दो नक्सलियों के मारे जाने का दावा

सुकमा : छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार रात सुरक्षा बल के जवानों पर चिंतावागू नदी के किनारे नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग में दो नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, शव बरामद नहीं हुए हैं। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार जवानों को सोमवार रात को आपरेशन के लिए करकनगुड़ा इलाके में भेजा गया था। चिंतावागू नदी के किनारे करीब 40-50 नक्सलियों ने अत्याधुनिक हथियारों से जवानों पर हमला कर दिया। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और दो नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बल के सभी जवान सुरक्षित कैंप लौट आए हैं। (नईदुनिया न्यूज)

पुलवामा आतंकी हमले के आरोपित की अस्पताल में मौत

जम्मू : कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों पर हुए आत्मघाती हमले के एक आरोपित की जम्मू जीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। आरोपित बिलाल अहमद कूचे जो काकापोरा हाजीबल कश्मीर का रहने वाला था। वह उन 19 आरोपितों में शामिल था, जिनका नाम इस हमले के दौरान एनआइए द्वारा आरोप पत्र में है। बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ कर्मियों के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 40 सीआरपीएफकर्मी बलिदान हो गए थे। जबकि आठ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बिलाल अहमद कूचे किश्तवाड़ की जेल में बंद था। बीते कुछ दिन से उसकी तबीयत खराब थी, उसे 17 सितंबर से जम्मू जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। (जासं)

आंध्र में मंदिर का रथ जलाए जाने के आरोप में पांच पकड़े

अनंतपुर : आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मंगलवार सुबह अज्ञात लोगों ने हनुमान मंदिर के रथ को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है। अनंतपुर के एसपी ने बताया कि घटना सांप्रदायिक नहीं है बल्कि एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच झगड़े का परिणाम है। पुलिस के अनुसार, इस रथ को सार्वजनिक स्थान पर रखने को लेकर विवाद हो गया और दानकर्ताओं को इसे अपने घर में रखने को कहा गया था। बातचीत के बाद रथ को खड़ा करने के लिए एक शेड बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन मंगलवार सुबह अज्ञात व्यक्तियों ने रथ में आग लगा दी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना को संज्ञान लेते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। (प्रेट्र)

इसलिए योगी ने दिखाया कड़ा रुख

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

गाजियाबाद के लोनी में दुकानदार आमिर जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था। शामली में एक ठेला दुकानदार का जूस में थूक मिलाते वीडियो प्रसारित हुआ था। गाजियाबाद के ही एक रेस्तरां में रोटी में कारकोच मिलने की घटना सामने आई थी।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखना किया था अनिवार्य : योगी सरकार ने इससे पहले सावन माह की शुरुआत में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों, रेस्तरां और ढाबों के साथ ही ठेले पर संचालकों का नाम लिखना अनिवार्य किया था। हालांकि, इस निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

इस तरह किया गुमराह

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

आवेदन प्रक्रिया को सरल करते हुए आवेदकों से सीमित जानकारी मांगी गई थी। आवेदकों ने सूचना बदलकर या छिपाकर दस्तावेज जमा किए। महिला ने पति की जगह पिता का नाम दिया। कंपनी के नाम पर हुए आवेदन में भी आवेदकों के नामों में मामूली बदलाव या फिर नाम के आगे पीछे शब्द जोड़कर या हटाकर और स्पेलिंग में बदलाव मिला है। इस मामले में प्राधिकरणकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उप्र में एक और मुठभेड़, सिपाहियों का हत्यारोपित ढेर

गाजीपुर में हुए एनकाउंटर में जीआरपी व एसटीएफ के जवान भी घायल

दिलदारनगर-जमानियां के बीच ट्रेन में शराब चढ़ाने की फिराक में था तस्कर

जागरण संवाददाता, गाजीपुर

गाजीपुर : मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू (फाइल फोटो)। स्रोत : एसटीएफ

मामा का आरोप, तीन दिन पहले उठाया था जाहिद को : जाहिद के चचेरे मामा असगर अली ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने भांजे को तीन दिन पहले ही गांव से उठा लिया था। पहले उसे यातना दी और इसके बाद फर्जी मुठभेड़ में मार दिया।

भाई को घर से ले गई पुलिस : जाहिद की मौत के बाद उप्र पुलिस की एक टीम मंगलवार को उसके घर फुलवारीशरीफ पहुंची। वहां स्थानीय पुलिस के साथ जाहिद के पिता मुस्ताक के मंसूर मोहल्ला स्थित घर पर दबिश दी और जाहिद के छोटे भाई पिंटू को साथ लेकर गर्दनीबाग थाना पहुंची। उसे लाने का कारण जाहिद की शिनाख्त बताया जा रहा है।

सुलतानपुर डकैती मामले में वांछित एक लाख रुपये के इनामी को उन्नाव में सोमवार तड़के मुठभेड़ में ढेर करने के 24 घंटे के भीतर ही गाजीपुर जिले के गोपालपुर में एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ एक और एनकाउंटर किया। दो आरपीएफ जवानों की हत्या में मुख्य आरोपित एक लाख के इनामी शराब तस्कर मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू को सोमवार की देर रात मुठभेड़ में मार गिराया। इस कार्रवाई में जीआरपी और एसटीएफ के एक-एक जवान भी गोली लगने से घायल हो गए। एसपी डा. ईरज राजा ने बताया कि पटना (बिहार) निवासी जाहिद के खिलाफ अलग-अलग जगह अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के चार मुकदमे दर्ज हैं।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तैनात आरपीएफ जवान गाजीपुर निवासी जावेद खान और बिहार के भोजपुर निवासी प्रमोद कुमार 19 अगस्त की रात बिहार के मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए बाड़मेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुए थे। रास्ते में चेनपुलिंग कर ट्रेन में शराब चढ़ा रहे तस्करों को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। तस्करों ने दोनों को बुरी तरह पिटाई करने के बाद चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। जिले के बक्सिया के पास दोनों के शव अर्धनग्न अवस्था में रेल पटरियों के पास मिले थे। इस मामले में एसटीएफ ने 28 अगस्त को पटना से शराब तस्कर गिरोह के सरगना व रेलवे कर्मचारी बिलेंद्र पासी को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पटना में ही मुठभेड़ के बाद चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद दो और आरोपित पकड़े गए। फरार चल रहे जाहिद पर एडीजी जोन वाराणसी ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। एसपी ने बताया कि जाहिद सोमवार रात गाजीपुर जिले के दिलदारनगर व जमनियां के बीच ट्रेन में शराब चढ़ाने की फिराक में था। नोएडा एसटीएफ, जीआरपी, दिलदारनगर थाने की पुलिस गोपालपुर पहुंची। पुलिस को देखते ही जाहिद और उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। जीआरपी जवान अनिल कुमार व एसटीएफ के मुख्य आरक्षी सुनील कुमार तिवारी गोली लगने से घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल होकर जाहिद गिर गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। अस्पताल ले जाने पर डाक्टर ने जाहिद को मृत घोषित कर दिया।

एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति के बीच 'ठंडे' हो रहे बदमाश

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश किस जाति का था? इन दिनों एनकाउंटर के बाद पुलिस को इस सवाल का सामना सबसे पहले करना पड़ रहा है। सुलतानपुर डकैती में शामिल रहे आरोपित मंगेश यादव के पांच सितंबर को मारे जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति देखकर जान लिए जाने का बयान देकर राजनीति गरमा दी थी। पक्ष-विपक्ष के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग भी तेज है और इसके बीच पुलिस कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। सुलतानपुर डकैती का आरोपित अनुज प्रताप सिंह सोमवार सुबह पुलिस की गोली लगने से ढेर हुआ और रात में गाजीपुर में दो सिपाहियों की हत्या की संगीन वारदात में शामिल रहा मु.जाहिद भी मारा गया। इस वर्ष अब तक 15 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। पूर्व आइपीएस अधिकारी आरकेएस राठौर कहते हैं कि 'हर पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच होती है। एनकाउंटर पुलिस व बदमाशों के बीच एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे बदमाशों में पुलिस की दहशत बढ़ती है तो आम लोगों में गुंडों का भय कम होता है।'

▸ पुलिस मुठभेड़ में पांच वर्ष पहले मारे गए थे सर्वाधिक 41 अपराधी, इस वर्ष अब तक 15 कुख्यात मारे गए

पुलिस आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2012 से 2017 के मध्य पुलिस मुठभेड़ में 34 अपराधी मारे गए थे। बीते सात वर्षों में अब तक कुल 209 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनमें 163 इनामी बदमाश हैं। 46 बदमाश ऐसे थे, जिन पर इनाम घोषित नहीं था।

मारे गए बदमाशों में पांच लाख का इनामी हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे, प्रयागराज में दिनदहाड़े उमेश पाल की हत्या में शामिल माफिया अतीक अहमद (अब मृत) का बेटा असद, कुख्यात अंशू दीक्षित, पांच लाख का इनामी दस्यु गौरी यादव व अन्य कुख्यातों के नाम शामिल हैं। पांच वर्ष पूर्व 2018 में सर्वाधिक 41 बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हुए थे।

विपक्ष के सवाल के बाद सीआइडी को सौंपी गई बदलापुर मुठभेड़ की जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण, मुंबई : विपक्षी दलों के सवाल उठाने के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपित की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत की जांच सीआइडी को सौंप दी गई है। ठाणे पुलिस ने सीआइडी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। इस बीच सीआइडी जांच पर भरोसा न करते हुए आरोपित के पिता अन्ना शिंदे ने बांबे हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने बेटे की मौत की विशेष जांच टीम (एसआइटी) से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट से जांच की निगरानी करने का भी अनुरोध किया है। सोमवार शाम को पुलिस वैन में हुई मुठभेड़ में यौन उत्पीड़न का आरोपित अक्षय शिंदे मारा गया था। उस पर इसी स्कूल में तीन और चार वर्ष की दो मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोपित को सोमवार शाम उसकी दूसरी पत्नी द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने एक कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी।

त्रिपुरा में 500 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

आत्मसमर्पण समारोह में बैठे एनएलएफटी और एटीटीएफ से जुड़े पूर्व उग्रवादी। प्रेट्र

अगरतला, प्रेट्र : त्रिपुरा में मंगलवार को प्रतिबंधित समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) से जुड़े करीब 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री माणिक साहा के सामने आत्मसमर्पण किया है। सिपाहिजाला के जम्पुइजाला में एक समारोह में उग्रवादियों का मुख्यधारा में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उग्रवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस सामूहिक आत्मसमर्पण के बाद मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया। सीएम साहा ने कहा, केंद्र और राज्य कई योजनाएं शुरू करके स्वदेशी लोगों के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 500 एनएलएफटी और एटीटीएफ उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और बाकी कैडर आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे।

हाई कोर्ट को सीबीआइ जांच सौंपने का अधिकार, पर कारण बताना जरूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो किसी मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दे, लेकिन उसे यह तर्क देना होगा कि क्यों राज्य पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं थी। अदालत ने यह टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद करते हुए की, जिसमें सीबीआइ को गोरखा प्रादेशिक प्रशासन में स्वैच्छिक शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण से संबंधित मामले में कुछ पत्रों में लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश से पता चला कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि राज्य की जांच क्यों अनुचित है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपने का अधिकार है। हालांकि, तर्क देना जरूरी है। शीर्ष अदालत बंगाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार कर दिया था।

हाथरस में कक्षा दो के छात्र की गला दबाकर हत्या, अंग्रेजी के शिक्षक पर शक

जागरण संवाददाता, हाथरस

उत्तर प्रदेश के हाथरस में डीएल पब्लिक आवासीय विद्यालय में सोमवार को कक्षा दो के छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अंग्रेजी का शिक्षक शक के दायरे में है। वह उस रात बच्चे के कमरे में ही सोया था। पुलिस के सामने बार-बार बयान बदल रहा है।

मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने प्रबंधक दिनेश बघेल, प्रधानाचार्य और तीन शिक्षकों की हिरासत में लेकर पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि योजनाबद्ध तरीके से वारदात की गई है। छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार निकाल दिए गए थे। हत्यारे का पता न लगने से गुस्साए लोगों ने मंगलवार को कोतवाली पर हंगामा किया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने बताया कि विद्यालय की मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पांचवीं कक्षा तक की मान्यता पर आठवीं तक कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। विद्यालय में छात्रावास की मान्यता भी नहीं है। नोएडा में साफ्टवेयर इंजीनियर श्रीकृष्ण का बेटा कक्षा दो का छात्र था। वह स्कूल परिसर में बने छात्रावास में ही रहता था। सोमवार सुबह जब वह छात्रावास से नीचे नहीं आया तो योग शिक्षक उसे बुलाने के लिए ऊपर गए। वहां वह अचेत अवस्था में पड़ा था। प्रबंधक दिनेश बघेल उसको उपचार के लिए आगरा ले गए। वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई। प्रबंधक की नामजद करते हुए चार अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। छात्रावास में कुल 24 बच्चे थे। किसी ने कुछ देखा नहीं। छात्र के गले में रस्सी बांधी होने की बात भी कही जा रही है। मंगलवार सुबह विद्यालय में सन्नाटा था।

पुलिस ने प्रबंधक दिनेश बघेल, प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह, हिंदी के शिक्षक वीरपाल सिंह, कंप्यूटर आपरेटर गोपाल और अंग्रेजी के शिक्षक राम प्रकाश सोलंकी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वारदात वाली रात रामप्रकाश सोलंकी हास्टल में बच्चों के साथ कमरे में सोया था। हत्या के समय बच्चे को पेशाब निकल गया था। सीओ हिमांशु माथुर का कहना है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

▸ प्रबंधक और प्रधानाचार्य समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज, सभी से पूछताछ

▸ जांच में सीसीटीवी कैमरे के तार निकले मिले, रद होगी स्कूल की मान्यता

प्रतीकात्मक

ट्रेनों में तोड़फोड़ और पलटाने की साजिश होगी नाकाम : अश्विनी वैष्णव

जागरण संवाददाता, जयपुर

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार रेल की सुरक्षा के मामलों को गंभीरता से लेती है। ट्रेनों में तोड़फोड़ और उन्हें पलटाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। यह हमारा संकल्प है। रेलवे ट्रेनों में तोड़फोड़ की संभावित कोशिशों को लेकर भी सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई राज्यों में प्रशासन एवं पुलिस के साथ बातचीत की जा रही है। यह जानकारी उन्होंने मंगलवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, राज्य सरकारों और एनआइए के साथ लगातार संपर्क में हैं। रेलवे की सुरक्षा कवच 4.0 प्रणाली से हादसों में कमी आएगी। राजस्थान में सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब सुरक्षा कवच से लैस हो गया है। उन्होंने सुरक्षा कवच के निरीक्षण के लिए सवाईमाधोपुर से सुमेरगंज मंडी कोटा तक ट्रेन के लोको में सफर भी किया। सुरक्षा कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 एक अस्थाई व्यवस्था थी जो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब इसके वापस लागू होने की कोई संभावना नहीं है। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद -370 हटाया गया है। अब विपक्षी दल चाहे कितना ही भ्रम फैलाएं यह फिर से लागू नहीं होगा। विपक्ष की बातों पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है। भाजपा और एनडीए की सरकार के प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर में भारत के संविधान के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। जनता में उत्साह है। पहले चरण में मतदाता बढ़-चढ़कर मतदान के लिए आगे आए हैं।

रेल मंत्री ने सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच ट्रेन में सफर कर किया सुरक्षा कवच का निरीक्षण

जयपुर में मंगलवार को गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

ट्रेन के आगे घुमावदार ट्रैक और नेटवर्क विहीन स्थान पर लगाए थे डेटोनेटर

मनीष करे, नईदुनिया, खंडवा : मध्य प्रदेश में खंडवा-भुसावल रेल खंड पर बुरहानपुर जिले के सागफाटा के निकट सेना की ट्रेन के आगे आरोपित गैंगमैन साबिर द्वारा डेटोनेटर लगाने की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, मामला गंभीर षड्यंत्र की ओर जाता दिख रहा है। साबिर द्वारा डेटोनेटर लगाने के लिए चुनी गई जगह का अधिकारी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। डेटोनेटर जहां लगाए गए, वहां पटरी घुमावदार होने से ट्रैक में एक तरफ झुकाव है। साथ ही वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिलता। ऐसे में वह स्थान ऐसा ब्लैक स्पाट है, जहां ट्रेन डिरेल होने का खतरा अधिक रहता है। मोबाइल नेटवर्कविहीन स्थान होने से हादसे की सूचना मिलने व राहत और बचाव कार्य में भी अधिक देरी हो सकती थी।

18 सितंबर की घटना की जांच के लिए रेलवे के आलाधिकारियों के अलावा आइबी, एनआइए और एटीएस के एक दर्जन से अधिक अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। आरपीएफ के डिवीजन कमांडेंट भुसावल प्रत्येक गतिविधि पर सीधी नजर रखे हुए हैं।

तमिलनाडु में हिज्ब-उत-तहरीर के 11 ठिकानों पर एनआइए का छापा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मंगलवार को तमिलनाडु में 11 स्थानों पर छापेमारी की। मामला इस्लामिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) के "चुनाव विरोधी अभियान" से जुड़ा है।

एनआइए ने चेन्नई, तांबरम और कन्याकुमारी जिलों में 11 संदिग्धों के घरों पर छापा मारकर एचयूटी के डिजिटल उपकरण, बेहिसाब नकदी और साहित्य समेत आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। यह तलाशी एचयूटी द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिये असंतोष फैलाने और चुनाव विरोधी अभियान चलाने के मामले में की गई।

एनआइए की जांच में पता चला है कि एचयूटी एक कट्टरपंथी संगठन है। यह उल्टे-सीधे काम करके लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए अपने अनुयायियों को भड़काने में जुटा है। इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता हमीद हुसैन है। इसमें पांच अन्य आरोपितों के साथ मिलकर हिज्ब-उत-तहरीर की भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ाने के साथ देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में बाधा डालने के लिए पूरे तमिलनाडु में गुप्त बैठकें व गतिविधियां कीं। एनआइए ने इस जुलाई में चेन्नई सिटी पुलिस से मामला अपने हाथ में लिया था।

आतंकी फंडिंग में दो के खिलाफ आरोपपत्र दायर : एनआइए ने मंगलवार को आइएस कट्टरपंथी अब्दुल मथीन अहमद ताहा उर्फ ताहा और मुस्साविर हुसैन शाजिब उर्फ शाजिब के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इन पर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के बीच आतंकी फंडिंग और मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। एजेंसी ने रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में भी इनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। एनआइए के अनुसार कर्नाटक के शिवमोग्गा निवासी, दोनों व्यक्ति भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने में लगे हुए थे।

▸ चुनाव विरोधी अभियान के जरिये असंतोष फैलाने में जुटा था संगठन

▸ शिवमोग्गा में दो आरोपितों के खिलाफ एनआइए का आरोपपत्र दायर

जागरण विशेष

सिल्क सिटी भागलपुर में जूट से नवाचार, खोज लिया विदेश में बाजार

भागलपुर के लिम्स एंड डिजाइंस स्टार्टअप ने जूट से उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में किए प्रयोग, बना सिल्क सिटी के अर्थतंत्र का नया साथी

ललन तिवारी • जागरण

भागलपुर : भागलपुर के जूट का नवाचार देश-दुनिया में दम दिखा रहा है। भारत के साथ ही विदेश में भी बेबी कैरियर के लिए जूट की खासी मांग है। अमेरिका, इंग्लैंड, फिलिपींस, जर्मनी और पोलैंड आदि देशों को निर्यात के माध्यम से वर्तमान में यह भागलपुर के अर्थतंत्र का साथी बन गया है। आम तौर पर जूट की पहचान खुरदरा धागा से बने उत्पाद के रूप में की जाती है, लेकिन नई विधि, नई कार्य पद्धति और नई तकनीक के सहारे इस जूट से मुलायम और चटख रंगों में खूबसूरत गुणवत्तापूर्ण कपड़े भागलपुर का स्टार्टअप बना रहा है। इन धागों/कपड़ों की बड़ी मांग विदेश के बाजारों से आ रही है। इन देशों में जूट से मुख्य रूप से बेबी कैरियर बनाए जाते हैं। देशी जूट के इन थैलों में विदेश में नौनिहालों की किलकारी गूंजती है।

जूट के कपड़े से बने बेबी कैरियर संग अमेरिकी ग्राहक • स्टार्टअप

बेबी कैरियर की बढ़ रही मांग

आधुनिक दौर में बच्चों को बेबी कैरियर में रखने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह माता-पिता के लिए अपने बच्चे के साथ सैर-सपाटे, घूमने का सुरक्षित और व्यावहारिक कपड़े का एक थैला है। विदेशों में प्रायः माता-पिता अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को बेबी कैरियर, स्लिंग कैरियर में लेने जाने से उन्हें अपने हाथों को खाली रखने का फायदा मिलता है। भारत से बेबी कैरियर का आयात करने वाले मुख्य देशों में अमेरिका, यूके, फिलिपींस, जर्मनी, पोलैंड शामिल हैं। बेबी कैरियर या इसके कपड़े देश-विदेश के ग्राहक सीधा आर्डर कर स्टार्टअप से खरीदते हैं।

जूट से बेबी कैरियर के लिए तैयार कपड़े के साथ लिम्स एंड डिजाइंस स्टार्टअप के संस्थापक भागलपुर के योगेंद्र प्रसाद व उनकी पत्नी अनिता • जागरण

इस तरह काम कर रहा नवाचार : लिम्स एंड डिजाइंस नाम के स्टार्टअप ने पारंपरिक जूट की उत्पाद प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव किए हैं। इससे जूट के धागे और कपड़े का निर्माण-उत्पादन बहुरंगी हो गया है। नया उत्पाद क्वालिटी में भी पहले से बेहतर हो गया है। इस स्टार्टअप के संस्थापक और व्यवसायी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह निर्यात के लिए विशेष तौर पर जूट यार्न, जूट एंजिलिना, जूट स्टेलिना युक्त कपड़े का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही खास उत्पाद के तौर पर बेबी सीलिंग कैरियर भी बनाया जा रहा है। इसकी देश में कम, लेकिन दुनियाभर में काफी मांग है। भागलपुर के फरका गांव निवासी नवाचारी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि वे लंबे समय तक दिल्ली में रहकर जूट उत्पाद के निर्यात से जुड़े रहे। मगर मांग बढ़ने पर अपने गांव का रुख कर लिया। यहां पत्नी अनिता के साथ लिम्स एंड डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली है।

> इनक्यूबेशन सेंटर में जूट आधारित नवाचार को तराशा जा रहा है। निर्यात के लिए यह स्टार्टअप वरदान बन रहा है। जूट से बड़े पैमाने पर कपड़ा निर्माण होने से जूट की खेती का विस्तार होगा। इसके अलावा जैसे-जैसे यह नवाचार समृद्ध होगा, क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
>
> डा. डीआर सिंह, कुलपति, बीएयू

जूट की खेती को मिलेगा व्यापक बाजार : बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सबएग्रीस इनक्यूबेशन सेंटर में नवोन्मेषी के रूप में चयनित होने के बाद इस नवाचार को उत्कृष्ट बनाने के लिए कई उपयोगी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इनक्यूबेशन सेंटर के नोडल पदाधिकारी सह अनुसंधान निदेशक डा. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस नवाचार से जूट की खेती को व्यापक बाजार मिलेगा। इस उद्योग को उन्नत बनाने में जो कुछ कमी रह गई है, उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पर पूरा जोर दिया जा रहा है। नवाचार को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, जिससे गांव में आटोमेटिक मशीन लगाकर जूट का धागा, कपड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाएगा। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सीबीआइ जांच की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले की जांच सीबीआइ को स्थानांतरित करने के आदेश को रद कर दिया था। यह मामला फरवरी 2018 में, जिसमें दो राजनीतिक दलों सीपीआइ (एम) और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के कारण शुहैब नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ शुहैब के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। घटना 2018 में हुई थी और अब, जांच पूरी हो गई है और राज्य पुलिस ने पहले ही कई लोगों को आरोपित बनाते हुए आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पीठ ने कहा कि इस समय मामले में हस्तक्षेप करना अविवेकपूर्ण होगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 25 सितंबर, 2024

दैनिक जागरण

क्षमा दान ही अपने मन को शांत करने की औषधि है

जलने लगी पराली

अभी मानसून की विदाई ही हुई है, लेकिन पंजाब में फसलों के अवशेष यानी पराली जलनी शुरू हो गई। यह इसलिए अनपेक्षित है, क्योंकि आम तौर पर पंजाब में अक्टूबर के पहले सप्ताह से पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है। यह ठीक है कि पंजाब में पराली जलाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से स्पष्टीकरण भी मांग लिया, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि उसे कोई संतोषजनक जवाब मिल सकेगा और पंजाब में पराली जलाने के सिलसिले को थामा जा सकेगा। पंजाब में पराली जलाए जाने से यही पता चलता है कि अभी तक वहां ऐसे प्रबंध नहीं किए जा सके हैं कि किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने पड़ें और यदि वे ऐसा करें तो उन्हें इससे रोका जा सके। यह निराशाजनक है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि में पराली को जलाने से रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं, लेकिन वे प्रभावी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। चिंताजनक यह है कि इन राज्यों की देखादेखी अन्य राज्यों में भी पराली जलाई जाने लगी है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, क्योंकि किसानों के समक्ष ऐसे उपाय पेश नहीं किए जा सके हैं, जिससे उन्हें पराली न जलानी पड़े।

चूंकि पंजाब, हरियाणा आदि में पराली जलाए जाने से उठने वाला धुआं देश की राजधानी में वायु की गुणवत्ता को कहीं अधिक प्रभावित करता है, इसलिए केंद्र सरकार भी सक्रियता दिखाती है और सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सर्दियों में दिल्ली समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाता है और वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा करता है। हैरानी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि लगता नहीं कि सभी राज्यों ने ऐसे प्रबंध कर लिए हैं, जिससे पराली न जले। यह ध्यान रहे कि सर्दियों में वायु की गुणवत्ता केवल पराली जलाए जाने से ही प्रभावित नहीं होती। इसके अतिरिक्त वह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, वाहनों के उत्सर्जन और कूड़ा-करकट जलाने से भी प्रभावित होती है। अच्छा होगा कि प्रदूषण रोधी एजेंसियां पराली को जलाए जाने से रोकने के अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारणों का भी निवारण करें। निःसंदेह सुप्रीम कोर्ट को भी इस ओर ध्यान देना होगा। उसे दिल्ली के साथ शेष देश के पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी।

इस क्रम में यह भी समझना होगा कि यदि वायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियां आने पर ही की जाएगी तो अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सकते। वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी वर्ष भर करनी होगी, क्योंकि अब बरसात को छोड़कर देश के बड़े हिस्से वायु की खराब गुणवत्ता से जूझते रहते हैं। वायु प्रदूषण केवल जनजीवन पर ही बुरा असर नहीं डालता, बल्कि वह देश की छवि भी मलिन करता है।

सुरक्षित सफर की चुनौती

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मामले में देर से सही परिवहन विभाग और पुलिस की नींद टूटती दिख रही है। इन विभागों को अब समझ आ रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए सभी श्रेणियों के मार्गों का सुरक्षा आडिट जरूरी है। कहा जा रहा है कि इन पर दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा। यह बात भी विभागों में तब समझ आई, जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में पेच कसे। विभागों से दुर्घटनाओं के संबंध में मार्गवार विवरण जुटाने को कहा गया है। कहां-कहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और इनकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन कराया जा रहा है। यह ठीक है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद परिवहन और पुलिस विभाग ने इस दिशा में नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन मूल प्रश्न अपनी जगह बना हुआ है कि विभागों ने इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रही हैं। पिछले आठ महीने के अंतराल में राज्य में तकरीबन आठ सौ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दो सालों की तुलना में यह पच्चीस फीसद अधिक है। इनमें कुछ दुर्घटनाएं तो चालकों की लापरवाही के कारण हुई हैं, पर बड़ा आंकड़ा उनका भी है जिनकी वजह सड़कों की तकनीकी खामी रही है। ऐसे स्थल ब्लैक स्पाट की श्रेणी में रखे गए हैं, पर इनमें से ज्यादातर का समुचित उपचार नहीं हुआ है। अब जबकि दुर्घटनाओं के लिहाज से खतरनाक क्षेत्रों का फिर से ब्योरा जुटाया जा रहा है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह आंकड़े फाइलों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इनके उपचार की दिशा में भी विभाग तत्परता दिखाएंगे। अन्यथा, इस कसरत का कोई फायदा नहीं होने वाला। राज्य सरकार को इसकी नियमित मानीटरिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जनता के बीच इस बात का स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि सफर सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों मंदिर

विकास सारस्वत

तिरुपति प्रसाद प्रकरण दर्शाता है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलनी चाहिए

अवधेश राजपूत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिनों यह कह कर सनसनी फैला दी कि पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी के शासन में तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में चर्बी युक्त घी का प्रयोग हुआ था। उल्लेखनीय है कि तिरुपति मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी नामक सरकारी ट्रस्ट करता है। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे. श्यामला राव ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद टीटीडी के नए कार्यकारी अधिकारी के रूप में उन्होंने प्रसाद में प्रयोग होने वाले घी की गुणवत्ता जांचने के आदेश दिए थे। घी के पांच आपूर्तिकर्ताओं में से एक एआर डेरी के नमूनों में घोर अनियमितता मिली। घी की शुद्धता एस वैल्यू में मापी जाती है और इसका निर्धारित मानक 95.68 से लेकर 104.32 के बीच रहना चाहिए, लेकिन एआर डेरी के सैंपल की एस वैल्यू मात्र 19.72 पाई गई। सैंपल के इतने निम्न स्तर को देखते हुए उसके घी में वसा यानी बीफ टैलो, सुअर की चर्बी और मछली के तेल के मिश्रण की आशंका व्यक्त की गई। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है एआर डेरी को ही द्रमुक शासनकाल में तमिलनाडु के पलनी मंदिर में भी घी आपूर्ति का ठेका मिला है।

हालांकि जगन रेड्डी और एआर डेरी ने आरोपों को निराधार बताया है, परंतु नमूनों की लैब रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि तिरुपति जैसे संपन्न मंदिर में जिस प्रसाद को श्रद्धालु पैसे देकर खरीदते हैं, वहां सरकारी कंपनी केएमएफ के भरोसेमंद उत्पाद नंदिनी को छोड़कर अनजान आपूर्तिकर्ताओं से घी क्यों लिया गया? हिंदू विरोधी छवि से ग्रस्त जगन रेड्डी और द्रमुक सरकारों द्वारा एक ही डेरी को अनुबंधित करना भी असामान्य लगता है। घी में पशु चर्बी होने का आरोप अत्यधिक गंभीर है। ध्यान रहे कि अतीत में धोखे से गोमांस खिलाकर हिंदुओं के सामने मतांतरण माफिया ने धर्म भ्रष्ट होने का डर और ऐसी स्थिति में मतांतरण को ही एकमात्र समाधान बताकर पेश किया है। जगन द्वारा आरोपों के खंडन पर इसलिए भी भरोसा मुश्किल है, क्योंकि टीटीडी पर कब्जे और उसकी गतिविधियों में जगन एवं मुख्यमंत्री रहे उनके पिता वाई. सैमुअल राजशेखर रेड्डी का रिकार्ड विवादास्पद रहा है। ईसाई मूल के पिता-पुत्र ने ऐसे दो लोगों को टीटीडी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया, जिन पर ईसाई होने के आरोप लगे। हालांकि इन दोनों अधिकारियों करुणाकर रेड्डी भूमना और बाईवी सुब्बा रेड्डी ने इन आरोपों का खंडन किया, परंतु भूमना की पुत्री के ईसाई पद्धति से विवाह का वीडियो सार्वजनिक हुआ था। नक्सली पृष्ठभूमि से आए करुणाकर रेड्डी का ऐसा बयान भी सार्वजनिक है, जिसमें उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को काला पत्थर बताकर उसे चप्पल से पीटने की बात कही है। पेरियार सरीखे घृणित बयान देने वाले व्यक्ति को पिता और पुत्र ने दो बार टीटीडी का अध्यक्ष बनाया।

रेड्डी पिता-पुत्र की मंशा पर इसलिए भी सवाल उठते हैं, क्योंकि वह अपने खास रिश्तेदारों को टीटीडी अध्यक्ष पद पर कायम रखना चाहते हैं। भूमना और बाईवी रेड्डी दोनों ही जगन के करीबी रिश्तेदार हैं। तिरुपति स्थित तिरुमला की सात पहाड़ियों को भगवान वेंकटेश्वर का पृथ्वी पर निवास माना गया है और यहां किसी और मजहब के उपासना स्थल बनाने की मनाही है, लेकिन राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री काल और करुणाकर रेड्डी के टीटीडी कार्यकारी अधिकारी रहते दोनों ने पवित्र क्षेत्र को केवल दो पहाड़ियों तक सीमित करने के प्रयास किए। उसी दौरान तिरुपति में कई चर्च और एक बड़ी मस्जिद अस्तित्व में आई और टीटीडी में बहुत से गैर-हिंदुओं को नौकरी भी मिली। इसके साथ ही तिरुपति में अम्यूजमेंट पार्क जैसे मनोरंजन स्थलों को बढ़ावा देकर हिंदू आस्था के एक बड़े तीर्थ की पवित्रता को हल्का करने का प्रयास भी हुआ।

तिरुपति प्रसाद पर पैदा हुआ वर्तमान विवाद हिंदू आस्था पर भीषण आघात है। श्रीश्री रविशंकर समेत कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस प्रकरण की तुलना 1857 की क्रांति में गोमांस से भरे कारतूसों के उपयोग से पैदा हुए उत्तेजनात्मक कृत्य से की है। यह दुखद स्थिति इसलिए भी निर्मित हुई, क्योंकि सरकारी नियंत्रण होने के कारण बड़े-बड़े मंदिर गैर हिंदू और नास्तिकों के कब्जे में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक किसी संस्थान को लेकर स्पष्ट कानून न हो, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वे सभी संस्थान भी राज्य की परिभाषा में आ जाते हैं, जिन पर स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण हो। ऐसे में नियुक्तियां, खरीद और प्रबंधन इत्यादि पर राजकीय नीतियां ही लागू होती हैं। इस कारण गैर-हिंदुओं की नियुक्तियां कानूनसम्मत हो जाती हैं, जिनका उपयोग बुरी नीयत वाले नेता हिंदुओं को मुंह चिढ़ाने और उनकी आस्था को रौंदने के लिए करते हैं। आज तिरुपति प्रसाद में चर्बी मिलाने का मामला है तो कभी मंदिरों से मूर्तियों की तस्करी, गहने चुराने और मंदिरों की जमीन हड़पने की खबरें आती रही हैं।

तिरुपति मंदिर के ठीक सामने ईसाईयत के प्रचार को बढ़ावा दिया गया है। मंदिरों पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाए गए चढ़ावे का गैर-धार्मिक कार्यों में किया गया उपयोग दानराशि की सरकारी लूट का माध्यम बन गया है। तिरुपति में हुए हालिया अनाचार के बाद यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सालाना करीब 1,200 करोड़ रुपये का चढ़ावा प्राप्त करने वाले मंदिर में प्रसाद सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला भी नहीं है। इस प्रकरण में जिस तरह हिंदू भावनाओं को रौंदा गया, उसे देखते हुए दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जो एक मिसाल बने। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति भी मिलनी चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हिंदू समाज स्वयं सरकार के समक्ष मंदिर प्रबंधन और प्रशासन का एक सर्वसमावेशी और मजबूत खाका पेश करे। यदि इतने गंभीर प्रकरण के बाद भी मंदिरों को हिंदू नियंत्रण में वापस देने की कवायद शुरू नहीं होती तो इस प्रकरण पर उपजा आक्रोश व्यर्थ है। अन्य समुदायों को अपने धर्मस्थलों की देखरेख का जैसा अधिकार है, आखिर वैसा हिंदुओं को क्यों नहीं है?

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

नई विभाजक रेखाएं खींचने की कोशिश

राजीव सचान

बेलगाम हो रही जाति, पंथ और भाषा के सहारे की जाने वाली विभाजनकारी राजनीति

राहुल गांधी के बयान का विरोध करते सिख। एएनआइ

अपने देश में विभाजनकारी राजनीति नई नहीं है। हम भारतीय तो इसे विस्मृत कर ही नहीं सकते कि किस तरह इसी राजनीति ने भारत का विभाजन कराया। तब केवल हिंदुओं और मुसलमानों को दो अलग-अलग कौम यानी राष्ट्र ही नहीं बताया गया था, बल्कि हिंदू और उर्दू में भी भेद पैदा कर यह साबित करने की कुचेष्टा की गई थी कि उर्दू मुसलमानों की और हिंदी हिंदुओं की भाषा है। ऐसी ही विभाजनकारी राजनीति नए सिरे से सिर उठाती दिख रही है। यदि कोई यह कहे कि भारत में अन्य भारतीय भाषा भाषियों पर हिंदी को न केवल थोपा जा रहा है, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि बोलने वालों से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनका खानपान कमतर है तो यह हर दृष्टि से एक विभाजनकारी और वैमनस्य पैदा करने वाला बयान है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम पहले भी किया गया है, लेकिन यह पहली बार सुनने को मिल रहा है कि अन्य भारतीय भाषा भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा के साथ उनकी संस्कृति और उनका खानपान भी कमतर है। कहना कठिन है कि राहुल गांधी के पहले भाषा को लेकर इतनी बेतुकी और भड़काऊ बात किसने कही थी। अपने हालिया अमेरिका दौरे के दौरान वह केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे। वहां उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि भारत में सिखों के सामने कड़ा, पगड़ी धारण करने और गुरुद्वारे जाने का संकट खड़ा हो सकता है। इसका विरोध हुआ तो उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी को अपने कहे को सही ठहराने के लिए मैदान में उतार दिया। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा यह बोले कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आर्थिक नाकाबंदी कर रखी है और चन्नी ने यह समझाया कि मोदी सरकार पंजाब की खेती को नष्ट करना चाहती है। ऐसे बयान खालिस्तान समर्थकों के मन की मुराद पूरी करने वाले ही हैं।

यह आश्चर्यजनक नहीं कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान से सहमति जताई। इसके बाद भी पिछले दिनों राहुल की ओर से यही कहा गया कि उन्होंने अमेरिका में सिखों को लेकर जो कुछ कहा था, उस पर वह कायम हैं। इसके पहले जब वह जून 2023 में अमेरिका गए थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों और एससी-एसटी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तब वह कांग्रेस के सांसद भर थे। अब नेता प्रतिपक्ष भी हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जाति गणना पर भी जोर देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के साथ अन्य अनेक दल भी जाति गणना की मांग कर रहे हैं और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यह कह दिया है कि जाति गणना होती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। पता नहीं कि जनगणना के साथ जाति गणना होगी या नहीं, लेकिन यदि कोई यह समझा रहा है कि इससे देश की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा तो ऐसा होने वाला नहीं। इसके बाद भी यदि कोई ऐसा ही मानकर चलता है तो उसे ऐसा मानने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जाति गणना की मांग करते हुए यह माहौल बनाना शुद्ध विभाजनकारी राजनीति है कि दलित छात्र इसलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के लोग प्रश्नपत्र तैयार करते हैं।

अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहानी सुनाई थी कि अमेरिका में आइआइटी जैसी एक परीक्षा में अश्वेत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रश्नपत्र श्वेत लोग बनाते थे। फिर एक बार अश्वेतों ने प्रश्नपत्र बनाया तो सारे गोरे फेल हो गए। यह काल्पनिक कहानी सुनाने के बाद उनका कहना था, 'अगर आइआइटी में अपरकास्ट लोगों के बनाए प्रश्नपत्र के कारण दलित छात्र फेल हो रहे हैं तो एक बार दलितों से प्रश्नपत्र बनवा कर देखें।' भारत में जाति के सहारे जातीय वैमनस्य फैलाने की राजनीति पहले भी होती रही है। अनेक दल ऐसे हैं, जो जाति आधारित राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। जाति की यह राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंचती दिख रही है कि हर किसी की जाति खोजी जा रही है और यहां तक कि अपराधियों की जाति का उल्लेख कर यह माहौल बनाया जा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। यह माहौल कुछ इस तरह बनाया जा रहा है कि विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य पैदा होने का खतरा उभरने लगा है।

जातिवादी राजनीति के चलते सोशल नेटवर्क साइट्स पर ऐसे हैंडल लगातार बढ़ रहे हैं, जो दूसरी जाति वालों को निशाना बनाते हैं, उन पर छींटाकशी करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। हाल के समय में इसका सिलसिला महिला पहलवानों के धरना-प्रदर्शन के समय शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव के समय इसने अन्य जातियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन यह सिलसिला थमने के बजाय और तेज होता दिख रहा है। अब इसमें एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण के समर्थक और विरोधी भी शामिल हो गए हैं। खतरा इसका है कि जातीय बैर भाव कहीं इंटरनेट की दुनिया से निकलकर जमीन पर न उतर आए। जातियां भारतीय राजनीति की एक सच्चाई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाए और उनके बीच वैमनस्य पैदा किया जाए। ऐसा लगता है कि भारतीय समाज की पुरानी विभाजक रेखाओं को कुरेदने के साथ नई विभाजनकारी रेखाएं खींची जा रही हैं। विडंबना यह है कि जो विपक्षी दल भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वे खुद ऐसी ही राजनीति न केवल खुलकर कर रहे हैं, बल्कि उसकी धार तेज भी कर रहे हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन की राह

मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य को जानते हुए भी हम अपनी नासमझी के कारण रोज किसी न प्रकार मरते रहते हैं। कभी हताशा से तो कभी हमें अहंकार मार देता है। कभी कुंठा हमें मार देती है। कभी चिंता में मरते हैं तो कभी सपने में मरते हैं। इतनी सारी समस्याओं के बीच जिंदगी जीना मानो पैराशूट लेकर विमान से कूदने जैसा साहस भरा काम है। हालांकि जिन्हें जीवन की मूल्यवत्ता का बोध है, वे जीवन के हर पल का सम्मान करते हैं। दुखों का जलजला हो या सुनामी की लहरें, ये लोग उभरते जीवन को टूटने नहीं देते। याद रहे कि जीने के लिए भोजन, पानी, वायु जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आयु, जबकि मरने के लिए कुछ भी नहीं। केवल एक क्षण।

उम्र पाना एक पहलू है और उस उम्र तक जीना दूसरा पहलू है। उम्र चाहे बढ़ रही है, परंतु जिंदगी घट रही है। उम्र तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि जीवन डोर है, किंतु जीना अपनी समझ, दृष्टि और बोध पर आधारित है। जब तक हम जीवन को समझपूर्वक नहीं जिएंगे तब तक यही कहा जाएगा कि लंबी उम्र तो पाई, किंतु यह कहना मुश्किल है कि हमने लंबा जीवन भी जिया कि नहीं? जीवन विकसित या वृद्ध होने की प्रक्रिया हो सकता है। विकसित होना वर्षों में जीवन को जोड़ना है, वृद्ध होना जीवन में वर्षों को जोड़ना है। वस्तुतः, उम्र का आंकड़ा नहीं, अपितु जीवन को जीना मायने रखता है। यह अधिक महत्व रखता है कि कौन कितनी गहराई से या सुगमता से जीता है।

हमारे पूरे जीवन का अमूमन एक तिहाई हिस्सा तो नींद के नाम चला जाता है और एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई की घुटाई में लग जाता है। इसके बाद जो समय बचता है उसका अधिकांश हिस्सा धन अर्जन की उठापटक में गल जाता है। शेष बचा समय खानपान, मौज-शौक, मित्र और रिश्तेदारों आदि के नाम खर्च हो जाता है।

डा. निर्मल जैन

केरल का 'जल बजट'

सुधीर कुमार

केरल 'जल बजट' अपनाने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य है। इसे अपनाकर केरल ने जल की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने, कृषि उत्पादन की सुनिश्चितता, पर्यावरण व समग्र जल सुरक्षा और पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में मिसाल कायम किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहली वर्षा केरल के समुद्री तट पर ही होती है, बावजूद इसके गर्मी के दिनों में राज्य के कुछ इलाके पानी की कमी का सामना करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए ही केरल ने जल बजट बनाने का फैसला किया है।

जल बजट जल संसाधन की मात्रा निर्धारित करने और उनके प्रबंधन पर केंद्रित एक रणनीति है। यह जल की उपलब्धता और उसके उपयोग का सालाना ब्यौरा देता है। जल बजट किसी वर्ष विशेष में प्राप्त पानी को वितरित और प्रबंधित करने का समाधान प्रस्तुत करता है। यह जल के उपभोग की सीमा निर्धारित करता है, जिससे भूमिगत जल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके भंडारण को स्थायी रूप से सूखने से बचाया जा सकता है। यह भूजल की स्थिति की जानकारी भी प्रदान करता है। जल बजट निर्धारण का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर होता है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है। इसके तहत उपलब्ध जल संसाधन को विभिन्न उपयोगों में खर्च करने की योजना बनाई जाती है और उसी के अनुसार जल संसाधन का कुशल उपयोग किया जाता है। अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी शेष है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो हम उसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आसन्न जल संकट को भी टाला जा सकता है।

अगर हमें पहले से पता हो कि हमारे पास कितना पानी शेष है और वह कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा तो हम उसका बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं

सूखे और मानसून की अनिश्चितता तथा जल बजट जैसी व्यवस्था न होने के कारण ही देश में कई शहर 'डे-जीरो' की स्थिति का सामना कर रहे हैं। बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहर अपने निवासियों की प्यास के साथ-साथ अन्य जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता पेश कर चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने के लिए पानी का अभाव रहेगा। निःसंदेह स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति हमारा संवैधानिक अधिकार है। 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य' (1991) मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है।' हालांकि यह तभी संभव है, जब हरेक स्तर पर जल संरक्षण के सार्थक प्रयास हों। जल संकट के व्यापक होने का प्रमुख कारण भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अपना हित समझे मुस्लिम समुदाय

'मुसलमानों को फिर से डराने की साजिश' शीर्षक से लिखे आलेख में मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बोर्ड के इतिहास का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण का प्रयास किया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ मुद्दों की तरह इस बार भी मुसलमानों को डराने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें भड़काया जा रहा है। गंभीर सवाल यह उठता है कि आखिर देश का मुसलमान किसी के भड़काने में आता ही क्यों है? वह अपने हित को समझ पाने में क्यों नाकाम है? कहीं इसके पीछे उसकी मजहबी मान्यताओं के प्रति कट्टरता और शिक्षा व्यवस्था तो नहीं है? देश का बाकी समाज जहां आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, वहीं मुस्लिम समाज के एक वर्ग में मदरसा जैसी मजहबी शिक्षा को ही जरूरी मान लिया गया है। मुस्लिम समाज को यह समझना होगा कि राष्ट्र की उन्नति में ही उनकी भी उन्नति निहित है। इसलिए संकीर्ण सोच वाले लोगों के बहकावे में आने के बजाय उन्हें अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा। तभी उनकी समृद्धि की राह भी खुलेगी?

वेदप्रकाश पाण्डेय, अंबेडकर नगर (उप्र)

सही सलाह

'राहुल की आत्मघाती आक्रामकता' शीर्षक आलेख में डा. एके वर्मा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे लड़कपन छवि से बाहर निकल कर भारतीय जनमानस की संस्कृति को अपनाएं। अमेरिका की अपनी यात्रा में राहुल गांधी के टिप्पणियों ने भारत में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया, जबकि पड़ोसी दुश्मन देशों में राहुल के बयानों को जमकर तारीफ की जा रही है। जानकार बताते हैं कि देश में सिख समुदाय को किसी तरह के धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वर्ष 1984 में कांग्रेस शासनकाल में एक सोची-समझी साजिश के तहत तीन हजार सिखों का नरसंहार किया गया और इस नरसंहार में कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। पुरी ने कहा कि मैं पिछले 60 साल से भी अधिक समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं और मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे कि उसे पगड़ी और कड़ा पहनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

संवैधानिक व्यवस्था का करें सम्मान

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने संवैधानिक पद की गरिमा का अपमान करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को छोड़ कर खड़ाऊं शासन चलाने का नया अध्याय और प्रयोग आरंभ किया है। अभी चार माह बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में उनका चार माह का शासन अरविंद केजरीवाल के लगभग दस वर्षों के शासन के मुकाबले कितना सार्थक और प्रभावशाली होगा, यह तो समय बताएगा, परंतु उन पर अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी छोड़ने का दबाव अपनी वास्तविकता जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बेल पर बाहर आने के बाद भगवान श्री राम से उनकी तुलना न केवल अपमानजनक है, बल्कि हास्यास्पद है। आतिशी की तुलना भरत से करना भी तुलसीदास जी की रामचरित मानस और ऋषि वाल्मीकि की रामायण का उपहास है। आम आदमी पार्टी के राम और भरत राजयोग और राजसत्ता का पूरा आनंद ले रहे हैं। इससे तो दिल्ली की विधानसभा को भंग करके नए विधानसभा चुनाव की अनुशंसा करना उचित था। यह प्रशंसनीय होता कि आम आदमी पार्टी अपने दस वर्षों का रिपोर्टकार्ड जनमानस के सामने लाए और फिर दिल्ली पर शासन करने के लिए जनता का आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करे। घोटालों का हिसाब किताब अदालतों में होता है भीड़ से नहीं। जनता गुनाहों और गुनाहगारों का निर्णय नहीं कर पाती, नहीं तो कितने ही अपराधी और भ्रष्टाचार पृष्ठभूमि के जन प्रतिनिधि विधायिकाओं में न बैठे होते। आतिशी की विवशता समझी जा सकती है। दिल्ली की विधानसभा चुनाव के परिणाम किसी के पक्ष में हो, आम आदमी पार्टी ने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी जमीन से निकालता है दिल्ली जल बोर्ड। जहां 1983 में यहां 33 फीट गहराई पर पानी निकल आता था, आज यह गहराई 132 फीट हो गई है।

आजकल

उपकरणों के हथियार में बदल जाने का संकट

हाल में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वाकीटाकी और रेडियो सेट विस्फोट के साथ अचानक फटे, तो समूचा विश्व इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ है। हालांकि इजरायल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इसे देखते हुए आज पूरी दुनिया आशंकित है कि क्या कभी उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटाप आदि इलेक्ट्रानिक उपकरणों में भी इसी तरह विस्फोट कराया जा सकता है?

आधुनिक किस्म की जंग में तकनीक एक बड़े हथियार की भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुकी है। प्रतीकात्मक

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-टेली परफार्मेंस से संबद्ध

इस आधुनिक युग में सूचना-संचार से लेकर ऐसे दर्जनों काम हैं, जिनमें विज्ञान की देन कही जाने वाली तकनीकों, मशीनों और उपकरणों ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है। हालांकि तकनीक के दूसरे पहलू की अपनी कई समस्याएं भी हैं। जैसे इंटरनेट और मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होने का हवाला अक्सर दिया जाता है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि तकनीक तो असल में हमारी जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन क्या यह वास्तव में जानलेवा हो सकती है? हाल में लेबनान और सीरिया में हिजबुल्ला के हजारों सदस्यों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे संचार उपकरण पेजर, वाकीटाकी और हैंडहेल्ट रेडियो सेट विस्फोट के साथ अचानक फटे, तो दुनिया इनके जानलेवा होने वाले पक्ष को देखकर हैरान रह गई। दावा किया गया कि पेजर और वाकीटाकी के अलावा घरों में लगे सोलर पैनलों में भी ऐसे ही विस्फोट हुए। दावा है कि इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ है। इजरायल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आज लेबनान समेत पूरी दुनिया आशंकित है कि क्या कभी उनके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटाप जैसे उपकरणों का युद्धक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है? क्या दुनिया उस दौर में पहुंच गई है जहां कोई देश अपने शत्रु के सैनिकों-नागरिकों को कोई वास्तविक जंग छेड़े बिना घर बैठे महज एक बटन दबाकर नुकसान पहुंचा सकता है?

जंग में क्या सब जायज है : लेबनान ने जब यह सवाल अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पूछा, तो प्रतिक्रिया में पेजर और वाकीटाकी को हमलों का जरिया बनाने को अनैतिक और युद्ध-अपराध कहा गया। असल में बीते करीब एक साल से इजरायल गाजापट्टी में आतंकी संगठन हमास के सहयोगी हिजबुल्ला के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस जंग में जिसका जहां दांव लग रहा है, वह उस तरीके से अपने शत्रु पर हमला कर रहा है। इस जंग में अपनी ओर से ये देश कई ऐसी सावधानी भी बरत रहे हैं, ताकि वे अपने दुश्मन की नजर में न आएं। जैसे कि हिजबुल्ला के शीर्ष नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को संचार के लिए मोबाइल या इंटरनेट के बजाय पेजर नामक उस उपकरण के इस्तेमाल का आदेश दे रखा है, जिसमें कोई सिम कार्ड जैसी चीज नहीं होती। पेजर मोबाइल फोन से पहले के जमाने की तकनीक है। इसके जरिये अमूमन कोई संदेश अंकों और अक्षरों के आदान-प्रदान तक सीमित रहता है। पेजर की खासियत यह है कि इसके उपयोगकर्ता की मौजूदा स्थिति यानी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी तरह वाकीटाकी से भी संदेश प्राप्त किए और भेजे जा सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही व्यक्ति बात कर सकता है। यह बैटरी से चलता है और इसे सेलुलर नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। हिजबुल्ला को यह खतरा रहा है कि इजरायल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी-मोसाद उसके लड़ाकों की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती है। लिहाजा उसने अपने लड़ाकों को कम तकनीक क्षमता वाले पेजर और वाकीटाकी प्रयोग करने के लिए दिए थे। पेजर और वाकीटाकी ऐसे बेसिक उपकरण हैं जिन्हें इस्तेमाल करने वाले की लोकेशन का पता लगाकर उस पर कोई हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन हाल के हमलों ने साबित कर दिया है कि सिर्फ पेजर और वाकीटाकी ही नहीं, हर किस्म के उपकरण हथियार में तब्दील किए जा सकते हैं, बशर्ते उसके निर्माण की प्रक्रिया और सप्लाई चेन में कोई सेंध लगाई जा सके। अंदाजा है कि यह खुफिया सूचना कि हिजबुल्ला अपने लड़ाकों के लिए हजारों पेजर एक साथ खरीदने वाला है, किसी तरह इजरायल के हाथ लग गई होगी। माना जा रहा है कि निर्माण अथवा सप्लाई चेन में ही किसी स्तर पर मोसाद ने घुसपैठ कर ली होगी और पेजर-वाकीटाकी आदि में विस्फोटक लगा दिए होंगे। ये विस्फोटक इस प्रकार लगाए गए थे कि इन्हें कोई संदेश भेजकर सक्रिय किया जा सके।

कैसे हथियार में बदली तकनीक : वैसे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले पेजर और वाकीटाकी आज के आधुनिक दौर में गुजरे जमाने के उपकरण लग सकते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये आज भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और कोयला खदानों समेत कई ऐसे संवेदनशील उद्योगों में-जहां मोबाइल नेटवर्क आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। चूंकि इनकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, इसलिए आपात स्थितियों में मोबाइल फोन के मुकाबले ये ज्यादा विश्वसनीय संचार उपकरण साबित होते हैं। प्रायः प्लास्टिक से बने पेजर और वाकीटाकी किसी सिग्नल को ग्रहण कर उसे डिकोड नहीं कर सकते। इनकी संरचना में एंटीना, स्पीकर, माइक्रोफोन, बैटरी, ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। स्पीकर और माइक्रोफोन को छोड़ दें, तो शेष तीनों विस्फोटक के कंटेनर का काम कर सकते हैं। यही नहीं, इन उपकरणों के अंदर बैटरी के आसपास इतनी खाली जगह होती है, जहां छोटा-मोटा विस्फोटक लगाया जा सकता है। यहां एक बड़े सवाल और आशंका ने जन्म लिया है। वह यह कि इस तरह तो मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, माइक्रोवेव, रेफ्रीजरेटर समेत हर उपकरण को हैक किया जा सकता है और उसे युद्धक हथियार में बदला जा सकता है।

क्या बम में बदल सकता है मोबाइल : इसमें संदेह नहीं है कि यदि किसी भी उपकरण के निर्माण और आपूर्ति प्रक्रिया में कोई देश जंग के इरादे से सेंध लगाने में सफल हो जाए, तो उन उपकरणों को वांछित समय पर निर्देश देकर विस्फोट करने अथवा कोई अन्य गड़बड़ी करने के लिए सेट किया जा सकता है। इनमें से मोबाइल या कहें कि स्मार्टफोन तो अपनी अत्याधुनिक कार्यप्रणालियों और वायरलेस कनेक्टिविटी के कारण पेजर और वाकीटाकी की तुलना में कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं। इंटरनेट, जीपीएस ट्रैकिंग और रिमोट कंट्रोल आदि जिन सहूलियतों ने मोबाइल फोन को अत्यधिक सुविधाजनक उपकरण में तब्दील किया है, वे सभी इसे जंग का सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कारगर हो सकते हैं। इससे सबसे जरूरी सूचना यानी लोकेशन तो एक आम इंसान तक हासिल कर सकता है। सेना या बड़ी एजेंसियां इन्हें हैक करके इन पर काल और मैसेज भेजकर धमाके तक कर सकती हैं। मोबाइल फोन तो वैसे भी अपनी लीथियम आयन बैटरियों से जुड़ी समस्याओं के कारण पहले से ही कुख्यात रहे हैं। ज्यादा गर्म हो जाने पर इनमें स्वतः विस्फोट हो जाने के दर्जनों हादसे प्रकाश में आए हैं। शार्ट सर्किट होने से लीथियम आयन बैटरी के फटने की समस्या बहुत आम रही है। वैसे तो स्मार्टफोन में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को पेजर और वाकीटाकी के मुकाबले ज्यादा पुख्ता माना जाता है, लेकिन बैटरी कंट्रोलर सिस्टम को ही अगर कोई हैक कर ले, तो जब चाहे उसमें विस्फोट करा सकता है। यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। यही नहीं, मोबाइल फोन की तरह इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) तकनीक से जुड़े अन्य सारे उपकरण हैक किए जा सकते हैं और उनसे अव्यवस्था फैलाई जा सकती है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आधुनिक किस्म की जंग में तकनीक एक बड़े हथियार की भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुकी है। पेजर, वाकीटाकी, मोबाइल फोन, ड्रोन, लेजर बम, सैटेलाइट हैकिंग और अंतरिक्ष में लड़े जा सकने वाले युद्ध-इन सभी में तकनीक का योगदान है। जो देश जासूसी और जंग के लिए इनके इस्तेमाल के तौर-तरीकों से लैस है, आज की तारीख में उसे दूसरे देशों के मुकाबले युद्ध में बढ़त हासिल है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उसे शत्रु देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में नहीं उतारना है, बल्कि यह काम एक अत्याधुनिक कमांड स्थापित करने और घर बैठे मशीनों को संदेश देने भर से संपन्न हो जाता है।

तकनीकी आत्मनिर्भरता से बचाव संभव

आज की तारीख में मोबाइल फोन के जरिये अपना डाटा दुनिया भर की कंपनियों के हवाले करके हम खुद कई गलतियां कर चुके हैं, फिर भी हिदायत दी जाती है कि जहां तक मुमकिन हो-इंटरनेट और बेहद एडवांस तकनीकों से लैस उपकरणों के इस्तेमाल से बचें। इस्तेमाल में आइओटी से लैस चीजें (जैसे कि आधुनिक कारें) सुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन हैकिंग की सूरत में ये खतरनाक बन सकती हैं। जनता के स्तर से अलग हटकर सरकार के स्तर पर एक समस्या और है। वह है तकनीक में आत्मनिर्भरता के अभाव की। हमारे देश ने सर्विस सेक्टर यानी आइटी इंजीनियरिंग में साफ्ट स्किल से लैस कर्मचारियों की फौज तैयार करने में महारत हासिल की, लेकिन निर्माण यानी मैन्यूफैक्चरिंग में भारत पिछड़ गया। इसके फलस्वरूप देश आज अपना ज्यादातर इलेक्ट्रानिक सामान चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों से मंगाता है। यह स्थिति सही क्यों नहीं है, इसे ऐसे समझना चाहिए कि अमेरिका ने चीन की कंपनी-हुआवे के उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। मोबाइल से लेकर तमाम घरेलू उपकरण और विशाल इंजीनियरिंग के सामान बनाने वाली इस कंपनी पर अमेरिका का आरोप है कि वह अपने उपकरणों के जरिये डाटा जमा करती है और जासूसी करने में चीन के नेतृत्व की मदद करती है। उपकरणों के जरिये डाटा संग्रह करने या उसे चुराने की प्रक्रिया कैसे जंग में किसी देश की मदद कर सकती है-लेबनान में हुए हालिया हादसे के मद्देनजर यह बात आसानी से समझी जा सकती है। बेशक तमिलनाडु में आइफोन की फैक्ट्री लगाकर भारत ने इस दिशा में सही पहल की है, लेकिन कोशिश करनी होगी कि सभी तरह के उपकरणों के निर्माण में देश आत्मनिर्भरता हासिल करे। ऐसा करना आर्थिक स्वावलंबन और रोजगार पैदा करने के नजरिये से ही नहीं, बल्कि युद्ध की सूरत में अपने हितों को संरक्षित करने के लिहाज से भी जरूरी है।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

गगनचुंबी आशाएं और बौनी सच्चाइयां

नृपेंद्र अभिषेक नृप

आजकल स्मार्टफोन की महिमा अपरंपार है। लोग नाश्ते की प्लेट से लेकर रात के सपनों तक, हर चीज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने में मग्न हैं। ऐसा लगता है मानो जीवन का असली मकसद ही अब सेल्फी लेना हो गया है। सुबह उठते ही लोग सबसे पहले अपनी फोन को ही देखते हैं, उसके बाद ही चेहरे को देखते हैं। चेहरा चाहे जैसे भी हो, फिल्टर से सब ठीक हो जाएगा। आजकल फिल्टर का जमाना है-दुनिया को जो दिखाना हो, वह दिखाओ, सच्चाई किसी को नहीं दिखती। पर असल में तो लोग खुद को खो रहे हैं, और खो रहे हैं समय, रिश्ते और सबसे बड़ी बात, वास्तविक जीवन की चमक।

धन का महत्व अब जीवन का मूल मंत्र बन चुका है। अगर आपके पास नई गाड़ी, बड़ा घर और एक महंगा स्मार्टफोन है, तो आप सफल हैं, भले ही आपकी रातों की नींद उड़ चुकी हो। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि लोग दिन-रात धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, और उसी धन की होड़ में जीवन का आनंद भूलते जा रहे हैं। जब आखिरकार बैंक बैलेंस बड़ा हो जाता है, तब पता चलता है कि जीवन के असली रिश्ते छोटे हो गए हैं।

समाज भी कुछ कम नहीं है। हम समाज में बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन खुद को बदलने की बात पर हम पल्ला झाड़ लेते हैं। स्वच्छता अभियान से लेकर महिला सशक्तीकरण तक, सब कुछ बस इंटरनेट मीडिया के हैशटैग बनकर रह जाता है। असल में बदलाव लाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और वह हमसे नहीं होता। हम आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं, लेकिन जमीन पर पैर रखना भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन उसके लिए कोई त्याग नहीं करना चाहते। हम दिखावे के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि असली जीवन को देखना ही बंद कर दिया है। हम चाहे जितना भी दौड़ लें, अंत में सच्चाई यही है कि हमें अपने अंदर झांकना होगा। जब तक हम वास्तविक जीवन के मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक यह दौड़ जारी रहेगी-बिना किसी मंजिल के, बिना किसी सुकून के।

पोस्ट

वायरल होने की अंधी दौड़ में इंसान कितना नीचे गिरता जा रहा है। रील बनाने के लिए दूसरों को परेशान करने वालों की कायदे से कुटाई होनी चाहिए।

राजा बाबू@GaurangBhardwa1

प्रगनानंद और वैशाली की मां को देखते ही आसपास की तमाम माताओं के चेहरे उभर आते हैं। ऐसा लगता है यह अपनी ही मां हैं, जिसने चूल्हे पर सपने सेंके हैं। बर्तन के साथ तमाम दुखों को धोया है और पति के पोलियोग्रस्त होने के बावजूद बेटे-बेटी को शतरंज का विश्व चैंपियन बना दिया है।

अतुल कुमार राय@AuthorAtul

राहुल गांधी ने शतरंज के विश्व चैंपियनों को बधाई तो दी, पर क्या खिलाड़ियों से उनकी जाति पूछी कि वे किस जाति के हैं? उन्होंने उनसे सामाजिक न्याय के बारे में पूछा?

श्रीमय तालुकदार@sreemoytalukdar

श्रीलंका में एक मार्क्सवादी राष्ट्रपति की ताजपोशी हो गई। नेपाल की कमान पहले से ही कम्युनिस्टों के पास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अमेरिका समर्थित सेनाओं का दबदबा है। मालदीव में इस्लामिक झुकाव वाले राष्ट्रपति हैं। म्यांमार में विद्रोहियों को अमेरिकी शह मिल रही है। कुल मिलाकर, भारत के लिए आसपड़ोस में सब कुछ ठीक नहीं। ब्रह्मा चेलानी @Chellaney

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या श्रीलंका में दिसानायके का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए चिंता का विषय है?

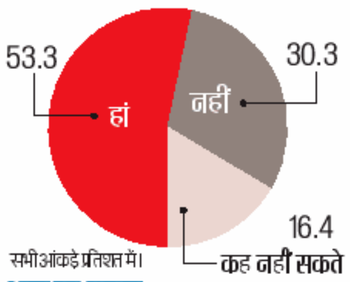

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को त्यागपत्र देना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आलराउंडर है सपा तभी हो रहा 'नाम',
नोट छापने का करें उसके नेता काम।
उसके नेता काम सगे डकैत-दुष्कर्मी,
फिर भी सीना तानचलें, देखो बेशर्मी।
टोपी लाल लगाय करें ये खड़ा बवण्डर,
कहलाते हैं आज तभी तो आलराउंडर!

- ओमप्रकाश तिवारी

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब डायरी

मंत्रिमंडल में बार-बार होते फेरबदल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ढाई साल के कार्यकाल के दौरान चौथी बार मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया है और चार मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पांच नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी है। इस पर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, वह रेल के डिब्बों को बार-बार बदलकर पंजाब की आर्थिकी और कानून की व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश न करें। एक बार इंजन बदलकर देख लें। उनका इशारा मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर था कि उन्हें बदलकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बाजवा ने कुछ दिन पहले भी इस तरह का बयान दिया था जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह पर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाजवा ने कहा था कि किसी महिला को पंजाब की कमान सौंप देनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा अक्सर एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। चाहे वह सार्वजनिक मंच हो या विधानसभा सत्र, लेकिन यहां मुद्दा पांच नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करने का है। आखिर इसकी क्या वजह रही कि मात्र ढाई वर्षों में ही मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट में चार बार फेरबदल करने पड़े। क्या मुख्यमंत्री को अपने इन मंत्रियों की काबिलियत पर संदेह था या फिर बात कुछ और है। सरकार के बार-बार इस तरह के कदम उठाने से जहां अन्य मंत्रियों का विश्वास डगमगा रहा है, वहीं आम लोगों की उम्मीदें भी धूमिल हो रही हैं। ढाई साल पहले जिस आम आदमी पार्टी को 117 में से 92 सीटें देकर रिकार्डतोड़ जीत आम लोगों ने दी थी, अब इस तरह का फेरबदल देख-देख कर उनकी भी उम्मीदें टूटती जा रही हैं। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायकों के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, उससे लग ही रहा था कि कैबिनेट में एक बार फिर से फेरबदल होगा। दिक्कत यह हो रही थी कि जून महीने के बाद से ही पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, जिस कारण उनसे चर्चा नहीं हो पा रही थी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जालंधर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से जालंधर पश्चिम के लोगों को आश्वासन दिया कि वह उनकी पार्टी के नेता को विधायक बना दें, मंत्री तो वह उन्हें बना ही देंगे। जालंधर पश्चिम के लोगों ने मुख्यमंत्री की बात को रखा और भारी बहुमत से मोहिंदर भगत को चुनकर विधानसभा में इस आस से भेजा कि वह मंत्री बनकर उनके इलाके का विकास करेंगे। मोहिंदर भगत को मंत्री बनाने की तैयारी भी लगभग हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उनको इंतजार करने के लिए कहा गया। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी में इस बात को लेकर नाराजगी है कि कुछ समय पहले ही भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए मोहिंदर भगत को कैसे मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, जबकि उनसे पहले के कई विधायक मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भगवंत मान की कैबिनेट में दो मंत्रियों की जगह पहले से ही खाली थी, तीसरी सीट कैबिनेट मंत्री मीत हेयर के सांसद बनने के चलते खाली हो गई। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री की बात को रखने के लिए मोहिंदर भगत को कैबिनेट में तो जरूर ले लिया गया है, लेकिन उनको ऐसे विभाग दिए गए हैं, जिन्हें आमतौर पर कम महत्व का माना जाता है। उनको रक्षा सेवाएं और बागवानी विभाग दिए गए हैं।

कुछ नए चेहरों को चार से पांच बड़े विभाग देकर नवाजा गया है। पार्टी में इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है कि क्या इस बार फेरबदल में मुख्यमंत्री की ज्यादा चली है या फिर पार्टी हाईकमान ने अपना दबदबा कायम रखा है। पिछली सरकारों के दौरान भी 18 मंत्रियों में से चार या पांच अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार 16 में ही पांच मंत्री अनुसूचित जाति से हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि ऐसा होशियारपुर जिले में डाक्टर राजकुमार चब्बेवाल के सांसद बनने के कारण खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए किया गया है। पार्टी का ध्यान इस जिले की आरक्षित सीट चब्बेवाल पर होने वाले उपचुनाव पर है। पार्टी अनुसूचित जाति के वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचना चाहती है।

खैर, कैबिनेट में बदलाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी-जल्दी उलटफेर पंजाब के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। वह भी तब जब किसी पार्टी को तीन चौथाई बहुमत मिला हुआ है। आमतौर पर अल्पमत वाली सरकारों या गठजोड़ सरकारों के दौरान तो इस तरह के फेरबदल होने की संभावना रहती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में इस तरह देखने को कम ही मिलता है।

सीएम भगवंत मान (दाएं से तीसरे) ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में चौथी बार बदला मंत्रिमंडल। फाइल

मंथन

चिंतित करता विषैला होता भूजल

पंकज चतुर्वेदी
पर्यावरण मामलों के जानकार

देश की राजधानी दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है और उसी गति से यहां पानी की मांग भी बढ़ रही है। दिल्ली में पूरे साल पानी वितरण का तंत्र जिन टैंकरों पर टिका है, उनकी जलापूर्ति भूजल के ऐसे स्रोतों से हो रही है, जो जहर बन चुके हैं और उस जल को शुद्ध-निरापद बनाने के न तो कोई उपाय हैं और न ही प्रयास हो रहे हैं। कितना दुखद है कि मजबूरी में लोग उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें बीमार बना रहा है। केंद्रीय भू जल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य खतरनाक रसायनों से परिपूर्ण है और ये हड्डियों के रोग, दांतों की कमजोरी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा हड्डियों और दांतों को कमजोर कर देती है। आर्सेनिक की अधिक मात्रा से त्वचा, आंखों, कैंसर, फेफड़ों और किडनी की बीमारी होती है। वहीं लवणता बढ़ने से ब्लड प्रेशर और पथरी का रोग होचा है। एक तो दिल्ली में भूजल और गहराई में जा रहा है, इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है।

दिल्ली में भूजल की उपलब्धता सालाना 291.54 मिलियन घन मीटर है। पाताल खोद कर निकाले गए पानी से यहां 47 हजार पांच सौ हेक्टेयर खेत सींचे जाते हैं। 142 मिलियन घन मीटर पानी कारखानों एवं पीने के काम आता है। दिल्ली जल बोर्ड 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी जमीन से निकालता है। जहां 1983 में यहां 33 फीट गहराई पर पानी निकल आता था, आज यह गहराई 132 फीट हो गई है। इसमें भी नाइट्रेट, फ्लोराइड एवं आर्सेनिक जैसे रसायन हानिकारक स्तर पर पहुंच गए हैं। सनद रहे कि पाताल के पानी को गंदा करना तो आसान है, पर उसका परिशोधन करना करीब असंभव। जाहिर है भूजल के हालात सुधारने के लिए बारिश के पानी से रीचार्ज एवं उसके कम दोहन की संभावनाएं खोजनी होंगी। आखिर दिल्ली के गर्भ के जल को जहरीला कौन बना रहा है? इस महानगर में कूड़े का सही तरह से प्रबंधन एवं निस्तारण न होना इसका सबसे प्रमुख कारण है। यहां कूड़े के तीन विशाल पहाड़ हैं और उनका हर दिन कद बढ़ता जा रहा है। सारी दुनिया से वैध-अवैध तरीके से इलेक्ट्रानिक कचरे यहां आ रहे हैं। इनका गैर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किए जाने से उपजे खतरनाक रसायन बहुत चुपके से धरती में गहरे तक समा रहे हैं और जीवनदायी जल को जहर बना रहे हैं। ई-कचरे के लगभग 97 प्रतिशत हिस्से को अवैज्ञानिक तरीके से जला कर या तोड़ कर उनमें से कीमती धातुएं निकाली जाती हैं एवं शेष को यूं ही कहीं फेंक दिया जाता है। इससे रिसने वाले रसायनों का एक भयानक तथ्य यह है कि इस कचरे की वजह से पूरी खाद्य शृंखला बिगड़ रही है। ई-कचरे के आधे-अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल रहे हैं, जो पेड़-पौधों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं। इसके चलते पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है। इसका असर वायुमंडल में आक्सीजन की मात्रा पर हो रहा है।

बैटरियों, कंप्यूटरों और मोबाइल फोन का कचरा सबसे खतरनाक है। इनमें पारा, कोबाल्ट, कैडमियम और न जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। कैडमियम से फेफड़े एवं किडनी दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। एक कंप्यूटर का वजन लगभग 3.15 किलो ग्राम होता है। इसमें 1.90 किलोग्राम सीसा, 0.693 ग्राम पारा और 0.049 ग्राम आर्सेनिक होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती-सड़ती नहीं है और जमीन में जज्ब हो कर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने का काम करती है। ठीक इसी तरह का जहर बैटरियों एवं बेकार मोबाइल फोनों से भी उपज रहा है। इनसे निकलने वाले जहरीले तत्व और गैसें मिट्टी एवं पानी में मिलकर इन्हें बंजर और जहरीला बना देती हैं। फसलों और पानी के जरिये ये तत्व हमारे शरीर में पहुंचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। बैटरियों से निकला तेजाब, नालों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण पाने के साथ मिल कर धरती में जहर भर रहे हैं। यहां के खेत और यमुना के कछार में सब्जी उगाने में बेशुमार रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने गहरे तक धरती और उसकी कोख के पानी को विष में बदल दिया है।

दिल्ली में जल आपूर्ति बगैर भूजल के संभव नहीं है। इस दूषित पानी के सेवन से यहां की बड़ी आबादी बीमार हो रही है। इससे लोगों पर आर्थिक और सामाजिक बोझ तो बढ़ ही रहा है, उनके कार्य करने की क्षमता और आर्थिक तंत्र भी गड़बड़ा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए आज दिल्ली और इसके आसपास करीब 100 किलोमीटर के दायरे में कचरा उठाने और इनके निस्तारण (खासकर इलेक्ट्रानिक कचरे) के लिए एक कड़ी और स्पष्ट नीति बनाने की तत्काल जरूरत है। साथ ही इस समूचे इलाके में जैविक खेती भी अनिवार्य की जानी चाहिए।

दिल्ली में भूजल और गहराई में जाने के साथ इसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। फाइल

****

रेडीमेड विक्रेताओं का राजस्व 10 % बढ़ने की उम्मीद

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में संगठित रेडीमेड खुदरा विक्रेताओं के राजस्व में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि आगामी त्योहारी व शादियों के सीजन और फैशन के प्रति बढ़ती पसंद का राजस्व वृद्धि में प्रमुख योगदान रहेगा। हालांकि, यह वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 की 11-12 प्रतिशत की वृद्धि से कम रहेगा। (प्रेट्र)

भारत डिजिटल पुनर्जागरण के शिखर पर है। इसमें एक जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

— संदीप पटेल, प्रबंध निदेशक, आइबीएम इंडिया

सेंसेक्स	84,914.04 ▼ 14.57	निफ्टी	25,940.40 ▲ 1.35	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 76,950 बदलाव नहीं	चांदी प्रति किलोग्राम	₹90,000 बदलाव नहीं	डालर	₹ 83.63 ▲ ₹0.9	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 75.64

एक नजर में

लैपटाप आयात के लिए मंजूरी व्यवस्था 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली : सरकार ने लैपटाप और टैबलेट सहित कुछ आइटी हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा मंजूरी व्यवस्था को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। प्रणाली की समीक्षा की समयसीमा 30 सितंबर है। इन उत्पादों का आयात 2023-24 में 8.4 अरब डालर का रहा। अधिकतर आयात चीन से किया गया था। तीन अगस्त, 2023 को लैपटाप, टैबलेट और छोटे आकार के कंप्यूटर पर आयात अंकुश लगाया था। (प्रेट्र)

पांच वर्ष के लिए बढ़ाई जाए ब्याज अनुदान योजना

नई दिल्ली : निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो ने मंगलवार को सरकार से ब्याज अनुदान योजना को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने का आग्रह किया। फियो ने कहा कि इससे इस क्षेत्र में कर्ज प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी, ताकि देश के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसी वर्ष अगस्त में निर्यात 9.3 प्रतिशत घटकर 34.71 अरब डालर रह गया था। (प्रेट्र)

दूसरी छमाही में बढ़ेगा निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च

नई दिल्ली : एसबीआइ के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि बैंक को कंपनियों से पहले ही करीब चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज के आवेदन मिल चुके हैं। शेट्टी ने बताया कि सड़कों, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से कर्ज की मांग आ रही है। (प्रेट्र)

जमा में धीमी वृद्धि से बैंक बांड से पैसा जुटाने पर मजबूर

मुंबई : जमा में धीमी वृद्धि से बैंकों को बांड के जरिये पैसा जुटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक बांड के जरिये 1.3 लाख करोड़ रुपये तक जुटा सकते हैं। यह बैंकों की ओर से बांड के जरिये जुटाई जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा राशि होगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से करीब 85 प्रतिशत बांड सरकारी बैंकों की ओर से जारी किए जाएंगे। (प्रेट्र)

85 हजार अंक के पार जाकर लुढ़का सेंसेक्स

इंट्रा-डे में 234 अंक बढ़कर 85,163 के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचा था बीएसई सूचकांक

मुंबई, प्रेट्र : स्पष्ट संकेतों के अभाव में घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को दिनभर उतार-चढ़ाव का माहौल रहा। गिरावट के साथ दिन की शुरुआत करने वाला बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के दौरान 234.62 बढ़कर पहली बार 85 हजार के पार पहुंचा। लेकिन अंत में यह 14.57 अंक की गिरावट के साथ 84,914.04 अंक पर बंद हुआ। उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण दोपहर के समय यह 84,716.07 के निचले स्तर तक पहुंचा था।

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी पहली बार कारोबार के दौरान 26 हजार के पार पहुंचा। अंत में यह 1.35 अंक की तेजी के साथ 25,940.40 अंक के नए रिकार्ड स्तर पर जाकर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 72.5 अंक बढ़कर 26,011.55 के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंचा था। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदुस्तान यूनीलिवर, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक जैसे बड़े शेयरों में बिकवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक उच्च स्तर को बरकरार रखने में कामयाब नहीं रह सके। हालांकि, चीन में घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन उपायों से धातु क्षेत्र के शेयरों में तेजी रही।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर का कहना है कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती से प्रेरित घरेलू सूचकांक नई ऊंचाइयों को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच चीन के केंद्रीय बैंक की ओर से दरों में कटौती और अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों ने वैश्विक निवेशक भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू धातु शेयरों में लाभ हुआ है। इसके विपरीत एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली के कारण गिरावट देखी गई। निकट भविष्य में अमेरिकी फेड के नरम दृष्टिकोण और अक्टूबर में आरबीआइ की ओर से दरों में कटौती से प्रेरित विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की ओर से मजबूत प्रवाह बने रहने की उम्मीद है।

14.47
अंक गिरकर 84,914 पर बंद हुआ सेंसेक्स कारोबार के अंत में

26
हजार के पार जाकर गिरा निफ्टी, 25,940 पर हुआ बंद

- एफएमसीजी और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में हुई मुनाफावसूली
- चीन में प्रोत्साहन उपायों से धातु क्षेत्र के शेयरों में रही तेजी

उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद बाजार में सुस्ती रही, लेकिन प्रमुख सूचकांक रिकार्ड स्तर तक पहुंचे। इससे पता चलता है कि बाजार में तरलता प्रवाह मजबूत बना हुआ है। निवेशक भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी के प्रति आश्वस्त हैं।

प्रशांत तापसे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च, मेहता इक्विटीज लिमिटेड

सेंसेक्स के टाप गेनर (%में)	
टाटा स्टील	4.29
पावरग्रिड	2.65
टेक महिंद्रा	1.88
एचसीएल टेक	1.36
महिंद्रा एंड महिंद्रा	0.78

सेंसेक्स के टाप लूजर (%में)	
हिंदुस्तान यूनीलिवर	2.56
अल्ट्राटेक सीमेंट	1.76
कोटक महिंद्रा बैंक	1.23
इंडसइंड बैंक	1.20
नेस्ले इंडिया	1.06

कच्चे तेल का मूल्य बढ़ने से नौ पैसे लुढ़का रुपया

घरेलू शेयर बाजारों में रहे उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में तेजी के कारण मंगलवार को डालर के मुकाबले रुपये में नौ पैसे की गिरावट रही। अंतरबैंक मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय रुपया डालर के मुकाबले 83.54 के स्तर पर खुला और अंत में यह 83.63 के स्तर पर बंद हुआ। सोमवार को रुपया में डालर के मुकाबले दो पैसे की तेजी रही थी। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड का वायदा मूल्य 2.42 प्रतिशत 75.69 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

सरकारी प्रयासों से ही मेक इन इंडिया हुआ सफल : गोयल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कारोबारी प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की सख्त नीति जैसे प्रयासों से ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम सफल हो सका। इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा जैसे कई उभरते हुए सेक्टर में भारत अब वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने की ओर अग्रसर है।

25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गोयल ने कहा कि हमने बीते 10 सालों में मैन्यूफैक्चरिंग में बेहतरीन सफलता हासिल की है। मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक जिला-एक उत्पाद, कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों से भी मेक इन इंडिया को मदद मिल रही है। हम समझते हैं कि बहुत ही बड़े पैमाने पर मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश आने वाला है जिससे लाखों की संख्या में नौकरियां निकलेंगी। हमारी अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी भी इससे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार दुनिया के 10 प्रमुख देशों में अपना कार्यालय खोलने जा रही है। उन्होंने दैनिक जागरण को बताया कि इसकी शुरुआत सिंगापुर से की गई है। दो दिन पहले ही वहां कार्यालय खोला गया है। जल्द ही दुबई, न्यूयार्क जैसे शहरों में ऐसे कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्य रूप से चार सेक्टर पर वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का यह कार्यालय फोकस करेगा। इनमें निवेश, व्यापार, टेक्नोलाजी और पर्यटन शामिल है। ये कार्यालय निवेशकों को भारत में जमीन से लेकर अन्य सभी कारोबारी सुविधाएं मुहैया कराने में मदद करेंगे।

पीयूष गोयल।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा ट्रेड, टेक्नोलाजी और टूरिज्म के प्रोत्साहन के लिए दुनिया के 10 बड़े शहरों में खुलेंगे निवेश कार्यालय

एसएंडपी ने 6.8% की विकास दर का अनुमान बरकरार रखा

नई दिल्ली, प्रेट्र : एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.8 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। साथ ही उम्मीद जताई है कि आरबीआइ अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए जारी आर्थिक परिदृश्य में रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.9 प्रतिशत रह सकती है। मजबूत विकास दर की बदौलत सरकार आरबीआइ को महंगाई दर को निर्धारित लक्ष्य 2-4 प्रतिशत के दायरे में लाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह सकती है। एसएंडपी ने कहा कि जून तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर धीमी रही, क्योंकि उच्च ब्याज दरों ने शहरी मांग को प्रभावित किया।

7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी आर्थिकी : मूडीज

मुंबई, आइएएनएस : मूडीज एनालिटिक्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। अपने नए एशिया-प्रशांत दृष्टिकोण में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने देश के विकास के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में 6.6 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान जताया है। मूडीज एनालिटिक्स ने भारत के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को पहले के पांच प्रतिशत से घटाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया है।

आरबीआइ गवर्नर बोले कीमत स्थिरता और वृद्धि के बीच संतुलन जरूरी

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को कहा कि कीमत स्थिरता और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देता है और इसके लिए 'बड़े स्तर पर वृद्धि के साथ समझौता करता है' तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की जरूरत पड़ सकती है।

दास ने काठमांडू में संबोधन में कहा कि आर्थिकी की मदद के लिए, केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति के साथ-साथ नियमन और निगरानी जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। उन्होंने नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आयोजित हिमालय शमशेर स्मृति व्याख्यान में कहा, 'मूल्य स्थिरता और वृद्धि के बीच संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मूल्य स्थिरता के लिए वृद्धि को छोड़ा जाता है।'

ईयू से एफटीए पर मेडिकल डिवाइस निर्माण होगा प्रभावित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घरेलू मेडिकल उपकरण निर्माताओं का मानना है कि यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से घरेलू स्तर का निर्माण प्रभावित होगा। मेडिकल उपकरण की घरेलू जरूरत की 70 प्रतिशत पूर्ति आयात से हो रही है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार कुछ माह पहले मेडिकल उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना भी लेकर आई थी। हालांकि ईयू के साथ एफटीए से मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना को भी धक्का लग सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ईयू के साथ एफटीए होने के बाद मेडिकल उपकरण बनाने वाला कोई भी देश खासकर चीन आसानी से भारत में बिना शुल्क के अपने उपकरण भेज सकेगा।

ईयू के नियम के मुताबिक वहां की मार्केटिंग कंपनियां किसी भी देश से माल लाकर उस पर ओरिजिन कंट्री के रूप में ईयू का लेवल लगा सकते हैं और फिर वह उत्पाद शुल्क के बिना भारत में प्रवेश कर जाएगा। एफटीए होने के बाद ईयू से आने वाले माल पर भारत में कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत जर्मनी, नीदरलैंड के बाद चीन से सबसे अधिक मेडिकल उपकरणों का आयात करता है। इस आशंका को लेकर संबंध में एसोसिएशन आफ इंडियन मेडिकल डेवाइस इंडस्ट्री (एआइएमईडी) ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। ईयू के साथ एफटीए के लिए गत सोमवार से नौवें चरण की बातचीत नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। एफटीए में मेडिकल उपकरणों को भी शामिल किया गया है।

एसोसिएशन के संस्थापक राजीव नाथ का कहना है कि कंट्री आफ ओरीजिन (मूल देश) पर ईयू का नाम तभी लिखा जाना चाहिए जब ईयू में उस उत्पाद पर कम से कम 35 प्रतिशत का वैल्यू एडिशन किया गया हो। भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित कंपनियों के मेडिकल उपकरणों को ही एफटीए के तहत भारत में शुल्क मुक्त आने की इजाजत मिले। भारत और अमेरिका किसी कंपनी को बिना वैल्यू एडिशन के अपना नाम कंट्री आफ ओरिजिन के रूप में लगाने की इजाजत नहीं देता है। पिछले चार सालों में मेडिकल उपकरण के आयात 68 प्रतिशत बढ़ा है।

- मेडिकल उपकरण कंपनियों ने मुक्त व्यापार समझौते पर जताई चिंता, सरकार को लिखा पत्र
- कुछ माह पहले मेडिकल उपकरण मैन्यूफैक्चरिंग प्रोत्साहन योजना लाई थी सरकार

कार्बन टैक्स को लेकर भारत की चिंता बरकरार

ईयू के साथ एफटीए वार्ता में कार्बन टैक्स या कार्बन बार्डर एडस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबैम) को लेकर भी सरकार की चिंता बनी हुई है। ईयू वर्ष 2026 के जनवरी माह से सीबैम के तहत कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा कर चुका है। इससे सीमेंट, स्टील, के साथ कई कृषि उत्पाद के निर्यात प्रभावित हो जाएंगे। अगर सीबैम के तहत ईयू टैक्स लगाने में कामयाब हो जाता है तो एफटीए के बावजूद भारत के कई आइटम के निर्यात पर ईयू में शुल्क लगेगा, जबकि एफटीए के बाद ईयू के आने वाले उत्पाद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

राष्ट्रीय फलक

ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

- उपराष्ट्रपति धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ
- 80 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा निवेशक होंगे शामिल

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के पैवेलियन में स्टाल तैयार करते कर्मचारी। जागरण

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आगाज बुधवार से इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा। पांच दिवसीय ट्रेड शो का शुभारंभ दोपहर करीब 12 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मंगलवार को प्रदेश सरकार में एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग व कपड़ा मंत्री राकेश सचान ने मार्ट पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ट्रेड शो को हर सितंबर में करने का निर्देश दिया है। अब वह प्रदेश के सभी मंडलों में ट्रेड शो के आयोजन करने की तैयारी में जुटे हैं। इससे प्रदेश के छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार मिलेगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य हैं जहां खुद का अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो होता है। प्रदेश की एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में यह अहम योगदान देगा। पिछले वर्ष ट्रेड शो में छह हजार करोड़ का व्यापार हुआ था। इस वर्ष यहां 80 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। देश-प्रदेश की पारंपरिक कारीगरी समेत विभिन्न विभागों के करीब 2,500 से अधिक स्टाल लगेंगे। 'एक जिला-एक उत्पाद' को भी बड़ा मंच मिलेगा।

दिखेगी वियतनाम की संस्कृति : इस बार ट्रेड शो में भागीदार देश वियतनाम है। ऐसे में दर्शकों को वियतनाम की संस्कृति, खान-पान के साथ व्यापारियों व उद्यमियों को वियतनाम के व्यापारियों के साथ रू-ब-रू होने का मौका मिलेगा। ट्रेड शो में अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण कर चुके हैं। यहां पर ओडीओपी खादी एवं ग्रामोद्योग, ग्राम्य विकास, संस्कृति एवं सूचना विभाग द्वारा उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा स्टार्टअप, ई-कामर्स, निर्यातक आदि विषयों पर तकनीकी सत्रों का भी आयोजन होगा।

पीयूष गोयल, जीतन राम मांझी भी करेंगे शिरकत : ट्रेड शो में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी आदि शिरकत करेंगे। वियतनाम के राजदूत गुयेन थान्ह भी समारोह में शामिल होंगे। इस बार दर्शक वियतनाम की समृद्ध संस्कृति, व्यंजन व अद्भुत उत्पादों को देख सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटान किया : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बजट में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा संशोधित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटान किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में कर न्यायाधिकरणों, हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा को बढ़ाया गया है। सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये किया गया है।

मंत्रालय ने कहा, 'अपील दाखिल करने की संशोधित मौद्रिक सीमा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रत्यक्ष कर से जुड़े 573 मामलों का निपटान किया। ये वे मामले हैं जहां कर प्रभाव पांच करोड़ रुपये से कम है।' इसमें कहा गया है कि यह कानूनी विवाद कम करने तथा व्यापार को और सुगम बनाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

फर्जी बिल बनाकर 135 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी, सात गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

48 फर्जी कंपनियां बना रखी थीं गिरोह ने, देशभर में दूसरी कंपनियों को देते थे फर्जी बिल

फर्जी कंपनियों के नाम से बिल बनाकर जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने राजफाश किया है। गिरोह ने पांच वर्ष में 48 फर्जी कंपनियां बनाकर 925 करोड़ रुपये के फर्जी बिल काटे और 135 करोड़ रुपये की जीसएटी चोरी कर ली। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। फर्जी बिल बनाने में कमीशन की रकम हवाला के माध्यम से ली जाती थी।

मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह के अनुसार रतनपुरी थाना क्षेत्र के अश्विनी ने गत दो सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस थाने में केस दर्ज कराते हुए बताया था कि कुछ लोगों ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि कागजात से फर्जी कंपनी बना ली और फर्जी बिल बनाकर जीएसटी चोरी की है। 248 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के बाद मंगलवार को जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह में शामिल सात आरोपित तस्लीम, जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी, आसिफ, मोइन व अजीम को गिरफ्तार कर लिया गया। तस्लीम का भाई वहादत फरार है।

एसएसपी ने बताया कि 12वीं कक्षा पास तस्लीम गिरोह का मास्टरमाइंड है। यह गिरोह बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच देकर उनसे कागजात लेता था और बीटेक पास आरोपित अजीम युवकों की फर्जी केवाईसी कराकर उनके नाम से जीएसटी में फर्म पंजीकृत करा लेता था। इसके बाद यह गिरोह पूरे देश में स्क्रैप और कबाड़ का काम करने वाले ऐसे व्यापारियों की तलाश करता था, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता था। ऐसे कारोबारियों को फर्जी कंपनी का बिल देकर जीएसटी चोरी की जाती थी।

सेवा में कमी को लेकर एतिहाद एयरवेज यात्री को देगा मुआवजा

रीतिका मिश्रा ● जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एतिहाद एयरवेज को स्वीडन की एक नागरिक को उसका केबिन बैग मिलने में देरी के लिए सेवाओं में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने एतिहाद एयरवेज को मुआवजे के लिए दो माह के अंदर 50 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल व सदस्य जेपी अग्रवाल की पीठ ने साथ ही कहा कि अगर एयरवेज इस राशि का भुगतान 17 नवंबर तक शिकायतकर्ता नहीं करता है तो नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

शिकायतकर्ता आशा देवी ने शिकायत में कहा कि वह स्वीडन की नागरिक हैं और पीआइओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) वीजा के तहत दिल्ली में रह रही हैं। स्वीडन से दिल्ली आने के लिए एतिहाद एयरवेज का टिकट खरीदा था। एयरहोस्टेस ने ओवरहेड केबिन लाकर में जगह की कमी के कारण केबिन बैग को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का सुझाव दिया। बाद में एयरहोस्टेस ने खुद ही उनका सामान दूसरी जगह रख दिया।

दिल्ली उतरने पर भी उन्हें बैग नहीं मिला तो उन्हें इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने आइजीआइ परिसर में एतिहाद एयरवेज काउंटर पर खोए हुए केबिन बैगेज के लिए एक आवेदन जमा किया। उन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि उनका सामान उनके पास पहुंच जाएगा। महिला ने कहा कि कई दिन के बाद एक कोरियर वाला उनके बैग को प्लास्टिक में लपेट कर लाया, लेकिन बैग में रखी 24 लाख स्वीडिश करेंसी, सोने की चेन, राडो की घड़ी, सोनी हैंडफोन गायब थे। उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की लेकिन कोई मदद नहीं मिली।

जीएसटी चोरी करने वाली 10,700 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : टैक्स अधिकारियों ने सरकारी खजाने को चपत लगाने के लिए बनाई गई बड़ी संख्या में फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने जीएसटी के तहत करीब 10,700 फर्जी पंजीकरण का पता लगाया है, जिनमें 10,179 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी शामिल है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के सदस्य शशांक प्रिय ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण पहले से ही 12 राज्यों में लागू है और चार अक्टूबर तक अन्य चार राज्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित 20 राज्य आधार प्रमाणीकरण शुरू करेंगे। एसोचैम के एक कार्यक्रम में शशांक प्रिय ने कहा कि भविष्य में टैक्स अधिकारी नए करदाताओं पर उनके जोखिम प्रोफाइल के आधार पर कुछ पाबंदियां भी लगा पाएंगे।

वाइब्रेंट विलेज योजना से जादूंग गांव में बन रहा इतिहास

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी

- राज्यपाल ने किया चीन सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग का भ्रमण
- कहा, वाइब्रेंट विलेज योजना पर दुनिया की नजर, चीन भी सैटेलाइट से देख रहा

राज्यपाल ले. जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह ने जादूंग गांव का भ्रमण किया। जादूंग में बनाए जा रहे होमस्टे के नक्शे और निर्माण का भी अवलोकन किया। जागरण

वाइब्रेंट विलेज योजना पर दुनिया की नजर है। चीन भी सैटेलाइट के माध्यम से इसे देख रहा है। इस क्रांतिकारी कदम से सीमा प्रबंधन की धारणा बदल गई है। ये बातें उत्तराखंड के राज्यपाल ले. जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी जनपद में चीन सीमा पर स्थित वाइब्रेंट विलेज नेलांग और जादूंग के भ्रमण के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जादूंग को फिर से बसाने का कार्य वैसे तो 60 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शानदार विजन से अब यहां इतिहास बन रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना से सीमावर्ती जादूंग अब प्रथम गांव बन गया है। प्रथम श्री गणेश होता है। प्रथम को गोल्ड मेडल और पुरस्कार दिया जाता है, जादूंग को भी यही दिया जाएगा।

राज्यपाल मंगलवार को दो दिवसीय भ्रमण पर उत्तरकाशी जनपद की हर्षिल घाटी पहुंचे। यहां सुबह सेना के सम्मेलन में प्रतिभाग के बाद उन्होंने नेलांग और जादूंग का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल ने जादूंग को फिर से आबाद करने के लिए यहां बनाए जा रहे होमस्टे का निरीक्षण किया। प्रथम चरण में यहां छह होमस्टे बनाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने जादूंग में विकास कार्यों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कार्यदायी संस्था और यहां कार्य कर रहे श्रमिकों को प्रोत्साहित भी किया।

राज्यपाल ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर वह कुछ समय पहले नई दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा भी शामिल था। देशभर में 2,751 वाइब्रेंट विलेज चिह्नित किए गए हैं। इनमें उत्तराखंड के 51 गांव शामिल हैं, जिसमें से 17 गांवों को फिर से जीवंत बनाने के लिए पहले चरण के विकास कार्य शुरू हो गए हैं।

आइटीबीपी चीन के लिए बड़ा संदेश : राज्यपाल ने नेलांग में सेना के जवानों और जादूंग में आइटीबीपी के हिमवीरों से बातचीत कर सीमा के इन प्रहरियों का मनोबल बढ़ाया। आइटीबीपी के जवानों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जादूंग गांव अंतिम पोस्ट है। अंतिम पोस्ट पर सेवा करने का अलग ही मजा होता है। आप भाग्यशाली हैं, जो अंतिम पोस्ट पर सेवा का अवसर मिला है। आपकी सतर्कता से कोई हमारी जमीन पर अपनी अंगुली भी नहीं रख सकता। राज्यपाल ने कहा कि चीन ने गत वर्षों में सिक्किम और गलवन में गलत हरकत की हैं। इसलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आइटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चीन के लिए बड़ा संदेश है कि हम यहां चीन से नहीं, बल्कि तिब्बत से सीमा साझा करते हैं।

****

1164 मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में दर्ज किए गए लाहौर में इस वर्ष। सिंध में दर्ज मामलों की संख्या 2023 में 10,201 तक पहुंच गई, जो 2022 में दर्ज 8,787 मामलों से 16 प्रतिशत अधिक है।

इजरायल के भीषण हमले में मारा गया हिजबुल्ला का एक और कमांडर

इजरायल का लेबनान में दूसरे दिन भी हमला, अब तक 569 मारे गए, 1835 लोग घायल

लेबनान में हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना

- इजरायल ने कहा-ईरान समर्थित संगठन को नहीं देंगे कोई मौका
- हिजबुल्ला ने भी कई इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले का किया दावा

लेबनान में इजरायली हमले में ध्वस्त भवन। एएफपी

बेरूत, रायटर : इजरायल का लगातार दूसरे दिन भी लेबनान में हमला जारी रहा। उसने मंगलवार को कई हवाई हमले किए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला का एक और वरिष्ठ कमांडर मारा गया। वह ईरान समर्थित इस संगठन के मिसाइल और राकेट इकाई का प्रमुख था। इजरायली सेना सोमवार से लेबनान में हवाई हमले कर रही है। उसने अपने इस पड़ोसी देश में हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इन हमलों में अब तक 569 लोग मारे गए और 1835 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि वह हिजबुल्ला को कोई मौका नहीं देगी। जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा।

बेरूत के दक्षिणी उपनगर में मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर की पहचान इब्राहिम कुबैसी के रूप में की गई है। इस हमले में छह लोगों के मारे जाने की खबर है। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संगठन पर बढ़ते दबाव से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध भड़क सकता है। इस क्षेत्र में पहले से ही इजरायल और हिजबुल्ला के सहयोगी हमास के बीच गाजा में एक वर्ष से संघर्ष चल रहा है। इजरायली सेना के अनुसार, ताजा हमले में लेबनान की ओर से 55 राकेट उत्तरी इजरायल की ओर दागे गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर को नष्ट कर दिया गया। जबकि हिजबुल्ला ने एक विस्फोटक फैक्ट्री समेत कई इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया।

कूटनीतिक समाधान की मांग : क्षेत्र में गहराते संकट का कूटनीतिक समाधान निकालने की मांग तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने सभी देशों से लेबनान में बढ़ते तनाव को रोकने का प्रयास करने का आग्रह किया है। जबकि इजरायल के करीबी सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा, 'मेरा मानना है कि हम इजरायल और लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव का कूटनीतिक समाधान निकाल सकते हैं।' वहीं इजरायल की ओर से गाजा पट्टी में किए गए हवाई हमले में 22 फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है।

रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर फिर किया हमला

- पोल्टावा में 20 बस्तियों में बिजली गुल, खारकीव पर हमले में पांच लोग घायल
- रूस को विदेश से मिल रहे 60 प्रतिशत रक्षा उपकण चीन के रास्ते आ रहे : यूक्रेन

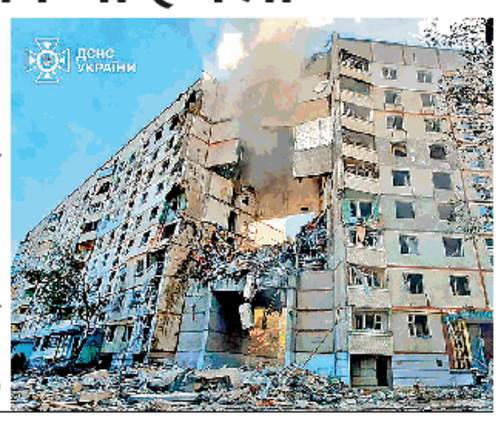

यूक्रेन के खारकीव में मंगलवार को रूसी हमले में क्षतिग्रस्त बहुमंजिला भवन। एपी >>

कीव, रायटर : रूस ने सोमवार रात यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को फिर निशाना बनाया। यूक्रेनी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सेंट्रल रीजन के पोल्टावा में ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले से 20 बस्तियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ड्रोन के मलबे गिरने से कई इमारतें नष्ट हो गईं। इसके साथ ही मंगलवार को खारकीव पर भी गाइडेड बम से हमला किया।

जपोरीजिया के रीजनल गवर्नर इवान फेदोरोव ने कहा कि जपोरीजिया पर हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम सात लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने दावा किया उसने रूस के 81 में 66 ड्रोन मार गिराये, अन्य ड्रोन व चार मिसाइलों को ट्रैक नहीं किया जा सका।

वहीं रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने वुहलेदर शहर पर हमला शुरू कर दिया है। फरवरी, 2022 में रूसी आक्रमण के बाद से ही इस शहर से रूस का कड़ा प्रतिरोध होता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उसका प्रारंभिक रणनीतिक लक्ष्य दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करना है। इस समय यूक्रेन का पांचवां हिस्सा रूस के कब्जे में है, इसमें डोनबास का 80 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है। इस बीच, यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने मंगलवार को संबाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में विदेश से आने वाले 60 प्रतिशत हथियारों के पुर्जे चीन के रास्ते आ रहे हैं।

पाकिस्तान सीनेट का पूर्व कर्मचारी ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सीनेट के एक पूर्व कर्मचारी तौसीफ शहजाद को मंगलवार को ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि शहजाद पर अपने फेसबुक पेज पर हजरत मुहम्मद का अपमान करने का आरोप है। पाकिस्तान में ईश निंदा के लिए उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रविधान है। बता दें, पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में ईशनिंदा के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

शहजाद लाहौर से 240 किमी दूर चीचावतनी शहर का निवासी है। एफआइआर के अनुसार, उप निरीक्षक शमसुल हसन ने नाइट ड्यूटी के दौरान फेसबुक खोला और शहजाद के अकाउंट में ईश निंदा करने वाला पोस्ट पाया। हसन की शिकायत पर ईश निंदा का मामला पंजीकृत किया गया। उसकी पत्नी और तीन बच्चों को लोगों की हिंसक प्रतिक्रिया से बचाने के लिए हिरासत में लिया गया है।

ईश निंदा संदिग्ध की हत्या के विरोध में धरने का आह्वान : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ईश निंदा के संदिग्ध शाह नवाज कुनभर की पुलिस मुठभेड़ के बहाने की गई हत्या के विरोध में सिंध यूथ एक्शन कमेटी ने बुधवार को उमरकोट में धरना देने की घोषणा की है। कमेटी ने कुनभर के लिए न्याय की मांग की है।

न्यूज गैलरी

सिंगापुर में भारतवंशी पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार में दोषी ठहराए गए

सिंगापुर : सिंगापुर के भारतवंशी पूर्व परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को मंगलवार को सरकारी सेवक के रूप में मूल्यवान चीजें लेने और न्याय में बाधा डालने का दोषी ठहराया गया। 62 वर्षीय ईश्वरन को तीन अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। कई महीने तक स्वयं को निर्दोष साबित करने के प्रयास के बाद सुनवाई के पहले दिन ईश्वरन ने दोष स्वीकार कर लिया। 50 वर्षों में किसी मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार दोषी ठहराए जाने का यह पहला मामला है। (प्रेट्र)

जार्जिया सीनेट के लिए भारतवंशी प्रत्याशी का समर्थन

वाशिंगटन : संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत एंड्रयू यंग ने जार्जिया प्रांतीय सीनेट के लिए चुनाव में प्रत्याशी जेनरेशन जेड के भारतवंशी डेमोक्रेट अश्विन रामास्वामी का समर्थन करने की घोषणा की है। यंग अटलांटा के मेयर भी रह चुके हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो रामास्वामी देश में पहले जेनरेशन जेड के भारतवंशी विधायक होंगे। रामास्वामी के माता-पिता 1990 में तमिलनाडु बस गए थे। (प्रेट्र)

ईरान में खदान दुर्घटना में सभी बचे हुए श्रमिकों की मौत

तेहरान : ईरान ने मंगलवार को कहा कि उसे लगता है कि देश के पूर्वी भाग की एक कोयला खदान में शनिवार को मीथेन गैस लीक से हुए विस्फोट के बाद फंसे बाकी श्रमिकों की मौत हो गई है। इसके साथ ही त्रासदी में मरने वालों की 49 हो गई है। प्रांतीय आपदा अधिकारी मोहम्मद अली अखैंडी ने सरकारी टेलीविजन पर ताबास की कोयला खदान में मारे गए लोगों की संख्या की जानकारी दी। (एपी)

तटरक्षकों के दुर्व्यवहार के विरोध में धरना जारी

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी तटरक्षकों के विरोध में ग्वादर में पांचवें दिन भी धरना जारी रहा। धरने के कारण क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। अल्टीमेटम की अवधि बीत गई, लेकिन अधिकारियों ने शिकायतों का समाधान नहीं किया। इसके बाद स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन की अगुआई में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तनाव बढ़ने के कारण मकरान तटीय राजमार्ग और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मार्गों समेत कई प्रमुख राजमार्ग बंद हैं। (एएनआइ)

दिल्ली में पढ़ी हरिनी बनीं श्रीलंका की प्रधानमंत्री

कोलंबो में मंगलवार को श्रीलंका की प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हरिनी अमरसूर्या। रायटर

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने मंगलवार को संसद को भंग करने के साथ विशेष गजट अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए। संसद भंग करने का आदेश मंगलवार आधी रात से प्रभावी हो गया है और संसदीय चुनाव आगामी 14 नवंबर को होंगे। दिल्ली में पढ़ी हरिनी अमरसूर्या को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और चार सदस्यीय नई कैबिनेट में राष्ट्रपति के अलावा दो अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं।

एस. भंडारनायके के निधन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली हरिनी अमरसूर्या (54), श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली और इस पद तक पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता हैं। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद दिनेश गुणवर्धने ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कालेज से समाज विज्ञान में स्नातक करने के बाद हरिनी ने आस्ट्रेलिया से एप्लाइड एंथ्रोपोलाजी में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की और एडनबर्ग विश्वविद्यालय से सामाजिक मानविकी में पीएचडी की। वह श्रीलंका विश्वविद्यालय में व्याख्याता रही हैं।

बीते शनिवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिसानायके ने कहा था कि वह संसद को भंग कर देंगे और तत्काल चुनाव का आदेश देंगे। इससे पहले मंगलवार को दिसानायके ने स्वयं समेत चार सदस्यीय कैबिनेट नियुक्त की। इनमें हरिनी के अलावा एनपीपी सांसदों में विजिता हेरात और लक्ष्मण निपुणार्चा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।

अनुरा कुमारा दिसानायके ने मंगलवार को कहा कि वह 2019 के ईस्टर संडे आतंकी हमले की जांच फिर से कराएंगे। आतंकियों ने सिलसिलेवार बम विस्फोट किए थे जिसमें 11 भारतीय समेत 270 की मौत हो गई थी।

पेशे से अध्यापिका, अब पीएम

छह मार्च, 1970 को जन्मीं एनपीपी सांसद हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री हैं। वह 2020 में एनपीपी राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद सदस्य (एमपी) बनीं थीं। पेशे से एक विश्वविद्यालय व्याख्याता और एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर हरिनी अमरसूर्या ने समाजशास्त्र में बीए (आनर्स) और मानवविज्ञान और विकास अध्ययन में एमए किया है। वह श्रीलंका की पहली ऐसी प्रधानमंत्री बन गई हैं, जो पेशे से अध्यापिका हैं। उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सामाजिक मानवविज्ञान में पीएचडी भी की है। श्रीलंका की संसद की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नौवीं संसद (2020-2024) में वह 269 दिन उपस्थित रहीं और 120 दिन अनुपस्थित रहीं थीं।

पश्चिम एशिया और यूक्रेन में अब भी शांति संभव : बाइडन

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएन से चीन को दिया कड़ा संदेश

कहा-हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारियों को प्रगाढ़ करते रहेंगे

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के मंच से कहा कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में अब भी शांति संभव है। वाशिंगटन को दुनिया की मदद से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब लेबनान में इजरायल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान एक वर्ष से जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वाशिंगटन पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने गठबंधनों और साझेदारियों के नेटवर्क को मजबूत करना जारी रखेगा। यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। उन्होंने यह भी बाइडन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अंतिम बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हमें अपने सिद्धांतों को भी बरकरार रखना होगा, क्योंकि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं, ताकि यह संघर्ष में न बदल जाए।' उन्होंने यूएन महासभा के 79वें सत्र में अपने संबोधन में कहा, अमेरिका अनुचित आर्थिक प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध और दक्षिण चीन सागर में अन्य देशों पर सैन्य दबाव के विरुद्ध आगे बढ़ रहा है। ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के साथ ही अपनी सबसे उन्नत प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा भी कर रहे हैं ताकि इनका उपयोग हमारे या हमारे किसी साझेदार के खिलाफ न हो सके।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने हालिया क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद यह बात कही है। अमेरिका में गत शनिवार को हुए इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा आस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने चेतावनी दी है कि असमानता व अनिश्चितता अस्थिर विश्व का निर्माण कर रहे हैं। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उन्होंने यह बात राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अन्य नेताओं की मौजूदगी में यूएन महासभा का सत्र शुरू होने के मौके पर कही।

सुरक्षा परिषद में सुधार की दिशा में अच्छी शुरुआत : भारत

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में सुरक्षा परिषद में सुधार पर पहली बार एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया जाना एक अच्छी शुरुआत है। नई दिल्ली 15 देशों के निकाय में सुधार के लिए एक निश्चित समय सीमा में वार्ता की शुरुआत की आशा करती है।

सऊदी अरब ने भिखारियों को लेकर पाक को दी चेतावनी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : सऊदी अरब ने उमराह की आड़ में आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने पाकिस्तान से ऐसे लोगों पर खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है। सूत्रों का हवाला देते हुए एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने अपनी खबर में बताया कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका पाकिस्तान के उमराह और हज यात्रियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। चेतावनी के बाद पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उमराह अधिनियम लाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य उमराह की व्यवस्था करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को कानूनी निगरानी के तहत लाना है। इससे पहले, सऊदी राजदूत नवाफ बिन सैद अहमद अल-मलिकी के साथ बैठक में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सऊदी अरब में भिखारी भेजने के लिए जिम्मेदार माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पाकिस्तान में परिवार के सामने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

- कार रोक कर लूटपाट के बाद किया सामूहिक दुष्कर्म

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान में एक परिवार के सामने नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पंजाब प्रांत में लुटेरों ने कार सवार एक परिवार को रोक कर उनके साथ लूटपाट की और 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना का सं प्रांत की मुख्यमंत्री मरयम नवाज ने पुलिस को 48 घंटे के अंदर दोषियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर पाकपट्टम शहर में हुई। यहां बाबा फरीद समेत कई ऐतिहासिक सूफी दरगाह हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी, दो बच्चों और 17 वर्षीय भतीजी के साथ कार से अपने गृहनगर बहावलनगर लौट रहा था। यह परिवार पाकपट्टम में अपने एक रिश्तेदार के घर गया था। चार सशस्त्र लुटेरों ने उनकी कार का पीछा किया। एफआइआर के अनुसार, लुटेरों ने पहले उनसे सोने के गहने, मोबाइल फोन, नकदी और कार की चाबी छीन ली। इसके बाद लड़की को जबरन सड़क किनारे खेत में ले गए। दो लुटेरों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जबकि दो लुटेरों ने परिवार को बंदूक के बल पर बंधक बनाए रखा। इस दौरान परिवार के सदस्य मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पाकिस्तान में 2020 भी इसी तरह की सनसनीखेज वारदात हुई थी। लाहौर मार्ग पर एक पाकिस्तानी मूल की फ्रांसीसी महिला से उसके दो बच्चों के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके विरोध में पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे।

एक रिपोर्ट के अनुसार, फैसलाबाद में 2023 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 728 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दुष्कर्म, अपहरण और आनर किलिंग की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

न्यूयार्क में यूनुस के खिलाफ वापस जाओ के लगे नारे

न्यूयार्क, एएनआइ : 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस को सोमवार देर रात न्यूयार्क में अपने होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। न्यूयार्क में आधिकारिक होटल में उनके आगमन से पहले प्रदर्शनकारियों ने मुहम्मद यूनुस के खिलाफ वापस जाओ के नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भी यूनुस के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय मीडिया दल ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उनका जवाब देने से भी परहेज किया। प्रसारित वीडियो में यूनुस के सुरक्षाकर्मी पत्रकारों को दूर रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि यूनुस वापस जाओ, पद छोड़ो। वह हाथों में बैनर थामे हुए थे जिन पर लिखा था कि शेख हसीना हमारी प्रधानमंत्री हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 84 वर्षीय यूनुस ने असंवैधानिक, अवैध रूप से बांग्लादेश की सत्ता हासिल की।

पीएम मोदी व ट्रंप की नहीं हो पाई मुलाकात

न्यूयार्क, आइएएनएस : अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। ट्रंप ने ही यह घोषणा की थी कि अमेरिका यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। लेकिन यह मुलाकात नहीं हो पाई। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहे। उनकी करीब 55 घंटे की यह यात्रा काफी व्यस्त रही। जबकि ट्रंप भी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। अमेरिका में पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वह रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने गत 17 सितंबर को कहा था कि वह अगले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। उन्होंने पीएम मोदी की खूब प्रशंसा की थी और विलक्षण व्यक्ति बताया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले शनिवार को अमेरिका पहुंचे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मेजबानी में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें आस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। पीएम मोदी की इन नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री ने रविवार को न्यूयार्क में भारतवंशियों के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके अलावा कई बैठकें कीं।

राष्ट्रीय फलक

संभल में प्रेमी को फंसाने के लिए दुष्कर्म पीड़ित बहन की हत्या

जागरण संवाददाता, संभल : मां के साथ गाजियाबाद से संभल आ रही दुष्कर्म पीड़ित किशोरी की हत्या के पीछे आनर किलिंग का मामला निकला। उसकी मां व दो भाइयों ने मामा के साथ मिलकर हत्या की थी। इसके बाद भाई ने किशोरी के प्रेमी और उसके मामा पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। अब पुलिस ने किशोरी के दो भाइयों और उसकी मां को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया। आरोपित मामा फरार है। स्वजन ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि किशोरी के प्रेम-प्रसंग के चलते उनकी काफी बदनामी हो रही थी, इसलिए हत्या का षड्यंत्र रचा और गांव ले जाकर उसे गोली मार दी।

18 सितंबर की रात 10 बजे तेज बरसात के दौरान कैलादेवी क्षेत्र के एक गांव की किशोरी मां के साथ साहिबाबाद (गाजियाबाद) से आ रही थी। दोनों को लेने के बहाने भाई बस स्टैंड तक गया था। रास्ते में किशोरी की हत्या कर दी गई। भाई ने प्राथमिकी में कहा था कि गांव का रिंकू अपने मामा के साथ कार से आया। कार की टक्कर से बाइक को गिरा दिया। बहन को बाल पकड़कर खींचा और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। रिंकू के साथ किशोरी का प्रेम-प्रसंग था। उसके साथ छह माह पूर्व वह फरार हो गई थी।

आनर किलिंग के शक में किशोरी के स्वजन से अलग-अलग पूछताछ की गई तो मामले का राजफाश हुआ। पूछताछ में हत्यारोपितों ने बताया कि किशोरी के प्रेम-प्रसंग के चलते उनकी काफी बदनामी हो रही थी। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह कर किशोरी का हत्या में प्रेमी रिंकू और उसके मामा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।

पेंशन के लिए नंगे पांव दो किमी रेंगकर पहुंचीं 70 वर्षीय वृद्धा, वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित

जागरण संवाददाता, अनुगुल

- ओडिशा के मुख्यमंत्री के गृहजिले की बीमार वृद्धा की बेबसी ने व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
- वीडियो प्रसारित होने के बाद जागा प्रशासन, उपलब्ध कराई व्हील चेयर, घर तक पहुंचेगी पेंशन

क्योंझर में पेंशन लेने को पैर-हाथ के बल घिसटते हुए पंचायत कार्यालय जातीं पथुरी। वीडियो ग्रैब

ओडिशा के क्योंझर में खड़े होने से लाचार एक 70 वर्षीय वृद्धा के पेंशन लेने के लिए नंगे पांव रेंगकर चलते हुए दो किलोमीटर दूर पंचायत कार्यालय पहुंचने का दृश्य सामने आया है। बीमार बुजुर्ग महिला की पहचान पथुरी देहुरी के रूप में हुई है, वह उम्रजनित बीमारी के कारण चल नहीं सकतीं। गांव की सड़क पर घुटनों के बल रेंगते हुए देहुरी का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित है। इसमें वह ऊंकडू बैठकर हाथ और पैर दोनों का सहारा लेकर कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इस घटना ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन वितरण प्रणाली की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। खास बात यह है कि महिला ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के गृह जिले क्योंझर के गांव की रहने वाली हैं।

बता दें कि ओडिशा सरकार ने कुछ दिन पहले बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों की पेंशन उनके घर तक पहुंचाने का निर्देश जारी किया था। देहुरी के अनुसार, पंचायत के एक अधिकारी ने उन्हें मासिक पेंशन लेने के लिए कार्यालय जाने के लिए कहा था। इस कारण उन्हें वहां पहुंचने के लिए घुटनों के बल रेंगकर जाना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार महिला के पास वहां पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं था।

तेलकोई ब्लाक विकास अधिकारी गीता मुर्मू ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन पहले वृद्धा के बैंक खाते में भेजी जाती थी। बाद में बीमार हो जाने पर उन्होंने बैंक जाने में असमर्थता जताई तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें हाथ से पेंशन देना शुरू कर दिया है। बीडीओ ने कहा कि अब पंचायत अधिकारी को हर महीने देहुरी को उनके घर जाकर वृद्धावस्था पेंशन वितरित करने के लिए कहा गया है। बीडीओ ने कहा कि उन्हें एक व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराई गई है।

****

मोदी की तारीफ पर तीन का अपहरण, इस्लामी नारे लगवाकर सड़क पर फेंका

जागरण संवाददाता, रामपुर

- रामपुर की घटना से दो संप्रदायों के बीच तनाव, पुलिस कर रही जांच
- शार्ट वीडियो बनाते समय मोदी की तारीफ किए जाने से थे खफा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए जय श्रीराम का जयघोष करने की रील (शार्ट वीडियो) बनाना उत्तर प्रदेश के रामपुर में तीन हिंदू युवाओं को महंगा पड़ गया। मुस्लिम युवकों ने कार से उनका अपहरण कर लिया। उनके साथ मारपीट की और इस्लामी नारे लगवाए। इसके बाद दो किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक गए। पीड़ित युवाओं ने तहरीर दी है। दो संप्रदायों के बीच का मामला होने पर तनाव की स्थिति बनी है।

जिले के मसवासी क्षेत्र के चंचल दिवाकर, प्रद्युम्न दिवाकर और सोनू दिवाकर रील बनाने के शौकीन हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए रील बनाई। इस बीच वह जय श्रीराम का जयघोष भी कर रहे थे। रील को फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर दिया। इससे गांव के कुछ मुस्लिम युवक खफा हो गए। उन्होंने पहले गांव में ही विरोध किया। इसके बाद मंगलवार को सुबह 11 बजे कई लोग कार से आए और तीनों को जबरन कार में डालकर ले गए। उनके साथ कार में मारपीट की गई। कई थप्पड़ मारे। इसके बाद इस्लामी नारे लगवाए गए। दो किलोमीटर दूर हाईवे किनारे फेंककर फरार हो गए। पीड़ितों ने मामले की जानकारी स्वजन को दी। मंगलवार की शाम उन्होंने पुलिस चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई। साथ ही नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की। अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर में

भारत ने मालदीव 3-0 से को हराया

थिंपू : स्थानापन्न खिलाड़ी हेमनीचुंग लंकिम के दूसरे हाफ में किए गए दो गोल की मदद से भारत ने मंगलवार को सैफ अंडर-17 फुटबाल चैंपियनशिप में मालदीव को 3-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। चांगलीमिथांग स्टेडियम में ग्रुप ए के अपने दूसरे और अंतिम मैच में सैमसन अहोंगशांगबाम ने 14वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई जबकि लंकिम ने 74वें और 89वें मिनट में गोल किए। इस जीत से भारत ग्रुप ए में छह अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत ने इससे पहले बांग्लादेश को 1-0 से हराया था। (प्रेट्र)

त्रीसा और गायत्री मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में

मकाऊ: त्रीसा जाली और गायत्री गोपीचंद की तीसरी वरीय भारतीय जोड़ी ने जापान की अकारी साता और माया तागुची की जोड़ी को मंगलवार को तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में हराकर मकाऊ ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी ने 15-21, 21-16, 21-14 से जीत दर्ज की। एन सिक्की रेड्डी व रुतविका शिवानी की जोड़ी ने महिला डबल्स क्वालीफिकेशन क्वार्टर फाइनल में चेयुंग यान यू और च्यु विंग ची की जोड़ी को 21-15, 21-10 से हराया। (प्रेट्र)

भारतीय हाकी टीम दो मैचों में जर्मनी की मेजबानी करेगी

नई दिल्ली : भारतीय पुरुष हाकी टीम 23 और 24 अक्टूबर को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जर्मनी के साथ दो मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेलेगी। हाकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने मंगलवार को कहा कि जर्मनी के विरुद्ध यह द्विपक्षीय सीरीज विश्व स्तरीय हाकी का उल्लेखनीय प्रदर्शन होगी। भारत और जर्मनी दोनों का खेल में एक समृद्ध इतिहास है और सीरीज प्रशंसकों को दुनिया की दो मजबूत टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने का अवसर देगी। (प्रेट्र)

पैरालिंपिक पदक विजेताओं को मिलेंगे 50 लाख रुपये

नई दिल्ली : भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआइ) ने पिछले महीने पेरिस पैरालिंपिक में पदक जीतने वाले देश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए कुल 50 लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक जीते थे। पुरुष सिंगल्स स्वर्ण जीतने वाले नितेश कुमार को 15 लाख रुपये, जबकि रजत पदक विजेता सुहास यतिराज और तुलसीमति मुरुगेसन को 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेता मनीषा रामदास और नित्या श्रीसिवन प्रत्येक को 7.50 लाख रुपये मिलेंगे। (प्रेट्र)

डेविस कप के लिए स्पेन की टीम में अलकराज-नडाल

मैड्रिड: स्पेन ने नवंबर में मलागा में खेले जाने वाले डेविस कप फाइनल्स के लिए राफेल नडाल और कार्लोस अलकराज को टीम में शामिल किया है। स्पेन 19-24 नवंबर को डेविस कप फाइनल्स के क्वार्टर फाइनल दौर में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। नडाल ने पेरिस ओलिंपिक के बाद से नहीं खेला है और उन्होंने चोट के कारण यूएस ओपन और लेवर कप से नाम वापस ले लिया था। वहीं, विश्व नंबर एक जानिक सिनर इटली की टीम का नेतृत्व करेंगे। (आइएएनएस)

गंगा तीरे, गेंद उछलेगी धीरे-धीरे

- ग्रीन पार्क स्टेडियम में नहीं मिलेगा स्पिन ट्रैक
- गेंदबाजों को टेस्ट के पहले दिन से मिलेगा उछाल

अभिषेक त्रिपाठी ● जागरण

कानपुर : लाल मिट्टी की पिच पर खेले गए चेन्नई टेस्ट मैच में शुरुआत में तेज गेंदबाजों तो बाद में भारतीय स्पिनरों का दबदबा रहा। अब भारतीय टीम 27 सितंबर से बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरा टेस्ट मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बनी काली मिट्टी की पिच पर खेलेगी। अभी तक यहां की पिच पर हुए अधिकतर टेस्ट मैचों में पिच पर उछाल कम ही देखने को मिली है लेकिन पिच के कायाकल्प के बाद इस पर बेहतर उछाल की उम्मीद जताई जा रही है।

भारतीय टीम प्रबंधन के कुछ लोग गंगा किनारे बने इस स्टेडियम में टेस्ट मैच खेलने के पक्ष में नहीं थे लेकिन बीसीसीआइ की नीति के कारण उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) को दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी दी गई। यूपीसीए ने भी टेस्ट मैच को लेकर पूरी तैयारी की है और मैच ग्रीन पार्क में ही कराने का निर्णय हुआ। महेंद्र सिंह धौनी और विराट कोहली की कप्तानी में जब भारतीय टीम घर में टेस्ट मैच खेलती थी तो काफी स्पिन ट्रैक देखने को मिलते थे। उस समय कई टेस्ट मैच दो से ढाई दिन में भी समाप्त हुए और शुरुआती ओवरों में ही स्पिनर लगा दिए जाते थे लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में अखाड़ा बनाने की जगह टीम स्पोर्टिंग विकेट पर ज्यादा खेलते दिखाई दे रही है। भारतीय टीम प्रबंधन अतिरिक्त स्पिन वाले ट्रैक को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। इस वर्ष इंग्लैंड के साथ हुई सीरीज में यह देखने को मिला था।

मुख्य पिच क्यूरेटर शिवकुमार ने दैनिक जागरण से कहा कि यह स्पिन ट्रैक तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसा कि पहले देखने को मिलता था। गेंद ज्यादा टर्न नहीं करेगी, स्पिनरों को एक या दो दिन बाद मदद मिलेगी। इस पिच पर पहले से उछाल बेहतर होगा और बल्लेबाजों को शाट खेलने में दिक्कत नहीं होगी। ग्रीन पार्क को लेकर जो एक धारणा है, इस बार यहां की पिच उससे बिल्कुल अलग होने वाली है। ग्रीन पार्क में अंतिम टेस्ट मैच 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था और वह भी काफी रोमांचक मैच हुआ था। अंतिम दिन मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था।

शिवकुमार के अनुसार, अगर मैच से पहले वर्षा भी होती है तो पिच पर नमी का असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वर्षा होने के बाद धूप खिलने पर पिच बेहतर तरीके से खेलेगी। सर्दी के मौसम में अगर वर्षा होती है तो पिच पर नमी होती है, लेकिन ऐसे मौसम में पिच धूप निकलने पर जल्द सूख जाती है। इस बार ग्रीन पार्क में आउटफील्ड के साथ ही पिच भी नए सिरे से तैयार की गई है। शिवकुमार ने बताया कि चार महीने पहले से ही प्रैक्टिस पिच सहित ही मुख्य पिच का नवीनीकरण किया गया है। कुल 15 पिचें ग्रीन पार्क में हैं। पिच स्क्वायर को फिर से तैयार किया गया है। स्टेडियम के गंगा किनारे होने के कारण पिच पर असर के बारे में क्यूरेटर ने कहा कि इसका इतना असर नहीं होता क्योंकि पानी कभी भी नदी के साइड में नहीं बल्कि नीचे बहता है। इस स्टेडियम की बात करें तो सुबह पिच के नीचे नमी रहती है और जब उसे हम कवर करते हैं तो उसमें थोड़ा मूवमेंट बनता है। ये पूरी दुनिया के स्टेडियमों में होता है, इसलिए यहां गंगा का कोई खास असर नहीं है।

उन्नाव के सरेनी गांव की मिट्टी से तैयार होती हैं पिचें: ग्रीन पार्क की पिचों की मिट्टी को उन्नाव से लाकर तैयार किया जाता है। इस बारे में शिवकुमार ने कहा कि उन्नाव ही कानपुर के सबसे नजदीक है और यहां के सरेनी गांव से काफी वर्षों से मिट्टी को लाया जाता रहा है क्योंकि यह नैचुरल क्ले होती है। यह मिट्टी खेत की होती है, तालाब की नहीं। अब तक यहां से मिट्टी लाई जा रही थी, लेकिन अब वहां स्रोत समाप्त होता जा रहा है। भविष्य में हमें पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी।

टूटेंगे कई रिकार्ड

एक तरफ भारत की निगाहें यह मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी, तो वहीं नजरें कई रिकार्ड बनाने पर होंगी। अगर भारतीय टीम कानपुर टेस्ट जीत लेती है तो वह टेस्ट की चौथी सबसे सफल टीम बन जाएगी। दरअसल, भारत ने अब तक 580 में से 179 टेस्ट जीते हैं और इतने ही टेस्ट दक्षिण अफ्रीका ने भी जीते हैं। कानपुर टेस्ट जीतकर भारतीय टीम उससे आगे निकल जाएगी।

- कानपुर में महज 35 रन बनाते ही विराट 27 हजार अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे। साथ ही विराट के नाम 114 टेस्ट में 29 शतक हैं और वह ग्रीन पार्क में शतक लगाते हैं तो आस्ट्रेलिया के सर डान ब्रैडमैन (52 टेस्ट में 29 शतक) को पीछे छोड़ देंगे।
- भारतीय कप्तान रोहित के पास भी यहां रिकार्ड बनाने का अवसर है। अगर रोहित शतक लगाते हैं तो वह कुल अंतरराष्ट्रीय शतकों के मामले में राहुल द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे। रोहित और द्रविड़ के नाम 48-48 शतक हैं।
- कानपुर में नौ विकेट लेकर अश्विन आस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन से आगे निकल सकते हैं। लियोन के नाम 129 टेस्ट में 530 विकेट हैं, जबकि अश्विन 101 टेस्ट में 522 विकेट ले चुके हैं।
- रवींद्र जडेजा 300 टेस्ट विकेट के करीब। कानपुर में एक और विकेट लेते ही वो टेस्ट में 300 विकेट पूरे कर लेंगे।

कानपुर में टेस्ट रिकार्ड

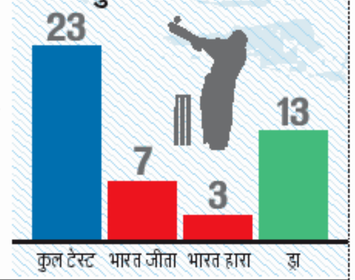

भारतीय टीम मंगलवार को कानपुर पहुंची। होटल पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ● प्रेट्र

आज अभ्यास करेंगी दोनों टीमें

जासं, कानपुर : भारत और बांग्लादेश की टीमें बुधवार से अभ्यास करेंगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बांग्लादेश की टीम अभ्यास करेगी। दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक मेजबान खिलाड़ी पसीना बहाएंगे। अगले दिन होने वाले पहले नेट्स सत्र में सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक भारत और दोपहर 1:30 से शाम 4:30 बजे तक बांग्लादेश टीम मैच की फाइनल तैयारी करेगी।

रामधुन के बीच हुआ भारतीय टीम का स्वागत

भारत और बांग्लादेश की टीमें मंगलवार को कानपुर पहुंचीं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। होटल में रामधुन के बीच टीम इंडिया का स्वागत रुद्राक्ष की माला पहनाकर किया गया। मेहमान खिलाड़ियों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया।

कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम ● एक्स

सरफराज, जुरैल और यश को टीम से रिलीज किए जाने की संभावना

नई दिल्ली, प्रेट्र : बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल सरफराज खान, अक्षर पटेल, यश दयाल और ध्रुव जुरैल को ईरानी कप के लिए दूसरे टेस्ट से रिलीज किए जाने की संभावना है। दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बदलाव की संभावना बेहद कम है और अगर इनमें से किसी खिलाड़ी को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिलती है तो ये खिलाड़ी ईरानी कप में खेलेंगे। यह मुकाबला एक से पांच अक्टूबर तक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई की टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे। मुंबई की टीम में पृथ्वी शा और शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है।

शेष भारत टीम : रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उपकप्तान), साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डिकल, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), मानव सुथार, सारांश जैन, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार, यश दयाल, रिकी भुई, शाश्वत रावत, खलील अहमद, राहुल चाहर।

राहुल भाई की कार्यशैली अनुशासित थी, गंभीर काफी सहज : अश्विन

चेन्नई, प्रेट्र: भारतीय टीम के सबसे अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि गौतम गंभीर अपने पूर्ववर्ती राहुल द्रविड़ की तुलना में अधिक सहज हैं, जिनकी कार्यशैली बहुत अनुशासित थी। द्रविड़ नवंबर 2021 से भारतीय टीम के कोच थे। वह इस जुलाई में भारतीय टीम से अलग हुए। उनकी मौजूदगी में टीम ने टी-20 विश्व कप का खिताब जीता। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर बहुत शांतचित हैं। मैं उसे 'रिलेक्स्ड रैंचो (सहज और शांत)' कहना चाहता हूं। उनकी मौजूदगी में कोई दबाव नहीं होता है। सुबह में टीम की बैठक को लेकर भी वह काफी सहज रहते हैं। वह आपसे पूछते हैं कि क्या आप सुबह बैठक में आएंगे, कृपया आइए। अश्विन ने कहा कि गंभीर की तुलना में द्रविड़ का दृष्टिकोण अधिक सख्त और व्यवस्थित था। उन्होंने कहा कि राहुल भाई चीजों को काफी व्यवस्थित रखना चाहते थे। वह चाहते थे कि किसी बोतल को भी एक विशेष समय पर एक विशेष स्थान पर रखा जाना चाहिए। वह इस मामले में बहुत ही अनुशासित थे।

इस अनुभवी आफ स्पिनर ने कहा, गंभीर से वह ऐसी चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं। वह ज्यादा कड़ाई करना पसंद नहीं करते हैं। वह सब का ख्याल रखते है और मुझे लगता है कि टीम के सभी खिलाड़ी उन्हें पसंद करेंगे। अश्विन ने कार दुर्घटना की गंभीर चोट से उबर कर टेस्ट टीम में वापसी करने वाले भारतीय विकेटकीपर रिषभ पंत की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंत बहुत अच्छा खेला। जब वह बल्लेबाजी कर रहा था तब मैंने रोहित से 10 बार कहा, वह बहुत अच्छा खेलता है लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कैसे आउट हो जाता है। वह हर तरीके से क्रिकेट के लिए पैदा हुआ है और एक मजबूत व्यक्ति है। उसके पास एक हाथ से बड़े शाट खेलने की क्षमता है।

आस्ट्रेलिया में पंत को शांत रखना होगा : पैट कमिंस

क्रिकेट डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने स्वीकार किया कि रिषभ पंत आस्ट्रेलिया में भारत के लगातार दो टेस्ट सीरीज जीतने के अभियान में 'बड़ा प्रभाव' रहे थे और इस वर्ष होने वाली बार्डर-गावस्कर ट्राफी में हमें पंत को शांत रखना होगा। 26 वर्षीय पंत ने दिसंबर 2022 में एक भयानक कार दुर्घटना में घायल होने के बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी करते हुए पिछले हफ्ते बांग्लादेश के विरुद्ध पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़ा। कमिंस ने कहा कि पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका पिछली कुछ टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और हमें उसे शांत रखने की कोशिश करनी होगी। हर टीम में एक या दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं।

वहीं, आस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने कहा कि पंत जैसे खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी करना बहुत बड़ी चुनौती है। उसके पास बल्लेबाजी का हर तरह का कौशल है। उसे गेंदबाजी करते समय गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है। इसलिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। इसलिए उसके लिए गेंदबाजी करना एक चुनौती है। रिवर्स और एक हाथ से फ्लिक जैसे अपने गैरपारंपरिक शाट के लिए पहचाने जाने वाले पंत ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पिछली दो टेस्ट सीरीज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंत ने 2021 में गाबा में अविजित 89 रन बनाकर इस मैदान पर 32 साल में कंगारू टीम की हार सुनिश्चित की और भारत को सीरीज भी जिताई।

रिषभ पंत

शाहीन अफरीदी की पाकिस्तान टेस्ट टीम में वापसी

लाहौर: तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की इंग्लैंड के विरुद्ध सात अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। सीरीज के लिए मंगलवार को टीम की घोषणा हुई। अफरीदी को खराब फार्म के कारण इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे और अंतिम टेस्ट से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज का पहला टेस्ट मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम : शान मसूद (कप्तान), सऊद शकील (उप कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हुरैरा, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, आमेर जमाल, नोमान अली, अबरार अहमद, मीर हमजा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह।

शान मसूद

दूसरे टेस्ट से पहले चोटिल फर्नांडो श्रीलंकाई टीम से बाहर

गाल : टेस्ट क्रिकेट में लगातार बड़ा उलटफेर कर रही श्रीलंकाई टीम एक बार फिर खिलाड़ियों के चोटों से परेशान नजर आ रही है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच से पहले तेज गेंदबाज विश्वा फर्नांडो चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं और उनकी जगह आफ स्पिनर निशान पीरिस को टीम में शामिल किया है। श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार को यह घोषणा की। फर्नांडो को अभ्यास के दौरान हैमस्ट्रिंग में जकड़न महसूस हुई और उन्हें रिहैब के लिए हाई परफार्मेंस सेंटर भेज दिया गया है। फर्नांडो ने अपने अंतिम टेस्ट मैच में पांच विकेट लिए थे, इसलिए श्रीलंकाई टीम के लिए यह बड़ा झटका है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट गुरुवार से गाल में खेला जाएगा।

शीर्ष परिषद के एजेंडे में नहीं नए बीसीसीआइ सचिव की नियुक्ति

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की शीर्ष परिषद बुधवार को बोर्ड के कामकाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, लेकिन निवर्तमान सचिव जय शाह की जगह नए सचिव की नियुक्ति एजेंडे में शामिल नहीं है। इस सप्ताह बेंगलुरु में होने वाली बोर्ड की 93वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले यह शीर्ष परिषद की अंतिम बैठक होगी। जय शाह के आइसीसी चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद नए सचिव की नियुक्ति आवश्यक हो गई है। हालांकि जय शाह आगामी एजीएम के दौरान बीसीसीआइ सचिव के रूप में अपनी मौजूदा भूमिका में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें एक दिसंबर से ही आइसीसी चेयरमैन का पदभार संभालना है।

जानकारी के अनुसार, शीर्ष परिषद की बैठक में पूर्व टाइटल प्रायोजक बायजू से विवाद पर चर्चा होगी। बीसीसीआइ का बायजू के साथ भुगतान निपटारे को लेकर विवाद है। बायजू ने पिछले साल मार्च में बीसीसीआइ के साथ अपना प्रायोजन करार समाप्त कर दिया था।

टी-20 विश्व कप की तैयारियों से खुश कप्तान हरमनप्रीत

मुंबई, प्रेट्र: हरमनप्रीत कौर लंबे समय से खिताब के करीब पहुंचकर चूकने के अहसास से परेशान हैं लेकिन भारतीय कप्तान को लगता है कि उनकी टीम ने तीन से 20 अक्टूबर तक यूएई में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में खिताब जीतने की दावेदारी पेश करने के लिए अच्छी तैयारी की है।

वर्ष 2009 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से भारतीय टीम केवल एक बार 2020 में फाइनल में पहुंचने में सफल रही है और तब टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी। भारत 2017 में महिला वनडे विश्व कप फाइनल भी खेला और वहां भी उपविजेता रही। हरमनप्रीत दोनों टीमों का हिस्सा रहीं और उन्होंने 2020 टी20 विश्व कप में टीम का नेतृत्व भी किया था। हरनमप्रीत ने कहा, यह सर्वश्रेष्ठ टीम है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। खिलाड़ी लंबे समय से एक साथ खेल रहे हैं। हम पिछली बार इतने करीब आ गए थे और सेमीफाइनल (2023) में हार गए। एशिया कप के दौरान हमने अच्छी क्रिकेट खेली, एक दिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। मुझे पता है कि मैंने कई विश्व कप खेले हैं लेकिन मेरे अंदर उतना ही उत्साह है जितना 19 साल की उम्र में था। भारतीय टीम ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में एक व्यापक तैयारी शिविर में हिस्सा लिया जहां खिलाड़ियों ने फिटनेस और क्षेत्ररक्षण में बहुत समय बिताया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां टीम अतीत में कमजोर रही हैं। हमने एक खेल मनोवैज्ञानिक की भी मदद ली।

हरमनप्रीत कौर

जीवन-विजय की जोड़ी बनी हांगझू ओपन चैंपियन

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ने मंगलवार को हांगझू ओपन का चैंपियन बनने के साथ पुरुष डबल्स में जोड़ी के रूप में अपना पहला एटीपी खिताब जीता, जबकि युकी भांबरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी मंगलवार को चेंगदू ओपन में उपविजेता रहे।

जीवन और विजय की गैरवरीय भारतीय जोड़ी ने एक घंटे और 49 मिनट तक चले मुकाबले में कान्स्टेंटिन फ्रांत्जेन और हेंड्रिक जेबेंस की गैर वरीयता प्राप्त जर्मन जोड़ी को 4-6, 7-6(5), 10-7 से शिकस्त दी। 35 वर्ष के जीवन के लिए यह एटीपी टूर स्तर का दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में रोहन बोपन्ना के साथ चेन्नई ओपन जीता था। वहीं विजय का यह एटीपी टूर का पहला खिताब है। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती सेट को 4-6 से गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए दूसरे सेट को 7-6 से जीतकर मुकाबले को टाई-ब्रेक तक खींचा। टाई ब्रेक में भारतीय जोड़ी 10-7 से आगे रही। जीवन और विजय की भारतीय जोड़ी अपनी सर्विस पर अंक भुनाने के मामले में शानदार रही।

इससे पहले, भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी चेंगदू ओपन के रोमांचक फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांस के सादियो डोंबिया और फैबियन रेबौल की जोड़ी से 4-6, 6-4, 4-10 से हारकर अपने तीसरे खिताब से चूक गई।

ट्राफी के साथ जीवन नेदुनजेझियान और विजय सुंदर प्रशांत ● एएफपी

हांगझू ओपन में पुरुष डबल्स के फाइनल में फ्रांत्जेन और हेंड्रिक जेबेंस को हराकर भारतीय जोड़ी ने जीती अपनी पहली एटीपी ट्राफी

आइओए कोषाध्यक्ष ने पीटी ऊषा को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने मंगलवार को संस्था की अध्यक्ष पीटी ऊषा को उनकी छवि को 'धूमिल' करने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आइओए अध्यक्ष ने एक शिकायत के आधार पर 10 सितंबर को यादव से स्पष्टीकरण मांगा था। यादव वर्तमान में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यादव और आइओए के कुछ अन्य अधिकारी राष्ट्रीय खेल संहिता में निर्धारित आयु और कार्यकाल दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर पद पर बने हुए हैं।

यादव ने 23 सितंबर को लिखे पत्र में कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधारहीन और राजनीति से प्रेरित पत्र को यह जानते हुए भी महत्व दिया कि आइओए की कार्यकारी परिषद के चुनाव 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुए थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों को भेजे गए अपने नोटिस को वापस ले लें। ऐसा न करने पर मुझे कानूनी सहारा लेना पड़ेगा।

ओलिंपियाड स्वर्ण के बाद विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयार गुकेश

भारतीय ग्रैंडमास्टर गुकेश ने कहा, शतरंज ओलिंपियाड को व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में लिया और इसका असर परिणाम में दिखा

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश नवंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले ओलिंपियाड में अपने प्रदर्शन पर संतोष जताया और कहा कि इस टूर्नामेंट को उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में लिया, जिसका परिणाम मुझे मिला। विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर 18 वर्षीय गुकेश की भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका रही, जिससे पुरुष टीम ने शतरंज ओलिंपियाड में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था।

गुकेश ने भारत के लिए शीर्ष बोर्ड पर शानदार प्रदर्शन किया और अपनी 10 बाजियों में नौ अंक हासिल किए। उन्होंने आठ बाजी जीती जबकि दो ड्रा रहीं। बुडापेस्ट से भारत पहुंचने पर गुकेश ने कहा, ओलिंपियाड को मैंने व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में लिया। मैं सिर्फ इस विशिष्ट टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था। मैं अपने प्रदर्शन और टीम के प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। परिणाम इस बात का सबूत है कि हम कई चीजें सही कर रहे थे और हम सही भावना के साथ खेल रहे थे। बुडापेस्ट में जो कुछ भी हुआ उससे मैं बेहद खुश हूं। गुकेश ने अप्रैल में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता था और 17 साल की उम्र में विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन गए थे। गुकेश और लिरेन 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक सिंगापुर में प्रतिष्ठित खिताब के लिए भिड़ेंगे। गुकेश ने कहा कि विश्व चैंपियनशिप में जाने से पहले मैं अच्छी लय में हूं। अभी कुछ महीने बाकी हैं और मैं कड़ी मेहनत करूंगा और पूरी तरह से तैयार रहूंगा। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने में सफल होते हैं तो वह दिग्गज विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। आनंद ने पांच बार विश्व खिताब जीता है।

डी गुकेश ● एएफपी

चेन्नई लौटने पर आर वैशाली, आर प्रगनानंद और श्रीनाथ नारायणन ● एएनआइ

भारत लौटने पर चैंपियनों का जोरदार स्वागत

ओलिंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय टीम के सदस्यों का मंगलवार को स्वदेश पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। डी गुकेश, आर प्रगनानंद, आर वैशाली और पुरुष टीम के कप्तान श्रीनाथ नारायणन मंगलवार सुबह चेन्नई पहुंचे। चारों के हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही प्रशंसकों ने जयकारे लगाकर उनका स्वागत किया। टूर्नामेंट में अजेय अभियान के साथ भारतीय पुरुष टीम के दबदबे में अहम भूमिका निभाने वाले गुकेश ने अपने व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक दिखाए। प्रगनानंद ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमने पहली बार ओलिंपियाड जीता है, हमने इससे पहले केवल कांस्य पदक जीता था। और हम दोनों वर्गों में जीतने में सफल रहे इसलिए यह हमारे लिए बहुत खास अहसास और गर्व का क्षण है। प्रगनानंद की बहन आर वैशाली ने कहा, यह एक स्वप्निल क्षण है। पिछली बार चेन्नई में हमने कांस्य पदक जीता था, हम स्वर्ण पदक जीतने के इतने करीब थे लेकिन अंतिम दौर में चूक गए। इस बार दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। यह ऐतिहासिक क्षण है।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार, 25 सितंबर, 2024

विश्व हृदय दिवस (29 सितंबर)

गैरसंचारी रोगों सेहोने वाली मौतोंमें हृदयरोग एकबड़ा कारकहै।पर अच्छी बात यहहैकि जीवनशैली में बदलाव कर इसे बदल भी सकते हैं।इसकेलिएकिन बातों का रखनाहै ध्यान?

हृदयरोग से बचाएगी अच्छी जीवनशैली

डा. एस रामाकृष्णन
कार्डियोलोजिस्ट, एम्स, नई दिल्ली

क्या थकान, तनाव कभी पीछा नहीं छोड़ते, धड़कन अनियमित होने के साथ बेचैनी रहती है? संभव है कि हृदयरोग की चपेट में आ रहे हों। आज 40 वर्ष आयु से ऊपर सर्वेक्षण करेंगे तो मधुमेह, हाइपरटेंशन और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल होता है। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है?

स्वस्थ भोजन, अच्छी जीवनशैली जरूरी: क्या आपकी थाली में पर्याप्त विटामिन, खनिज, फाइबर व अन्य पोषक तत्व हैं, इसका ध्यान रखें। ऐसे आहार जिनमें कैलोरी कम हो पर वे पोषण प्रदान करते हों, उन्हें चुनें। जैसे-हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज आदि। डेरी उत्पाद, मछलियां, फलियां, नट्स आदि को शामिल करें। साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उसके अनुसार, शारीरिक गतिविधि भी होती रहे।

कैसी है नींद की गुणवत्ता: आप रात भर नींद लेने के बाद भी सुबह थकान महसूस करते हैं, तो इसका अर्थ नींद बाधित रहती है। यह नहीं भूलें कि आपकी नींद की गुणवत्ता आपके खानपान की आदतों के साथ आपके मूड, स्मरण क्षमता आदि को प्रभावित कर रही है। अच्छी नींद की कमी आपको निरंतर हृदयरोग के मुहाने पर खड़ी रखती है।

तनाव है बड़ी मुसीबत: ऐसे मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जो चिकित्सक के पास आकर तनाव बढ़ने की शिकायत करते हैं। तनाव धूमपान के लिए उकसाता है, अधिक खाने और शारीरिक निष्क्रियता को बढ़ावा देने वाला होता है। क्रोनिक तनाव उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है और ये सभी हृदयरोग, हृदयाघात को खुला आमंत्रण देने वाले हैं।

जरूरी बातें
- हृदयरोग का प्रमुख कारक है मधुमेह। इसे नियंत्रण में रखने के लिए नियमित जांच कराएं। ● यदि परिवार में बीमारियों का इतिहास है तो सतर्कता बढ़ाएं। ● यदि वजन सही है, तो भी नियमित अंतराल पर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेना चाहिए।
- कोलेस्ट्रोल है तो दवाइयों की मदद भी लेनी पड़ सकती है।
- हफ्ते में 150 मिनट व्यायाम भी करते हैं तो रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल नियंत्रण में रहेगा।

वार्तालाप : सीमा झा

स्थायी तनाव

दिनभर की थकान के बावजूद लगता है काम तो खत्म ही नहीं हो रहा। सुबह उठ रहे हैं तो काम और थकान दबोच लेते हैं और शाम ढल रही है तो अगले दिन की चिंता के साथ... तय मानिए तनाव (क्रोनिक बर्नआउट) के जाल में आप फंसते जा रहे हैं। बर्नआउट के जोखिम को आखिर पहचानें कैसे, तनाव नियंत्रित हो और जीवन में खुशहाली को कैसे लौटाएं, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

फोटो: फ्रीपिक

तनाव नियंत्रित करने का अभ्यास

डा. एकांश शर्मा
साइकियाट्रिस्ट, इह्बास, नई दिल्ली

तनाव को नियंत्रित करने का सबसे सहज तरीका है मित्र और स्वजन के साथ घुलना-मिलना और घूमना-फिरना। स्ट्रेस हमारे अंदर प्रेशर कुकर की तरह होता है। यह इकट्ठा होता रहा, तो एक दिन फट जाएगा। सीटी की तरह प्रेशर निकालते रहना आवश्यक है। अगर भागती-दौड़ती दुनिया में अपनों का सहारा नहीं मिला, तो मुसीबत आएगी ही। शरीर में आक्सीटोसिन हार्मोन तभी रिलीज होता है, जब हम स्वजन और प्रियजन के साथ होते हैं। यह हार्मोन एंटी स्ट्रेस की तरह होता है। 10-15 मिनट के लिए ही फोन और गैजेट को हटाकर उनके साथ भोजन करें, बात करें। इससे 40-50 प्रतिशत तनाव कम हो जाएगा। वर्क फ्राम होम के चलते हर समय स्क्रीन के सामने रहना होता है। इससे आंखें और मस्तिष्क थक रहे हैं। स्क्रीन देखने से डोपामीन बार-बार रिलीज होता है। यह नशीले पदार्थों के सेवन, इंटरनेट एडिक्शन से भी होता है। इससे बचना चाहिए।

एकाग्र रहें पर तनाव लेकर नहीं

डा. हंसा जी योगेन्द्र
योग विशेषज्ञ एवं निदेशक, दयोग इंस्टीट्यूट, मुंबई

हमें कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। काम के साथ शरीर और मन भी होता है, इन सभी के बीच संतुलन जरूरी है। कोई भूखा रहकर या अनिद्रा में काम तो नहीं कर सकता। हर डेढ़ घंटे पर थोड़ा रिलैक्स करें, दूर जाकर या खड़े होकर काम करें।

तनाव तो लेने की चीज नहीं : काम होगा या नहीं, कोई चिल्लाएगा, यह सोचने के बजाय वर्तमान में रहें। जितनी क्षमता है उतना ही करें। यह आत्म अनुशासन से आएगा। विचारों का आवेग आएगा, पर बचना तो हमें ही है।

टिप्स : तनाव का संबंध सांस के साथ है। धीरे-धीरे लंबी सांस लें। दो-तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करें। तनाव हटाना है तो शरीर में थोड़ा खिंचाव लाएं, हाथों को फैलाएं।

काम का दबाव न बन जाए जोखिम

मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म अर्न्स्ट एंड यंग में काम करने वाली 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन की काम के दबाव के चलते जान चली गई। अब सवाल उठता है- क्या जीवन और पेशेवर कार्य का असंतुलन इस हद तक खराब हो सकता है कि जिंदगी ही जोखिम में पड़ जाए। कामकाज का दबाव, नौकरी की अनिश्चितता और बढ़ती संवादहीनता जाने-अनजाने में जिंदगी का हिस्सा बन गई है। मनोदशा को कुचल रहा यह दबाव कैसे कम हो, इस पर साइकियाट्रिस्ट डा. एकांश कहते हैं कि हमें तीन बातों का ध्यान रखना है- पहला, पेशेवर जीवन सुख-दुख में साथ रहने वाले स्वजन से दूरी का कारण नहीं बनना चाहिए, दूसरा, काम का दबाव पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने या फिर बागवानी जैसे शौक को हमसे न छीन ले, तीसरा, आभासी दुनिया यानी स्मार्टफोन और गैजेट से पर्याप्त दूरी भी जरूरी है। वर्क-लाइफ असंतुलन में जी रहे लोग बढ़ते काम के दबाव के साथ असहाय महसूस करने लगते हैं। इसका असर बहुत बड़ा होता है। थोड़ा-सा आराम करके तनाव व थकान दूर कर सकते हैं, पर बर्नआउट तो डरावने स्तर तक लेकर चला जाता है।

मस्तिष्क पर असर

तनाव आते ही एमिगडाला के सिग्नल से हाइपोथैल्मस सक्रिय हो जाता है। यह संवेदनशील हिस्सा होता है। खतरा सामने होने पर अलग-अलग हार्मोन निकलने लगते हैं। एसीटीएच हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाने से कार्टिसोल निकलता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। थोड़े समय के लिए अलर्टनेस आती है, पर ये स्ट्रेस 24 घंटे बना रहे, तो बिहेवियर पैटर्न बन जाता है।

7 बातों पर ध्यान देना शुरू करें

1. खूब पानी पिएं : तनाव महसूस कर रहे हैं, तो पानी की मात्रा बढ़ाएं। यह हाइड्रेशन के साथ दिमाग को सुकून का सिग्नल देता है। पानी से स्किन व पेट अच्छा रहता है।

2. एक्सरसाइज करें : व्यायाम, रनिंग करें। जिम करने से सेरोटोनिन (हैपी हार्मोन) रिलीज होता है, इससे 30-35 प्रतिशत तनाव खत्म हो जाता है।

3. शौक को जिंदा रखें : नए काम और शौक शुरू करें। पढ़ें, संगीत सुनें, बागवानी, प्रकृति से जुड़ें, इन्हें छोड़े नहीं। इन छोटी-छोटी चीजों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है।

4. पैसे नहीं, खुशहाली ढूंढें : पैसे के बजाय खुशहाली को कमाना सीखना चाहिए। पैसे बनाने में पांच के बजाय सात साल लग जाएंगे, पर स्वास्थ्य गया तो उसे कोई नहीं लौटा पाएगा।

5. पाजिटिव रहें : मानसिक स्वास्थ्य एक दिन का काम नहीं है, यह अभ्यास का विषय है।

6 संतुलन: भावनाओं का सम्मान करें। ये माइंडफुलनेस, व्यायाम, सही नजरिए से होगा।

7. वाहने से नहीं करने से होगा : जिम्मेदारी खुद लेंगे तो समय भी निकाल लेंगे। हमारे डाक्टर 12 से 14 घंटे तक सेवाएं देने के बाद भी फिट रहने का भरपूर जतन करते हैं। उनसे सीखना चाहिए।

तनाव कैसे बनता है बर्नआउट

बर्नआउट से पहले एक स्थिति होती है तनाव की। यह इंसान के जीवन में सामान्य सी बात है। लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहे तो वह बर्नआउट हो जाता है। इससे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और इम्युनिटी तीनों ही प्रभावित होती है। किसी चुनौती से पहले स्ट्रेस से सामना होता ही है। यह अच्छा भी है। लेकिन, तनाव और दबाव लगातार बना रहे, यह ठीक नहीं।

तनाव का शरीर पर असर

लगातार तनाव में रहने से कम उम्र में ही शरीर बूढ़ा दिखने लगता है, इम्युनिटी खराब हो जाती है। पेट की समस्या होने लगती है। तनावपूर्ण माहौल में काम करने वालों के साथ यह समस्या स्थायी तौर पर जुड़ जाती है। पाचन में सहायता करने वाले आंतों के अच्छे बैक्टीरिया खराब होने लगते हैं। अगर हमारा शरीर 24 घंटे तनाव में रहेगा तो जाहिर है शरीर हर समय एक्टिवेट रहेगा। इससे थकान और आलस्य होगा। फोन आने पर भी घबराहट होने लगती है। इससे इमोशनल, काग्निटिव हेल्थ और इम्युनिटी सब खराब होने लगेगी।

नींद, भोजन, दिनचर्या संतुलन

कामकाज के अव्यवस्थित होने से शरीर की प्रतिक्रिया देने की क्षमता गिरने लगती है। जैसे नींद प्रभावित हुई तो स्वत: ही भोजन का चक्र बिगड़ जाएगा। खुद के लिए समय निकालना कठिन हो जाएगा। अपने शौक को समय नहीं दे पाएंगे।

स्वभाव में बदलाव

- थकान महसूस होना
- नए काम और
- जिम्मेदारियों से बचना
- नींद का बाधित होना
- दुखी, चिड़चिड़ा और जीवन से बेपरवाह होना

तनाव से बीमारियां

उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्या, टाइप-2 डायबिटीज

सुबह की शुरुआत धीमी हो

माइंडफुलनेस यानी विचारों और भावों के साथ वर्तमान को महसूस करने का गुण जीवन में उतारना आवश्यक है। यह प्राणायाम से एक स्तर ऊंचा है। सुबह उठते ही फोन चलाने, भागदौड़ की आदत छोड़ कर आप खुद पर उपकार कर सकते हैं। सुबह आधे-एक घंटे पहले उठ जाएं, दिन की शुरुआत धीमे करें, इससे दिमाग तरोताजा रहेगा।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

वर्ग पहेली-2762

बाएं से दाएं
1. हार, शिकस्त (4)।
2. एक जैसा, सम (4)।
5. सचमुच (3)। 8. घंटा बजने का शब्द (2)।
9. खट्टापन, किण्व (3)।
10. वहन करने योग्य (4)।
12. समावेश (4)। 15. यूनानी चिकित्साशास्त्री (3)।
18. अंधकार, अंधेरा (2)।
19. प्रतिलिपि, काषी (3)।
20. अंधकार को दूर करने वाला (4)। 21. मानना (4)।

ऊपर से नीचे
1. मतलब, ध्यान (4)।
3. एक प्रसिद्ध विज्ञानी का उपनाम (3)।
4. चंद्रमा, ओशो का एक नाम (4)।
6. गन्ना (2)। 7. भेड़-बकरी चराने वाला (4)।
8. वृक्ष की डाली, शाखा (3)। 11. महादेव के उद्घोष में प्रयुक्त शब्द (2,2)। 13. मृत्यु शोक (3)। 14. सज्जनता, भलमनसाहत (4)। 16. जी, अंत :करण (2)। 17. पीछे मुड़ना (4)। 18. प्रकार (3)।

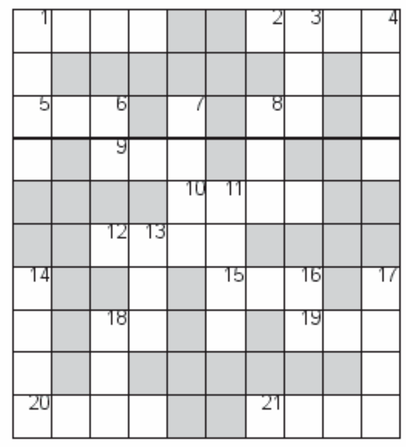

© Bird Features & Writing Agency

भूल सुधार
मंगलवार, 24 सितंबर 2024 के अंक में प्रकाशित वर्गपहेली-2761 में विसंगति के कारण इसका परिणाम शून्य किया जा रहा है। पाठकों को हुई असुविधा के लिए खेद है।

जागरण सुडोकू-2762

	7		9			8		2
3			5					
		9		2	8	1		4
	3		6				1	
8				1		6		
		7	8					9
5					9	2		1
		2	1		4			
	1			8				6

कल का हल

6	4	9	8	3	7	2	5	1
8	7	5	4	2	1	9	3	6
2	1	3	6	9	5	4	8	7
4	8	6	3	7	2	1	9	5
1	3	2	5	8	9	6	7	4
9	5	7	1	4	6	8	2	3
5	9	8	7	1	4	3	6	2
7	2	4	9	6	3	5	1	8
3	6	1	2	5	8	7	4	9

आज का भविष्यफल- 25 सितंबर, 2024 बुधवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी। आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक। आज का दिशाशूल : उत्तर।
विशेष : अष्टमी श्राद्ध, मातृ नवमी श्राद्ध दोपहर 12 बजकर 30 मिनट के पश्चात।
कल 26 सितंबर, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : दक्षिण
विशेष : नवमी श्राद्ध
कल की भद्रा : रात्रि के 12 :53 से 27 सितम्बर को दोपहर 01 :21 बजे तक।
विक्रम संवत 2081 शके 1946 दक्षिणायण, अश्विन मास कृष्ण पक्ष की नवमी 12 घंटे 26 मिनट तक, तत्पश्चात दशमी पुनर्वसु नक्षत्र तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र परिघ योग तत्पश्चात शिव योग मिथुन में चंद्रमा तत्पश्चात कर्क में।

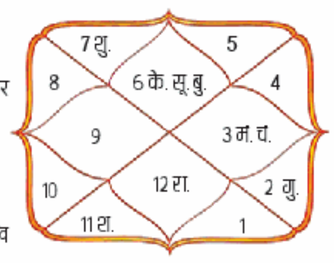

मेष : गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। संतान के कारण चिंतित रहेंगे।
वृष : आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। जीवन सुखमय होगा।
मिथुन : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
कर्क : जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी।
सिंह : रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा।
कन्या : अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
तुला : आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
वृश्चिक : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पिता या गुरु से सहयोग मिलेगा।
धनु : प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मकता में सफलता मिलेगी।
मकर : जीविका में प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।
कुंभ : पारिवारिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। कार्य संपन्न होगा। धन व्यय होगा।
मीन : आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।

राष्ट्रीय फलक

शुद्धि अनुष्ठान: तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशुओं की चर्बी युक्त घी के उपयोग संबंधी विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण का 11 दिवसीय 'प्रायश्चित' जारी है। इसके अंतर्गत मंगलवार को पवन कल्याण ने विजयवाड़ा स्थित श्री कनक दुर्गा मंदिर में एक शुद्धि अनुष्ठान में भाग लिया। उन्हें सफाई करते हुए भी देखा गया। प्रेट्र

साधु परिषद का तिरुपति मंदिर के सामने प्रदर्शन

लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की

तिरुपति, एएनआइ : तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु चर्बी के इस्तेमाल के विरोध में आंध्र प्रदेश साधु परिषद ने मंगलवार को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के प्रशासनिक भवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साधुगण तिरुमाला बचाओ और टीटीडी बचाओ से बैनर हाथों में थामे हुए थे।

साधु परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासनंद सरस्वती ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर अपने कार्यकाल के दौरान तिरुमाला मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन ईसाई समुदाय से हैं और उन्होंने कभी भगवान वेंकटेश्वर को महत्व नहीं दिया। कभी हिंदू धर्म में विश्वास नहीं किया। इन लोगों ने हमेशा भगवान वेंकटेश्वर को व्यापारिक उद्देश्य से देखा। उन्होंने मंदिरों में हिंदू भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे से बहुत सारा पैसा हड़प लिया है। उनकी मंदिर में कोई आस्था नहीं थी। उन्होंने करोड़ों भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। हम मांग करते हैं कि सरकार इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

उधर , उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी को तिरुपति लड्डू प्रसादम में मिलावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि वह सनातन धर्म की रक्षा के लिए जान तक देने को तैयार हैं।

विजयवाड़ा में उन्होंने कहा- ''मुझे नहीं पता कि वाईवी सुब्बारेड्डी और करुणाकर रेड्डी ने ईसाई धर्म अपनाया है या नहीं लेकिन जगन मोहन के शासनकाल में तिरुपति मंदिर में बोर्ड की स्थापना की गई थी और वह लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। सुब्बारेड्डी और करुणाकर पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा- 'धर्मनिरपेक्षता एकतरफा रास्ता नहीं बल्कि दोतरफा रास्ता है जिसमें सभी धर्मों को शामिल होना चाहिए।

सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पैकेट पर चूहों का वीडियो प्रसारित, मंदिर ट्रस्ट ने शुरू की जांच

मुंबई, प्रेट्र: तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट को लेकर चल रहे विवाद के बीच सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पैकेट पर चूहों का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि, श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट (एसएसजीटी) ने इस आरोप से इन्कार किया है और कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शिवसेना नेता और एसएसजीटी के अध्यक्ष सदा सर्वणकर ने कहा- ''रोजाना प्रसाद के लाखों लड्डू बांटे जाते हैं और उन्हें तैयार करने की जगह साफ-सुथरी होती है। वीडियो में एक गंदी जगह दिखाई दे रही है। यह मंदिर परिसर नहीं है और इसे कहीं बाहर शूट किया गया है।''

प्रयागराज के मंदिरों में बाहर से प्रसाद लाने पर रोक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : तिरुपति मंदिर में अर्पित होने वाले लड्डू में पशुओं की चर्बी मिलाने का मामला प्रकाश में आने के बाद तीर्थराज प्रयाग में प्राचीन मंदिरों में सख्ती बरती जा रही है। श्रीमनकामेश्वर महादेव व संकट मोचन हनुमान मंदिर में बाहर का लड्डू व पेड़ा अर्पित करने पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं से सिर्फ फल व पुष्प अर्पित करने का आग्रह किया गया है। शक्तिपीठ मां अलोपशंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं को नारियल, इलायची दाना व चुनरी अर्पित करने को कहा गया है। मंदिर प्रबंधन प्रसाद की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। वहीं, श्रद्धालुओं से उन्हीं दुकानों से मिष्ठान लाने का आग्रह किया गया है, जिनकी जांच खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग करता है। मां अलोपशंकरी मंदिर के प्रबंधक व श्रीमहानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्रीमहंत यमुना पुरी का कहना है कि मइया को नारियल व फल अर्पित करने का आग्रह किया गया है।

रामनगरी में अनुष्ठान के साथ पूरा हुआ वारकरियों का प्रण

जागरण संवाददाता, अयोध्या : अयोध्या में ढांचा ध्वंस के बाद हम लोग बहुत खुश हुए थे। यह करोड़ों हिंदुओं के लिए गर्व का क्षण था, लेकिन रामनगरी से मायूस होकर लौट रहे थे। मेरा सपना अधूरा था। उसी समय हमने प्रण लिया था कि अब तभी लौटेंगे, जब रामजन्मभूमि पर हमारे आराध्य भगवान राम का भव्य मंदिर निर्मित हो जाएगा। जब 32 वर्ष बाद यह सपना प्रभु कृपा से पूरा हो गया, तबसे हम सभी यहां आना चाह रहे थे। यह कहना था कि महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय से जुड़े श्रीनारायण भक्त नारायण महाराज शिंदे का। ये विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अशोक सिंहल के संपर्क में थे। वह बताते हैं कि ढांचा गिरने के बाद लोग छिपते-छिपाते अपने-अपने गंतव्यों की ओर जा रहे थे। तब हमने अपने समुदाय के साथियों को एकत्रित किया और सरयू जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया कि अब हम अयोध्याधाम में तभी लौटेंगे, जब यहां भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा।

कृष्ण जन्मभूमि व ज्ञानवापी पर दावा छोड़ दें मुस्लिम : डा. केके मोहम्मद

डा. राकेश राय ● जागरण

- आइसीएचआर की राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने आए इतिहासकार ने दैनिक जागरण से की बातचीत
- कहा- कृष्ण जन्मभूमि व ज्ञानवापी पर हिंदुओं के आधार के हैं पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण

गोरखपुर: अयोध्या में ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष का पुरातात्विक प्रमाण देने वाले इतिहासकार व पद्मश्री डा. केके मोहम्मद का कहना है कि मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी पर पूरी तरह हिंदुओं का अधिकार है। मुस्लिम समाज के लोगों को इन पर दावा छोड़ देना चाहिए। इन स्थलों पर मस्जिद से पहले मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के पास हैं।

इंडियन काउंसिल आफ हिस्टोरिकल रिसर्च (आइसीएचआर) की ओर से गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने पहुंचे डा. मोहम्मद ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में मंदिर-मस्जिद प्रकरण पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि देश में अमन-चैन कायम रखने के लिए हिंदुओं को भी चाहिए कि इन तीन प्रमुख धर्म स्थलों के अलावा अन्य मंदिरों को लेकर कोई मांग और विवाद न पैदा करें। अयोध्या, मथुरा और काशी के धर्मस्थलों को उसी तरह कहीं नहीं बसाया जा सकता है, जैसे मक्का-मदीना की मस्जिद कहीं और नहीं बनाई जा सकती।

डा. मोहम्मद ने कहा कि कई मंदिरों का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के दौरान उन्होंने पाया कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों की शह पर बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े गए। कई स्थानों पर इसके साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे स्थान हिंदुओं की विरासत हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए। इन परिस्थितियों में जब आज के मुस्लिम उसके पक्ष में आते हैं, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी कोई भूमिका भी नहीं है। ऐसे स्थानों का पुरातात्विक प्रमाण देकर मैं मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ किए गए खराब बर्ताव का प्रायश्चित भी कर रहा हूं।

हिमाचल-उत्तराखंड में दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी

जागरण टीम, नई दिल्ली

- फिर सक्रिय होगा मानसून, छह अक्टूबर तक जाने के संकेत नहीं
- मानसून की अवधि लंबी, लेकिन सामान्य से 20 प्रतिशत कम हुई वर्षा

10 स्थानों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार

हिमाचल में पांच दिन से वर्षा नहीं हुई है। इसके चलते निचले व मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। प्रदेश के 10 स्थानों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। ऊना में सबसे अधिक तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला और इसके आसपास पर्यटन स्थलों पर अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री रहा। दोपहर बाद बादल छाने व ठंडी हवा चलने से पर्यटकों व स्थानीय लोगों को राहत मिली।

उत्तर भारत के पहाड़ों में कमजोर पड़े मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ जिलों में दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बता दें कि हिमाचल में इस बार मानसून सक्रिय होने के बाद बीच में कमजोर पड़ गया था। हालांकि, अगस्त में सर्वाधिक वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश से मानसून सामान्य तौर पर 24 सितंबर तक लौट जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अब भी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के तहत वर्षा होने की स्थिति बनी है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में मानसून जाने में कुछ समय लग सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 सितंबर के बाद मौसम फिर साफ होगा। इससे पहले 2019 में 11 अक्टूबर को मानसून की वर्षा पूरी तरह से बंद हुई थी। फिलहाल अभी छह अक्टूबर तक मानसून जाने के संकेत नहीं हैं। भले ही मानसून की अवधि इस वर्ष लंबी जा रही है, लेकिन प्रदेश में वर्षा सामान्य से 20 प्रतिशत कम हुई है।

उत्तराखंड में आज तीव्र वर्षा का अलर्ट : उत्तराखंड में एक सप्ताह से मौसम शुष्क है और पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। हालांकि आज मंगलवार से मौसम ने करवट ली है। देहरादून समेत पर्वतीय जिलों में दोपहर बाद वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल मंडराने के आसार हैं। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। इसे लेकर कुमाऊं मंडल में यलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में हल्की वर्षा के आसार हैं।

बिहार में नदियों व तालाबों में डूबने से 24 की मौत : बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान डूबने से मां-बेटी समेत 24 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ को सुरक्षित बचा लिया गया। मृतकों में मुंगेर के सात, पूर्वी चंपारण के छह, बिहारशरीफ के तीन, वैशाली, मधेपुरा व पश्चिमी चंपारण के दो-दो, लखीसराय व कटिहार के एक-एक लोग शामिल हैं। बिहारशरीफ जिले में मंगलवार को जिउतिया पर्व की पूर्व संध्या पर स्नान के क्रम में डूबने से मां-बेटी समेत तीन की मौत हो गई।

****

बंगाल ने पहले ही डीवीसी से पानी छोड़े जाने को लेकर कर दिया था सतर्क

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- सामने आया 17 सितंबर को भेजा गया मेमो, ममता ने बिना सूचना पानी छोड़ने का लगाया था आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले आरोप लगा रही हों कि दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने उनकी सरकार को सूचित किए बिना अपने बांधों से पानी छोड़ा, जिससे बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आ गई जबकि राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पहले ही आठ जिलों को डीवीसी से पानी छोड़े जाने को लेकर सतर्क कर दिया गया था। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग का एक 'मेमो' सामने आया है। 17 सितंबर की तारीख वाले इस मेमो के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग ने आधा दर्जन से अधिक जिले के जिलाधिकारियों को बाढ़ की आशंका को लेकर सावधान किया था।

मुख्यमंत्री ममता ने मंगलवार को कहा कि बंगाल में भारी वर्षा के कारण बाढ़ नहीं आई है। डीवीसी का काम सिर्फ पानी छोड़कर लोगों की जान लेना है। उसका ध्यान बिजली बेचने पर है। वह राज्यों को बाढ़ से बचाने का अपना प्राथमिक उद्देश्य भूल गई है। मैं ऐसी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। डीवीसी मुख्यालय के बंगाल से स्थानांतरित होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता के बयान की निंदा करते हुए कहा कि बनर्जी हमेशा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती हैं कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। वहीं मवेशी तस्करी कांड में जमानत मिलने के बाद अनुब्रत मंडल तिहाड़ जेल से रिहा होकर सोमवार सुबह सीधे बोलपुर पहुंचे, ममता भी बोलपुर पहुंची थीं।

डीवीसी ने कहा है कि डीवीसी अधिनियम, 1948 के अनुसार, बंगाल और झारखंड सहभागी राज्य हैं और केंद्र के प्रतिनिधियों के अलावा प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि बोर्ड में होता है। बोर्ड से इस्तीफे का कोई प्रविधान नहीं है। बंगाल के विद्युत सचिव शांतनु बसु ने बांधों से पानी को अनियंत्रित तरीके से छोड़े जाने की वजह से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ आने के कारण बोर्ड से इस्तीफा दिया है।

कार्बन क्रेडिट पाने वाला दुनिया की पहला रेल नेटवर्क बना दिल्ली मेट्रो

2011 में आज ही दिल्ली मेट्रो संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट पाने वाला दुनिया का पहला रेलवे नेटवर्क बना था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यदि मेट्रो नहीं होती तो प्रतिदिन इसका उपयोग करने वाले 18 लाख लोग कार, बस या मोटरसाइकिल से यात्रा करते, जिससे प्रदूषण बढ़ता।

40 घंटे का कार्य सप्ताह शुरू कर हेनरी फोर्ड ने बदली श्रम व्यवस्था

1926 में आज ही फोर्ड कंपनी के हेनरी फोर्ड ने कर्मचारियों के काम करने के शेड्यूल को दिन में आठ घंटे व सप्ताह में पांच दिन कर दिया था। यह कदम रणनीतिक होने के साथ उनकी मानवीय संवेदनाओं का भी परिणाम था। इस निर्णय ने पूरी दुनिया के श्रम व्यवस्थाओं को प्रभावित किया।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सतीश धवन ने दी थी नई ऊंचाई

राकेट विज्ञानी सतीश धवन का जन्म 1920 में आज ही श्रीनगर में हुआ था। 1951 में संकाय सदस्य के रूप में आइआइएससी, बेंगलुरु से जुड़े। 1962 में इसके निदेशक बने। आइआइएससी में देश की पहली सुपरसोनिक विंड टनल उन्हीं की देन है। 1972 में वह इसरो के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लांच किया था। उन्होंने इनसैट, आइआरएस और पीएसएलवी के विकास में योगदान देकर भारत को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था।

डिस्लेक्सिया व एडीएचडी के कामन जीनों की हुई खोज

उपलब्धि ▶ शोधकर्ताओं ने की है 174 कामन जीनों की पहचान, रोगों की रोकथाम में हो सकती है मददगार

इन विकारों के लिए जिम्मेदार 49 साझा आनुवंशिक क्षेत्रों का भी पता लगाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जिनकी उत्पत्ति कारकों की सटीक पहचान न होने से उनका इलाज जटिल और कठिन हो जाता है। इसलिए शोधकर्ताओं का जोर बीमारी के कारकों की खोज पर ज्यादा होता है। इस क्रम में शोधकर्ताओं ने डिस्लेक्सिया और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसआर्डर (एडीएचडी) नामक रोगों के कामन 174 जीनों की पहचान की है, जो उनकी आनुवंशिक उत्पत्ति पर नई रोशनी डालते हैं। मालूम हो कि डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, जिससे पीड़ितों को बोलने में अधिक समय लगता है, शब्दों को उच्चरित करने में कठिनाई होती है और अक्षरों, संख्याओं तथा रंगों के नाम याद रखने में भी परेशानी होती है। जबकि एडीएचडी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने, अति सक्रियता और आवेग में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

ब्रिटेन की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व वाली एक टीम ने बताया है कि 174 जीनों में से 121 की पहले पहचान नहीं हो पाई थी। उन्होंने न्यूरोडेवलपमेंटल विकारों के लिए जिम्मेदार 49 साझा आनुवंशिक क्षेत्रों का भी पता लगाया है। मालिक्यूलर साइकिएट्री नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध निष्कर्ष के मुताबिक, यह डिस्लेक्सिया की आनुवंशिक उत्पत्ति पर नई रोशनी डालते हैं और यह भी प्रदर्शित करते हैं कि वे एडीएचडी के साथ कैसे ओवरलैप होते हैं। इस तरह से डिस्लेक्सिया और एडीएचडी के पीछे

जीन की पहचान आसान करेगी रोगों की रोकथाम। प्रतीकात्मक

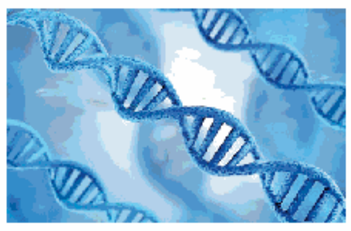

की जैविक क्रियाओं को समझने में मदद मिल सकती है, जो अक्सर लोगों में एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इन स्थितियों के अंतर्निहित जीन उन्हें आटिज्म, द्विध्रुवी विकार और सिजोफ्रेनिया जैसे अन्य मानसिक रोगों के इलाज से अलग करते हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मनोरोग जीनोमिक्स कंसोर्टियम (पीजीसी) के आनुवंशिक डेटासेट का विश्लेषण किया। पीजीसी एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है, जो मनोरोग संबंधी विकारों के कारक जीनों की पहचान करने और रोग के जोखिम को बदलने वाले वैरिएंट का पता लगाने के लिए दुनियाभर के लोगों के आनुवंशिक डेटा को एकत्र करता है। शोधकर्ताओं ने लगभग दस लाख लोगों के डिस्लेक्सिया आनुवंशिक आंकड़ों का विश्लेषण किया। टीम ने डिस्लेक्सिया और एडीएचडी, आटिज्म, बाइपोलर डिसआर्डर और सिजोफ्रेनिया सहित 10 अन्य न्यूरोडेवलपमेंटल और मनोरोग लक्षणों के लिए समान लक्षणों वाले जीन के समूहों को खोजने के लिए सांख्यिकीय टूलों का उपयोग किया। शोधकर्ताओं का दावा है कि डिस्लेक्सिया और एडीएचडी दोनों में अंतर्निहित आनुवांशिक वैरिएंट की जांच में 49 लोकी (व्यक्तिगत लक्षणों के जीडब्ल्यूएएस में पहले नहीं पाए गए 40) को 174 जीनों (व्यक्तिगत लक्षणों के जीडब्ल्यूएएस में नहीं पाए गए 121) को संभावित प्लियोट्रोपिक वैरिएंट के रूप में शामिल किया।

जीडब्ल्यूएएस जीनोम- वाइड एसोसिएशन अध्ययन को संदर्भित करता है, जो एक शोध पद्धति है और एक निश्चित लक्षण या बीमारी से जुड़े जीन को चिह्नित करने के लिए कई लोगों के जीनोम का विश्लेषण करती है। प्लियोट्रापी उसे कहा जाता है, जहां जीन का एक ही प्रकार एक साथ कई लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता आस्टेजा सियुल्किनटे के मुताबिक, यह पहली बार है कि मनोरोग लक्षणों के संदर्भ में डिस्लेक्सिया के आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन किया गया है। भविष्य में उनके बीच संबंधों की अधिक सूक्ष्म समझ के लिए डिस्केल्कुलिया या डिस्प्रेक्सिया जैसी अन्य सीखने की कठिनाइयों को भी अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए।

ग्लोबल वार्मिंग का अद्भुत अध्ययन

बेल्जियम के मास्मेचेलेन में 'इकोट्रान' में नाशपाती तोड़ते एक विज्ञानी। 'इकोट्रान', एक रिसर्च फैसिलिटी है, जिसमें सुविधाओं से युक्त 12 पारदर्शी गुंबदाकार संरचनाएं हैं। इसमें हैसेल्ट विश्वविद्यालय के शोधार्थी जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने इसके अंदर एक नियंत्रित वातावरण में नाशपाती उगाया है, जो यह दर्शाता है कि 2040 में जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेगा। यह जानने पर भी जोर है कि ग्लोबल वार्मिंग से यूरोप के फल उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रायटर

इधर-उधर की

75 साल बाद परिवार से मिला अपहृत हुआ व्यक्ति

1951 में एक पार्क से किया गया था लुई का अपहरण। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका में 1951 में एक पार्क से छह साल की उम्र में जिस बच्चे (लुई अरमांडो) का अपहरण कर लिया गया था, वह 75 साल बाद अपने परिवार को मिला है। परिवार ने तो आस भी छोड़ दी थी। लेकिन जब लुई की बहन की बेटी 63 वर्षीय एलिडा एलेक्विन ने 2020 में शौकिया आनलाइन डीएनए परीक्षण कराया। इसमें एक व्यक्ति के साथ उनका डीएनए 22% मेल खा गया। इसके आधार पर लुई की फाइल पुलिस ने दोबारा खोली और उसे ढूंढ निकाला।

वायु प्रदूषण बढ़ा सकता है पार्किंसंस का खतरा

▸ पीएम 2.5 और नाइट्रोजन आक्साइड का उच्च स्तर है खतरनाक

▸ जेएएमए नेटवर्क ओपन जर्नल में प्रकाशित हुआ है एक ताजा शोध

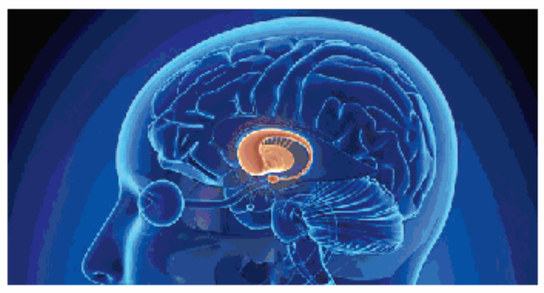

नई दिल्ली, आइएएनएस: दुनियाभर में प्रदूषण का स्तर जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, उसके व्यापक दुष्परिणाम भी उसी गति से सामने आ रहे हैं। पहले के अध्ययनों में वायु प्रदूषण के कारण हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे घातक रोग के प्रमाण मिल चुके हैं। अब इस बात के भी प्रमाण तेजी से पुख्ता हो रहे हैं कि वायु प्रदूषण पार्किंसंस रोग का भी जोखिम बढ़ा सकता है।

एक अनुमान के अनुसार, दुनियाभर में एक करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं, जिनमें 10 प्रतिशत लोग भारत के हैं। बता दें कि इस रोग के लक्षणों में शरीर में कंपन, मांसपेशियों या अंगों में अकड़न, सहज गति का धीरे-धीरे खत्म होना, जिससे अक्सर मानसिक कौशल या प्रतिक्रिया समय में कमी आना, आवाज में बदलाव या चेहरे के भाव में कमी, पलकें झपकाने जैसी स्वाभाविक गति में धीरे-धीरे ह्रास होना शामिल हैं।

जेएएमए नेटवर्क ओपन नामक जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) और नाइट्रोजन डाइआक्साइड (एनओटू) का उच्च स्तर पार्किंसंस के बढ़ते जोखिम से जुड़ा था। सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलाजिस्ट डा. अंशु रोहतगी का कहना है कि इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि वायु प्रदूषण से पार्किंसंस रोग विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पीएम 2.5 और एनओटू जैसे प्रदूषकों के संपर्क में आने से पार्किंसंस रोग के लक्षण तेजी से उभर सकते हैं।

वायु प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी गंभीर दुष्प्रभाव। प्रतीकात्मक

पीएम 2.5 एक हानिकारक प्रदूषक पदार्थ है, जो फेफड़ों में प्रवेश कर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह ज्वालामुखी और रेगिस्तान जैसे प्राकृतिक स्रोतों या उद्योग, वाहनों, कृषि, घरेलू जलावन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित आग जैसी मानवीय गतिविधियों से पैदा हो सकता है।

पार्किंसंस के अलावा, पीएम 2.5 को और भी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा पाया गया है, जिनमें अस्थमा, फेफड़ों के विकार, मधुमेह और अल्जाइमर भी शामिल हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक के हिसाब से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली हवा में पीएम 2.5 का स्तर पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हवा की वार्षिक औसत सांद्रता होनी चाहिए। लेकिन दुनिया की 99 प्रतिशत आबादी इस स्तर से ऊपर की पीएम 2.5 सांद्रता वाली हवा में रहती है। वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों में, पार्किंसंस रोग के अधिक जोखिम से जुड़ा है।

जिन लोगों का पहले से ही पार्किंसंस का इलाज चल रहा है, उनके लिए वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से रोग बढ़ने और लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम 2.5 जैसे प्रदूषक ब्लड-ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं, जिससे सूजन और आक्सीडेटिव तनाव पैदा हो सकता है और यह स्थिति पार्किंसंस रोग के बढ़ने में मददगार होती है।

खाद्य पैकेजिंग के सामग्री में मिले ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े 200 रसायन

अनुसंधान

खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए उपयोग होने वाले पेपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। शोधकर्ताओं की टीम ने एक अध्ययन में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, पेपर, कार्ड बोर्ड आदि में ऐसे 200 संदिग्ध रसायनों की पहचान की है जो ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम पैदा करते हैं।

शोध का निष्कर्ष 'फ्रंटियर्स इन टाक्सीकोलाजी' में मंगलवार को प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता कहते हैं कि इससे स्पष्ट है कि वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर्याप्त नहीं है। फूड पैकेजिंग फोरम की निदेशक एवं अध्ययन की सह लेखिका जेन मुनके कहती हैं कि इन हानिकारक रसायनों को लेकर जागरूकता आवश्यक है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2022 में विश्वभर में 23 लाख महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थीं, जबकि 6.7 लाख की मौत हो गई।

शोध दल ने हाल में प्रकाशित संभावित ब्रेस्ट कार्सिनोजन की सूची से तुलना की। उन्होंने खाद्य संपर्क सामग्री (एफसीएम) में 189 संभावित ब्रेस्ट कार्सिनोजन पाए। इनमें 143 प्लास्टिक और 89 पेपर या कार्डबोर्ड से निर्मित थे। इसके अलावा उन्होंने दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले एफसीएम में 76 संदिग्ध ब्रेस्ट कार्सिनोजन के साक्ष्य पाए, इनमें 60 (80 प्रतिशत) प्लास्टिक से बने थे। महत्वपूर्ण यह है कि बाजार में मौजूद ये एफसीएम यूरोप और अमेरिका जैसे उच्च मानकीकृत वाले क्षेत्रों से हैं। इस तरह अध्ययन खाद्य सामग्रियों की व्यापक असुरक्षा के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

छह अक्टूबर से होगा बिग बास 18 का आगाज

फिर शो की मेजबानी करेंगे सलमान। इंटरनेट मीडिया

अभिनेता सलमान खान की इस साल कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई है। हालांकि रियलिटी शो बिग बास से उनका नाता कायम है। वह एक बार फिर शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। यह लगातार 14वीं बार है जब सलमान इस शो की मेजबानी करते नजर आएंगे। चाहे घर के अंदर प्रतिभागियों के बीच लड़ाई-झगड़ा हो या आपसी मनमुटाव सलमान खान का वीकेंड का वार का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। निर्माताओं ने हाल ही में एक रोमांचक प्रोमो के साथ बिग बास सीजन 18 की घोषणा की है। शो का प्रीमियर छह अक्टूबर को रात नौ बजे कलर्स चैनल पर होगा। शो के प्रोमो से पता चलता है कि इस बार शो में प्रतिभागियों का इतिहास भी खंगाला जाएगा। इसके अलावा शो में समय की पाबंदी से जुड़ी भी कुछ चीजें होंगी। निर्माताओं द्वारा बिग बास 18 के लिए प्रतियोगियों की अंतिम लिस्ट की पुष्टि बाकी है। हालांकि, खबरें हैं कि इस बार करणवीर मेहरा, नायरा बनर्जी, चाहत पांडे, शहजादा धामी, अविनाश मिश्रा, निया शर्मा, शोएब इब्राहिम, धीरज धूपर, समीरा रेड्डी, डाली चायवाला, करण पटेल और ईशा कोप्पिकर शो का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल सलमान अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग को पूरा करने में लगे हैं। यह फिल्म अगले साल ईद पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

...इसलिए श्वेता ने की सिंघम अगेन

« बड़ी स्टारकास्ट के बीच सिंघम अगेन में श्वेता की भी होगी अहम भूमिका ● जागरण आर्काइव

किसी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म से जुड़ने के बाद कलाकार के लिए कई संभावनाएं खुल जाती हैं। उस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्मों में उनकी उपस्थिति बनी रहने से लेकर उनकी भूमिका को बढ़ाए जाने समेत कई चीजें होती हैं। ऐसी ही संभावनाओं को देखते हुए अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन को स्वीकृति दी। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सिंघम अगेन में अभिनेता अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के अलावा दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर और टाइगर श्राफ समेत वैसे ही काफी बड़ी स्टारकास्ट है। ऐसे में रोहित के साथ पहले वेब सीरीज द इंडियन पुलिस फोर्स कर चुकी श्वेता इस फिल्म को स्वीकृति देने को लेकर कहती हैं, 'इंडियन पुलिस फोर्स करने के कुछ दिनों बाद उनका (रोहित शेट्टी) का फोन आया कि सुनो सिंघम अगेन बना रहा हूं, उसमें एक भूमिका है, वो निभाओगी क्या? मैंने उसके लिए भी स्वीकृति दे दी। मैं तो बस उनके उस पुलिस यूनिवर्स से जुड़ना चाहती थी। छोटी-बड़ी जैसी भी भूमिका थी, मैं बस उनके साथ काम करना चाहती थी तो कर लिया।' क्या रोहित शेट्टी की पुलिस यूनिवर्स में आगे श्वेता की भी भूमिका बढ़ाई जा सकती है? इसके जवाब में वह कहती हैं, 'हां, हो सकता है और यह भी हो सकता है कि न भी बढ़े। एक बात तो तय है कि अगर आप एक बार जुड़ गए तो उस यूनिवर्स के साथ आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। मेरे लिए तो बस एक बार नाम जुड़ना जरूरी था।'

पूरी फिल्म के बजट जितना सितारों ने करण से मांगी थी फीस

फिल्मकार करण जौहर अक्सर इस विषय पर आवाज उठाते आए हैं कि सितारों की फीस उनकी फिल्मों के प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए। हाल ही इस एक इंटरव्यू में उन्होंने सितारों की ज्यादा फीस और अपनी फिल्म किल के निर्माण से जुड़ी घटनाओं को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी भी कलाकार को ज्यादा फीस नहीं दे रहा हूं, अगर उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई नहीं की है। मैंने एक छोटी फिल्म किल प्रोड्यूस की। यह एक नवोदित कलाकार के साथ एक हाई कांसेप्ट फिल्म थी। मैंने इसमें किसी स्टार को नहीं लिया, क्योंकि इसके लिए मैं जिस किसी भी स्टार के पास जाता था, वो सब इसके लिए उतनी फीस मांगते थे, जितनी इस फिल्म का पूरा बजट था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको इतना कैसे दे सकता हूं, जब मेरी पूरी फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये है। क्या आप मुझे इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि यह फिल्म 120 करोड़ रुपये की कमाई करेगी। नहीं न। तो मैंने इस फिल्म के लिए एक नया लड़का ढूंढा। मुझे यह कहना पड़ेगा कि वह एक आउटसाइडर है।' उल्लेखनीय है कि किल में अभिनेता लक्ष्य लालवानी और राघव जुयाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

जल्द ही एक एक्शन फिल्म निर्देशित करने वाले हैं करण। इंटरनेट मीडिया

अब कैसे मुझे तुम मिल गए में डींगे हांकती दिखेंगी प्रीति अमीन

काम करने के साथ-साथ कलाकार को अगर सेट पर ही मजाक-मस्ती वाला माहौल मिल जाए तो फिर काम का दबाव नहीं रहता है। कुछ ऐसा ही देखकर अभिनेत्री प्रीति अमीन धारावाहिक कैसे मुझे तुम मिल गए की टीम से जुड़ी हैं। अब वह इस धारावाहिक में शो की नायिका अमृता की दुबई वाली मौसी वंदना की भूमिका में नजर आएंगी। चूंकि उनका पात्र शो के नायक यानी कि अर्जित तनेजा अभिनीत विराट को पसंद नहीं करता है तो अब वह शो में विराट की ठेठ सास बनकर उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचाने की कोशिश करेंगी। धारावाहिक 'कसम से' से अपने सफर की शुरुआत करने वाली प्रीति इस शो के साथ अपने नए सफर को लेकर कहती हैं, 'शो में मेरी पात्र वंदना उर्फ वैंडी बड़ी डींगें हांकने वाली महिला है, जो दुबई से अभी-अभी लौटी है। मैंने अभी-अभी इस शो की शूटिंग शुरू की है। शो की पूरी टीम ने मेरा स्वागत पूरे दिल से किया। वंदना विराट की जिंदगी में बहुत-सी मुश्किलें खड़ी करेंगी, क्योंकि विराट ने उनकी भांजी अमृता से जबर्दस्ती शादी कर ली थी। उम्मीद है कि दर्शकों को मेरा यह काम भी पसंद आएगा।' प्रीति इससे पहले लापतागंज, दुर्गा और चारु तथा कथा अनकही धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं।

टीवी में अपने काम को लेकर सजग हैं प्रीति। टीम स्वयं

मरने की खबर ने मुझे ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया था

इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कई बार अफवाहों का स्तर इतना नीचे चला जाता है कि बिना जांचे-परखे कलाकारों के निधन तक की भी खबरें प्रसारित होने लगती हैं। अभिनेता श्रेयस तलपड़े के बाद कुछ दिनों पहले अभिनेता देवेन भोजानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिस पर सामने आकर स्वयं देवेन को स्पष्टीकरण देना पड़ा। देवेन 27 सितंबर को डिज्नी प्लस हाटस्टार पर प्रदर्शित हो रही वेब सीरीज ताजा खबर सीजन 2 में एक बार फिर महबूब भाई की भूमिका में नजर आएंगे। अपने निधन से जुड़ी अफवाहों और मीम को लेकर वह कहते हैं, 'धारावाहिक साराभाई वर्सेस साराभाई में मेरा पात्र दुष्यंत तकनीक के मामले में काफी तेज था। करीब तीन-चार सप्ताह पहले माइक्रोसाफ्ट का सर्वर डाउन हो गया था। तब लोगों ने ऐसे काफी मीम बनाए कि अब इस समस्या का समाधान सिर्फ दुष्यंत ही कर सकता है। उसके बाद कई मीडिया हाउस ने मेरे इंटरव्यू किए। मैंने ऐसे ही एक इंटरव्यू के लिए धन्यवाद कहते हुए नमस्कार की इमोजी को एक्स पर पोस्ट कर दिया था। पहली नजर में उसमें मेरी फोटो और नमस्कार दिख रहा था। किसी ने ऐसे देखा और लिख दिया कि वह तो बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। इसके बाद ऐसे शोक संदेशों की झड़ी लग गई। जब मैंने वो देखा तो सोचा अरे यार यह क्या हो गया। फिर मैंने लिखा कि हैलो, आइ एम अलाइव (मैं जिंदा हूं)। फिर वो पोस्ट बहुत प्रसारित हो गया। उतना प्रसारित तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना अपने मरने की खबर से हो गया।'

ताजा खबर के दूसरे सीजन में भी महबूब भाई की भूमिका में नजर आएंगे देवेन ● मिडडे

दो अक्टूबर को प्रदर्शित नहीं होगी कोई बड़ी फिल्म

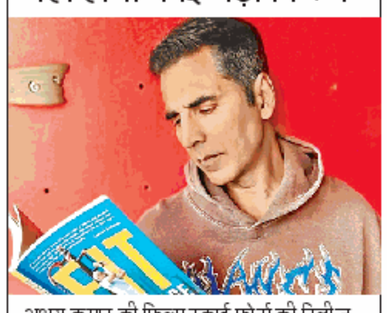

अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की रिलीज तिथि हुई स्थगित ● मिडडे आर्काइव

फिल्म निर्माता सार्वजनिक अवकाश में फिल्म को रिलीज करना फायदे का सौदा मानते हैं। आगामी दो अक्टूबर को अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म स्काई फोर्स को रिलीज करने की घोषणा भी हुई थी। हालांकि, इस साल रिलीज अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, खेल खेल में टिकट खिड़की पर कमाल नहीं दिखा पाई। खबरें थी कि इन फिल्मों के न चलने की वजह से निर्माताओं ने स्काई फोर्स की रिलीज स्थगित करने का फैसला किया। जबकि सप्ताहांत के लिए यह अच्छा मौका था। इस बाबत ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन कहते हैं, 'टिकट खिड़की का परिणाम देखते हुए निर्माताओं का आत्मविश्वास हिला हुआ है। वहीं रीरिलीज फिल्मों को देखने अच्छी संख्या में दर्शक सिनेमाघर आ रहे हैं क्योंकि टिकट 120 से 140 रुपये है। यह इस बात का संकेत है कि टिकट की कीमतों पर इस समय ध्यान देने की जरूरत है। कई बार नई फिल्मों के टिकट के दाम और बढ़ा दिए जाते हैं। अब एक फिल्म के टिकट की कीमत ढाई सौ रुपये है।'

अपनी भूमिका समझने को आदर्श ने बना डाली शार्ट फिल्म

वैसे तो अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए कलाकार कई प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, विशेषकर तब जब भूमिका किसी वास्तविक व्यक्ति से प्रेरित या उस पर आधारित हो। ऐसे में उस व्यक्ति के जीवित रहने की दशा में कलाकार उससे मिलना-जुलना और उनके बारे में समझना पसंद करते हैं। रीमा कागती निर्देशित फिल्म सुपरब्वायज आफ मालेगांव में वास्तविक फिल्मकार नासिर शेख की भूमिका निभा रहे अभिनेता आदर्श गौरव ने तो इस भूमिका को समझने के लिए पूरी शार्ट फिल्म ही बना डाली। दरअसल, फिल्म सुपरब्वायज आफ मालेगांव कम से कम संसाधनों और बहुत कम पैसों में फिल्में बनाने के लिए प्रख्यात मालेगांव की फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित है। नासिर शेख उन अग्रणी व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के साथ मालेगांव में फिल्म बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। ऐसे में उनकी जीवन के संघर्षों को समझने के लिए आदर्श ने उनके साथ रहने के साथ-साथ वैसे ही सीमित संसाधनों के साथ शार्ट फिल्म बना डाली। मैंने मालेगांव में न सिर्फ नासिर के साथ काम किया, समय बिताया, बल्कि उन्हीं सीमित संसाधनों के साथ अपनी खुद की शार्ट फिल्म बनाई। कम से कम उपकरण, छोटी टीम और लगभग बिना किसी बजट के। इन बाधाओं के साथ फिल्म निर्माण की प्रक्रिया समझने में मुझे अपनी भूमिका में जितनी अच्छी तरह से उतरने का मौका मिला, वह किसी दूसरे तरीके से संभव नहीं था।'

सुपरब्वायज आफ मालेगांव में नासिर की भूमिका में नजर आएंगे आदर्श। @gouravadarsh (इंस्टाग्राम)

सौभाग्य से, मेरे पेशे में कोई आयु सीमा नहीं है: अनुपम खेर

अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन पर अपना बायोडाटा पोस्ट करके सबका ध्यान खींचा। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हर पांच साल बाद मैं अपना बायोडाटा अपडेट करता हूं। सौभाग्य से, मेरे पेशे में कोई आयु सीमा नहीं है। अपने परिचय में उन्होंने लिखा, 'अगर जिंदगी एक फिल्म है, तो मुझे एक ब्लाकबस्टर फिल्म मिली है। शिमला के एक छोटे से शहर से लेकर अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाने तक के अपने सफर में 500 से ज्यादा फिल्में की।' उन्होंने बताया कि उनका करियर प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने, जुनून और इस अटल विश्वास का सबूत है कि असफलता सिर्फ एक घटना है, कोई इंसान नहीं। अपने अनुभवों के तहत उन्होंने शुरुआती सफर के बारे में बताया कि जेब में सिर्फ 37 रुपये और ढेर सारे सपने लेकर आया था। धैर्य और दृढ़ता की कला सीखते हुए छोटी-छोटी भूमिकाएं निभाईं। अनुपम ने अपनी पहली फिल्म सारांश के बारे में भी बताया, जिसने न केवल उनके करियर की शुरुआत की, बल्कि उनके जीवन दर्शन को भी आकार दिया।

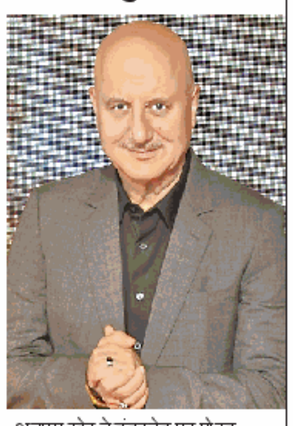

अनुपम खेर ने इंटरनेट पर पोस्ट किया बायोडाटा ● जागरण आर्काइव

****